चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

1986 से प्रकाशित | 15 मई– 21 मई 2017 | नई दिल्ली | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अब भाजपा ही कांग्रेस है

एक दार्शनिक ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य खाली रहता है, तो वह दूसरे मनुष्य की नक़ल करता है. भाजपा यही कर रही है. भाजपा ने अपने तीन वर्ष के शासनकाल में ऐसा क्या किया है, जो कांग्रेस के दस साल के काम से अलग है? दरअसल, भाजपा कांग्रेस की नक़ल के मामले में कांग्रेस को ही पीछे छोड़ रही है. चाहे मनरेगा हो या आधार. भाजपा के पास नई योजनाएं कहां हैं? ये सारी योजनाएं जनसंघ की वास्तविक योजनाएं नहीं हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक सोच है?

कमल मोरारका

पिछले कुछ महीनों में देश का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, देश के अधिकतर राज्यों में भाजपा का शासन स्थापित हुआ है. भाजपा मजबूत हुई है. दिल्ली नगर निगम चुनाव के नतीजों ने इस दावे को अतिरिक्त मजबूती प्रदान की है. भाजपा के लोगों, उसके समर्थकों और वोटर्स में यह धारणा बनी है कि देश ने भाजपा को अपना रहनुमा स्वीकार कर लिया है. यहां यह जानना दिलचस्प होगा कि उत्तर प्रदेश में पिछले दो चुनावों से भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही थी. इस चुनाव में यह मुद्दा तकरीबन नहीं के बराबर था. उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था. इस चुनाव में विकास, रोज़गार, सबका साथ सबका विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर को मुद्दा बनाया गया था. ज़ाहिर है, रोज़गार का अवसर युवाओं को आकर्षित करता है. भारत ने 1947 से लेकर आज तक शानदार तरक्की की है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि के कारण बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है. लिहाज़ा कोई भी दल, चाहे वो जिस दृष्टिकोण का हो, जबतक रोज़गार उपलब्ध कराने और क्रयशक्ति बढ़ाने का वादा नहीं करता, युवा उसकी ओर आकर्षित नहीं होते.

क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक सोच है

भाजपा की जीत को लेकर संघ परिवार के लोग दावा कर रहे हैं कि ये संघ के दृष्टिकोण की जीत है. ज़ाहिर है, किसी मुद्दे पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए हर शख्स स्वतन्त्र है. यहां मैं यह साफ़ कर दूं कि कांग्रेस से मेरा कोई लेना–देना नहीं है. दस वर्षों के अपने कार्यकाल में कांग्रेस ने अनेक गलतियां की हैं, जो उसकी पराजय का कारण बनीं. पिछले दिनों भाजपा से जुड़े एक मित्र से बातचीत हुई. उनका कहना था कि नरेंद्र मोदी आज देश के एकमात्र सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं. किसी भी दल में ऐसा कोई नेता नहीं, जो उनके करिश्मा, उनकी भाषण शैली और उनकी लोकप्रियता का मुकाबला कर सके. दूसरी बात यह कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के कई आरोप हैं, जबकि भाजपा के तीन वर्षों के शासनकाल में भ्रष्टाचार का कोई बड़ा मामला उजागर नहीं हुआ है. मैं उनकी बातों से सहमत हूं, लेकिन एक संशोधन के साथ. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद लाइसेंस के बदले पैसा लेने के अवसर समाप्त हो गए थे. किसी भी राजनैतिक दल को चुनाव लड़ने और सत्ता में बने रहने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है. कांग्रेस ने आर्थिक संसाधनों, चाहे वो कोयला हो या स्पेक्ट्रम आवंटन, को पैसे इकट्ठे करने के नए उपाए के तौर पर अपनाया. सुप्रीम कोर्ट ने 2जी और कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर दिया. यह सही है कि भाजपा पर अभी तक किसी बड़े घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि कोल ब्लॉक आवंटन और 2जी लाइसेंस के बदले पैसा उगाही की संभावना खत्म हो गई है. सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इनका आवंटन अब बोली लगाकर की जाए. जबतक भाजपा पैसे की उगाही का कोई नया तरीका नहीं ढूंढ लेती, तब तक उस पर किसी बड़े घोटाले का आरोप नहीं लग सकता. लिहाज़ा भाजपा के शासन में कोई बड़ा घोटाला नहीं हुआ है, इस दावे को स्वीकार कर लेने में भी कोई हर्ज़ नहीं है.

अब सरकार से जुड़े सकारात्मक पक्ष की तरफ लौटते हैं. भाजपा ने अपने तीन वर्ष के शासनकाल में ऐसा क्या किया है, जो कांग्रेस के दस साल के काम से अलग है? अब तक कोई भी ऐसी योजना नहीं दिखी है, जिसे भाजपा ने शुरू किया हो और जो देश में पिछले 70 साल से होता आ रहा हो, उससे अलग हो. दरअसल, भाजपा कांग्रेस की नक़ल के मामले में कांग्रेस को ही पीछे छोड़ रही है. मिसाल के तौर पर, प्रधानमंत्री ने संसद में स्वयं कहा कि मैं मनरेगा को समाप्त नहीं करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि यह किस तरह का घपला था. फिलहाल, गरीबी उन्मूलन के लिए वे मनरेगा पर भरोसा कर रहे हैं और उसे प्रोत्साहित भी कर रहे हैं. उसी तरह, आधार कार्ड का मामला है. जब तक भाजपा विपक्ष में थी, आधार की आलोचना करती रही, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा आधार को हर एक चीज़ का आधार बना देना चाहती है. इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर भी शामिल है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर चिदंबरम के दिमाग की उपज थी. भाजपा के पास नई योजनाएं कहां हैं? जो योजनाएं हैं, उनका श्रेय या तो चिदंबरम को जाता है या सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी काउंसिल को. ये सारी योजनाएं जनसंघ की वास्तविक योजनाएं नहीं हैं. बहरहाल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे पास कोई वैकल्पिक सोच है?

एकदलीय बनाम बहुदलीय बनाम द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था

क्या हमारे यहां द्विदलीय राजनीतिक व्यवस्था ही सही है? दरअसल द्विदलीय व्यवस्था की संभावना है, क्योंकि भाजपा अपने दम पर सत्ता में आई है. लेकिन इस सम्भावना को भी नकारा जा रहा है, क्योंकि मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत का वादा किया है. यानि, वे दूसरी पार्टी नहीं चाहते हैं. वे एकदलीय शासन व्यवस्था चाहते हैं. एकदलीय व्यवस्था लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है. यदि कांग्रेस ख़राब है तो उसी तरह भाजपा भी ख़राब है. उसमें भी सत्ता का अहंकार आ गया है. उसने भी नियम तोड़ने शुरू कर दिए हैं. राज्यपाल केंद्र से डरने लगे हैं. यदि क्रिकेट की भाषा में कहें तो कोई भी अपने क्रीज़ में रह कर बैटिंग नहीं कर रहा है. दुर्भाग्यवश एक दूसरा खतरा यह है कि पिछले 20–30 वर्षों में प्रेस का स्तर बहुत नीचे गिरा है. 1977 तक देश में एक जीवंत प्रेस था, जो इंदिरा गांधी के आपातकाल को भी झेल गया था, लेकिन आज प्रेस पूरी तरह से घुटनों के बल आ गया है. उसे खरीदा जा सकता है और प्रभावित किया जा सकता है. प्रेस में आज सरकारी पक्ष के अलावा कोई अन्य पक्ष पेश नहीं किया जाता. ■

मौजूदा सरकार कांग्रेस प्लस गाय

यह सही है कि 70 साल के बाद नेतृत्व बदला है. आरएसएस की सोच सत्ता में आई है. तो क्या आरएसएस उस सोच का एक छोटा सा हिस्सा भी लागू कर पाई है? सुषमा स्वराज ने जोश में कह दिया कि भगवद्गीता को भारत का पवित्र ग्रन्थ घोषित कर देना चाहिए. प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि देश में केवल एक राष्ट्रीय किताब है और वो है भारत का संविधान. संघ परिवार कई प्रो–हिन्दू या प्रो–हिंदुत्व योजनाएं लागू करवाना चाहता है. गाय एक बड़ा मुद्दा है. भाजपा के एक पुराने नेता अरुण शौरी ने दो साल पहले कहा भी था कि मौजूदा सरकार, कांग्रेस प्लस गाय सरकार है.

अब गाय का मुद्दा ही देखिए. गाय को लेकर एक थिंक टैंक होना चाहिए. इस पर बहस होनी चाहिए. एक नीति होनी चाहिए, जो कहीं दिखाई नहीं देती है. गाय के नाम पर किसी के ऊपर कीचड़ उछालना, बीफ खाने का आरोप लगा कर किसी की हत्या कर देना राष्ट्रीय नीति नहीं है. यह लचर रवैया है. यह मुसलमानों में डर की भावना पैदा करना है. लोगों ने लोक सभा में 281 सीटें देकर नरेंद्र मोदी में अपना भरोसा जताया था. अभी नरेंद्र मोदी के पास दिखाने के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है! कोई भी एक अनोखी योजना नहीं है जो कांग्रेस से अलग हो. इस देश में ऐसे लोगों की एक बड़ी संख्या है जो गाय को पूजते हैं. लेकिन आप देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जाएंगे तो वहां बीफ लोगों का मुख्य भोजन है. गोवा, जहां भाजपा सत्ता में है, लोग गोमांस खाते हैं. सवाल है कि नीति आयोग क्या कर रहा है? फिलहाल उसे इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति बनाने की ज़रूरत है. यह कहा जा सकता है कि आज देश में जो सरकार है, वो कांग्रेस का विकल्प नहीं, बल्कि कांग्रेस का स्थान लेने वाली सरकार है. एक आदमी गया, उसकी जगह दूसरा आ गया. कागज़ी कार्यवाही वैसी ही है, नौकरशाही वही है, कार्यप्रणाली वैसी ही है.

ये नई शैली की राजनीति नहीं है

सवाल है कि क्या इस देश में अलग तरह की शासन व्यवस्था की सम्भावना है? यह बेहतर होगा यदि भाजपा ये मान ले कि हमारे पास संख्या बल तो है, लेकिन हम कुछ नया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संविधान हमारे सामने है. स्वतंत्रता संग्राम के मूल्य संविधान में शामिल हैं. पहले की सरकारों से अलग, कोई भी प्रधानमंत्री पांच से दस प्रतिशत से अधिक अलग कुछ भी नहीं कर सकता है. समस्याएं एक जैसी हैं, समाधान भी एक जैसे हैं. कोई क्रान्तिकारी बदलाव केवल तानाशाही में ही मुमकिन है. भाजपा को राजनीति के नए प्रतिमान स्थापित करने चाहिए. मिसाल के तौर पर, गोवा में भाजपा को ये घोषणा करनी चाहिए थी कि कांग्रेस ने 17 सीटें जीती हैं और हमने 13 सीटें जीती हैं, इसलिए हम विपक्ष में बैठेंगे. ये राज्यपाल का सिरदर्द है कि वो कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं. ये होती नई शैली की राजनीति.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

लाल हो रही काली ज़मीन | P-3

जो कमज़ोर है लुटेगा वही टिकेगा जो बिकेगा | P-4

कश्मीर में इंटरनेट बंद करने के उल्टे परिणाम | P-5

अब भाजपा ही कांग्रेस है

पृष्ठ 1 का शेष

लेकिन भाजपा ने वही किया जो कांग्रेस किया करती थी. गोवा से बदतर उदाहरण मणिपुर का था. भाजपा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेसी संस्कृति को दोहरा रही है. नजमा हेपतुल्ला और मुदुला सिन्हा इन दोनों राज्यों में भाजपा नियुक्त राज्यपाल हैं. वहां सरकार बनाना कानून के मुताबिक है, संविधान सम्मत है. लिहाज़ा, मैं इसमें कोई गलती नहीं देखता. लेकिन, यह नई शैली की राजनीति नहीं है. उत्तराखंड में भाजपा ने कांग्रेसियों को पार्टी में शामिल कर चुनाव लड़ा और सरकार बना ली. सवाल है कि उन्हीं पुराने चेहरों के साथ भाजपा नई सरकार, नई शासन व्यवस्था कैसे दे सकती है? जो काम कांग्रेस ने 1952 से 1967 के दौरान किया, वही काम अब भाजपा कर रही है. इन शुरुआती 15 वर्षों में हर जगह कांग्रेस ही कांग्रेस थी. जब 1967 के बाद लालबहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू नहीं रहे तो पहली बार 1967 में संयुक्त विधायक दल या इस तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार में आई. चौधरी चरण सिंह, गोविन्द नारायण सिंह और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने. लेकिन इनकी अवधि बहुत छोटी थी. सवाल है कि कांग्रेस के जो लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, क्या वे जनसंघ की मानसिकता को भी अपना लेंगे? मैं यह ज़रूर कह सकता हूं कि वे उस तरह से अनुशासित नहीं किए जा सकते, जिस अनुशासन के संघ के लोग आदि हैं. हालांकि, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन देखते हैं कि उत्तराखंड की सरकार कैसे काम करती है, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसे काम करती है? लेकिन भाजपा की दूसरी सरकारों की स्थिति भी बहुत अलग नहीं है. गुजरात में एक लम्बे समय से उनकी सरकार है, वहां तो ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? वहां शिव सेना है. वहां अहंकार इतना अधिक है कि भाजपा, शिव सेना के साथ समन्वय नहीं बिठा पा रही है.

कश्मीर पर भाजपा क्या सोचती है

ये मान लेते हैं कि गरीबी है, बेरोज़गारी है, एक दिन में औद्योगीकरण नहीं किया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास धीरे धीरे होता है. लेकिन, कश्मीर जैसे बड़े मुद्दों पर भाजपा क्या कर रही है? कश्मीर पर सिवाय यह कहने के कि नेहरू ने वहां गलती की, भाजपा ने क्या किया? बेशक, नेहरू ने वहां गलती की, क्योंकि वे भगवान नहीं थे. उस गलती की जिम्मेदारी मौजूदा सरकारों की है. समस्या का समाधान करना है. क्या भाजपा ने कश्मीर को लेकर एक भी ऐसा काम किया है जो कांग्रेस से अलग है? कुछ भी नहीं! अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह ने पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत की और समस्या का समाधान तलाश करने की कोशिश की. भाजपा ये काम भी नहीं कर रही है. मोदी के मौजूदा रुख से यह लगता है कि वे कश्मीर समस्या का समाधान सुरक्षा बलों की सहायता से करवाना चाहते हैं. अगर सुरक्षाबलों के हाथों सभी समस्याओं का समाधान मुमकिन होता तो आज पाकिस्तान एक बहुत ही समृद्ध देश होता. कश्मीर एक संवेदनशील मुद्दा है. भाजपा हमेशा सरदार पटेल का गुणगान करती है. सरदार पटेल कश्मीर मामले में स्पष्ट थे. उनका मानना था कि कश्मीर मुस्लिम बहुल राज्य है, लिहाज़ा उसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए. यह हकीकत है कि नेहरू को कश्मीर से लगाव था, क्योंकि वे एक कश्मीरी पंडित थे. यदि नेहरू से गलती हुई और भाजपा अगर समस्या का समाधान सरदार पटेल की सोच के मुताबिक करना चाहती है, तो यह मसला कल ही हल हो जाएगा.

भाजपा को बताना चाहिए कि कश्मीर पर उसका नजरिया पहले की सरकारों से कैसे अलग है? क्या आरएसएस यह बोल सकता है कि कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाए? नहीं. मुशर्रफ जब भारत आए थे तो उन्होंने कहा था कि कश्मीर विभाजन का एक अपूर्ण एजेंडा है. कई लोगों ने भाजपा को यह सुझाव दिया था कि उन्हें उनके ही जाल में फंसाया जाए. उनसे कहा जाए कि यदि वे सोचते हैं कि विभाजन अपूर्ण एजेंडे का हिस्सा है तो विभाजन के बाद जो मुसलमान यहां रह गए थे वे भी उसी अपूर्ण एजेंडे का हिस्सा हैं. आखिरकार देश का विभाजन दो राष्ट्र के सिद्धांत पर हुआ था. कांग्रेस ने दो राष्ट्र के सिद्धांत को निरस्त कर दिया था. आरएसएस को मुशर्रफ से यह कहने से कोई नहीं रोक रहा था कि आइए दो राष्ट्र के सिद्धांत को मान लेते हैं. एक मुस्लिम राष्ट्र होगा, एक हिन्दू राष्ट्र होगा. लेकिन इस तरह का एक भी साहसी बयान न तो आरएसएस की तरफ से आया और न ही विश्व हिन्दू परिषद की तरफ से. उनका एकमात्र खेल यह है कि नेहरू को दोष दो, कांग्रेस को दोष दो, मुसलमानों पर दबाव बनाओ. फ़िलहाल हमें इस मुद्दे पर नई सोच की ज़रूरत है, लीक से हटकर सोचने की ज़रूरत है. यदि भाजपा कांग्रेस की पैरवी कर रही है, तो उसे पाकिस्तान के साथ बातचीत की शुरुआत कर देनी चाहिए. बातचीत नहीं रुकनी चाहिए, भले ही उसे कुछ हासिल हो या न हो. यह बातचीत द्विपक्षीय हो और बिना किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी के हो. लेकिन, जैसे ही पठानकोट की तरह कोई आतंकी कार्रवाई होती है तो भाजपा कहती है कि हम बातचीत नहीं करेंगे. फिर समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? पठानकोट नवाज़ शरीफ ने नहीं किया था. जिसने भी यह काम किया, उसका यह मकसद था कि बातचीत की प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न की जाए और सरकार उस जाल में फंस जाती है, जबकि सरकार को कहना चाहिए था कि बातचीत जारी रहेगी.

संघ, मोदी और बापू

नए विचारों को अपनाने की आवश्यकता है. यदि भाजपा को लगता है कि कांग्रेस का रुख सही है, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है. 1947 से 2014 (जब मोदी ने सत्ता संभाली) के दौरान भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दुनिया के किसी भी देश की तुलना में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया है. 1947 और आज के आंकड़ों की तुलना कीजिए, तो चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य या इन्फ्रास्ट्रक्चर हो, दुनिया का कोई भी देश लोकतांत्रिक ढंग से ये उपलब्धि हासिल नहीं कर पाया है. चीन की मिसाल दी जा सकती है, लेकिन वहां लोकतंत्र नहीं है. कोई भी देश यह दावा नहीं कर सकता कि एक व्यक्ति एक वोट, पूर्ण साक्षरता का अभाव, अन्धविश्वास और धर्मान्धता के बावजूद हमने इतनी दूरी तय की है. चुनाव के दौरान कांग्रेस को भला-बुरा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कम से कम चुनाव के बाद तो सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए. सच्चाई यह है कि कांग्रेस ने बेहतर काम किया है. कुछ लोग घोटालों में भी शामिल रहे हैं, लेकिन उनके लिए कानून है. सरकार कार्रवाई कर सकती है. सवाल यह है कि भारत की केवल एक प्रतिशत आबादी कश्मीर में रहती है. मौजूदा सरकार उस आबादी का दिल जीतना चाहती है या केवल वहां की ज़मीन चाहिए. भारत एक विस्तारवादी शक्ति नहीं है. हम किसी देश पर क़ब्ज़ा जमाना नहीं चाहते. दिक्कत ये है कि भाजपा कांग्रेस का विकल्प तो है, लेकिन उसके पास वैकल्पिक नीति नहीं है. वैकल्पिक नीति तलाशने में मोदी सक्षम हैं. मोदी कह सकते हैं कि अब मैं सत्ता में हूं और संघ परिवार की सोच को लागू करूंगा.

आरएसएस ने गांधी जी को कभी भी राष्ट्रपिता के रूप में स्वीकार नहीं किया है. वे कहते हैं कि राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता. लेकिन मोदी होशियार हैं. वे जानते हैं कि रामायण और महाभारत की तरह गांधी भारतीयों के खून में शामिल हैं. सत्ता संभालने के पहले दिन से ही उन्होंने बापू, स्वच्छ भारत और गांधी से जुड़ी चीज़ों को उजागर करना शुरू कर दिया था. गांधी पर मोदी के इस रुख को स्वीकार करने के लिए आरएसएस तैयार नहीं है. यदि सरकार लोगों की यादाश्त से गांधी और नेहरू को निकालने में सफल होती है तो आरएसएस को इस बात से ख़ुशी होगी. लेकिन ऐसा करने के लिए भाजपा को अलग तरह की राजनीति करनी पड़ेगी. फ़िलहाल उसके पास करने को कुछ भी नहीं है. एक दार्शनिक ने कहा था कि यदि कोई मनुष्य खाली रहता है तो वह दूसरे मनुष्य की नक़ल करता है. भाजपा यही कर रही है.

दबाव की राजनीति!

अच्छा ये होगा कि विकास प्रक्रिया जारी रखी जाए, बुरा यह कि सीबीआई को नियंत्रित किया जाए, आईबी को नियंत्रित किया जाए और सबको ब्लैकमेल किया जाए. मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपने काम से खुश होना चाहिए कि किसी अन्य दल के पास उससे अलग विचार नहीं हैं. जो लोग कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं हैं, जो आम राजनैतिक विश्लेषक हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि हम अभी बहुत मुश्किल स्थिति में फंसे हुए हैं. यदि शासन व्यवस्था में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य शामिल नहीं होता, नैतिकता नहीं होती तो भारत एक बनाना रिपब्लिक बन गया होता.

अब कोई मुख्यमंत्री (अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री) ख़ुदकुशी कर ले और 60 पन्नों का नोट छोड़ जाए, तो उस नोट में क्या लिखा है, उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए. यह देखना चाहिए कि उस मुख्यमंत्री ने क्या कहा. वो एक मरने वाले व्यक्ति की अंतिम घोषणा है, जो किसी भी अदालत में साक्ष्य के तौर पर पेश की जा सकती है. भले ही उसमें मोदी का नाम नहीं हो, सोनिया गांधी का नाम हो. लेकिन एक बार फिर भाजपा ने कांग्रेस का तरीका अपनाया है कि ऐसी चीज़ों को लोगों को डराने के लिए इस्तेमाल किया जाए. कथित तौर पर उस नोट में जस्टिस खेहर के बेटे का नाम शामिल है और इस तरह से शामिल है कि जस्टिस खेहर कमज़ोर हो जाएं. यदि वाकई उनके बेटे का नाम उसमें शामिल है और उसकी जानकारी उन्हें है, तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट और सरकारी एजेंसियों को इस दबाव से बचाना चाहिए. आपातकाल के दौरान सरकार ने ऐसा किया था. एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाकर गलत फैसला दिलवाया गया. ये फैसला सिविल लिबर्टी के खिलाफ था. 4-1 के बहुमत से ये फैसला आया था. पांच जजों की बेंच में केवल जस्टिस एचआर खन्ना ने झुकने से इनकार किया था. जस्टिस चंद्रचूड़, जो उस बेंच में शामिल थे, ने आपातकाल के बाद यह स्वीकार किया था कि उन्हें खेद है कि वे इस गलत फैसले में शामिल रहे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना साहस नहीं जुटा पाया कि वो सही फैसला दे. आज हालत उसी दिशा में जा रहे हैं. आम आदमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसका पक्ष क्या है? वो यह कहता है कि कल कांग्रेस करती थी आज भाजपा कर रही है, उन्हें करने दें. लिहाज़ा आम आदमी इससे प्रभावित नहीं होता. वो महंगाई, कृषि क्षेत्र से जुड़े मामलों और रोज़गार से प्रभावित होता है. अमित शाह की तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने इस खेल को अच्छी तरह से समझा है. उनका मानना है कि बड़ी-बड़ी बातों से कुछ नहीं होता, उनका काम है चुनाव जीतना. चुनाव कैसे जीतना, शायद कांग्रेस जो दांव चलती थी, उससे दो-तीन दांव अधिक चल कर. ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके. अब यह पैसा कहां से आएगा? निश्चित रूप से अमीरों के यहां से आएगा. एक-दो नीतियों में यहां-वहां बदलाव करो और पैसा हासिल करो. मीडिया को बहुत सारा पैसा दो ताकि वहां से कोई विरोध ना हो.

यहां यह ज़रूर समझना चाहिए कि जनता भाजपा को वोट नहीं कर रही है. वह उस पार्टी को वोट कर रही है, जो चुनाव लड़ रही है. उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है. कांग्रेस पार्टी एक तरह से अनुपस्थित है. भाजपा वैसे ही जीत रही है, जैसे कभी कांग्रेस जीता करती थी. लोकतंत्र स्थापित होने के पहले 20 वर्षों तक कोई अन्य पार्टी महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं थी. सोशलिस्ट कमज़ोर थे, कम्युनिस्ट छोटे इलाकों तक सीमित थे और जनसंघ लगभग थी ही नहीं. दरअसल आपातकाल के बाद जनता पार्टी ने सत्ता पर क़ब्ज़ा किया लेकिन वो बहुत दिनों तक नहीं चल सकी, क्योंकि उसमें विचारधारा का टकराव था. आज दो चीज़ें तलाशने की आवश्यकता है. पहली यह कि भाजपा की नीयत और नीति क्या है? यदि भाजपा की नीति और नीयत, कांग्रेस की ही नीति और नीयत है, तो यह समझना चाहिए कि यह भाजपा की सरकार नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार एक नए नाम के साथ सत्ता में है. यदि भाजपा का मुद्दा गाय, मंदिर है तो फिर भाजपा का स्टैंड अलग होना चाहिए. यह भाजपा के लिए ज़रूरी है कि वे जनता को ये बताएं कि उनकी राष्ट्रीय नीति क्या है या ये कहें कि उनकी राष्ट्रीय नीति वही है जो संविधान कहता है. भाजपा देश के लोगों से कहे कि एक संविधान सम्मत सरकार चलाने की कांग्रेस ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की. कांग्रेस नहीं चला सकी, लेकिन हम चलाएंगे. भाजपा ये बताए कि हम भ्रष्टाचार मुक्त रहने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और साथ ही लोगों को यह भी बताए कि (काम करने की) अधिकतम सम्भावना इतनी ही है. देश के लिए, भाजपा को ये काम तो जरूर ही करना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 09 अंक 11
15 मई- 21 मई 2017

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-65500786, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16++ (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

कोयलांचल में जारी है वर्चस्व की कभी न ख़त्म होने वाली जंग

लाल हो रही काली ज़मीन

कोयले की काली कमाई की चमक से सभी लोग आकर्षित होते हैं और जल्दी कमाने की होड़ में अपना गैंग बनाने में जुट जाते हैं. नए लोग बंद पड़े खदानों से अवैध उत्खनन कर करोड़ों की कमाई करते हैं और संरक्षण देने वाले अपने आकाओं को एक बड़ी राशि रंगदारी के रूप में देते हैं. ये छोटे गैंग स्थानीय लोगों से बंद पड़े खदानों से कोयला निकलवाते हैं और प्रति टन 600 रुपए उन्हें देते हैं, जबकि बाजार में इसी कोयले को 7000 रुपए में बेचते हैं.

प्रशान्त शरण

कोयले की अवैध काली कमाई पर वर्चस्व को लेकर झारखंड के कोयलांचल में हत्याओं का दौर लगातार जारी है. कोयलांचल में आठ बड़े गैंग में चार सौ करोड़ रुपए से भी अधिक की रंगदारी को लेकर खूनी खेल चलता रहता है. 29 साल में 340 से भी ज्यादा लोगों की हत्याएं माफियाओं ने कर दी, जबकि छोटे-छोटे प्यादे तो लगभग रोज ही मारे जाते हैं. कोयलांचल में 40 वैध खदानें हैं, जबकि इससे कहीं अधिक अवैध खनन. इन वैध खदानों से लगभग 1.50 लाख टन कोयले का उत्पादन होता है, जबकि इस उत्पादन में लोडिंग, अनलोडिंग और तस्करी में लगभग 400 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूली माफिया के गुर्गे करते हैं. वैसे पिछले 57 साल से कोयलांचल में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन पिछले 29 सालों से इस लड़ाई ने हिंसक रूप ले लिया है. 29 साल में कोयलांचल में वर्चस्व को लेकर साढ़े तीन सौ से भी ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं. उसके बाद भी हर रोज एक छोटा गैंग उभरकर सामने आ जाता है. लेकिन कोयलांचल में अभी भी सिंह मेंशन का ही दबदबा है. अब फर्क सिर्फ ये हो गया है कि सिंह मेंशन में भी बंटवारा हो गया और चारों भाईयों एवं उनके बेटों का अलग गैंग हो गया है. इतनी हत्याओं के बाद भी कोयले की अवैध काली कमाई से लोगों का मोहभंग नहीं हो पा रहा है. अब तो गोरखपुर के भी माफिया डॉन कोयलांचल के माफियाओं के साथ मिलकर इस अवैध काली कमाई में लग गए हैं.

धनबाद में हाल ही में हुई उप महापौर नीरज सिंह की हत्या ने कोयलांचल में एक बार फिर बदले की आग को भड़का दिया है. नीरज सिंह सहित चार लोगों को 21 मार्च की शाम गोलियों से भून दिया गया था. नीरज की हत्या का आरोप उनके ही चचेरे भाई एवं सूरजदेव सिंह के बेटे संजीव सिंह पर लगा. संजीव अभी झरिया से भाजपा के विधायक हैं. पुलिस ने हत्या के आरोप में संजीव सिंह को गिरफ्तार किया है. वैसे संजीव इस हत्या के आरोपों से इंकार करते हुए कहते हैं, भला मैं अपने चचेरे भाई की हत्या क्यों करूंगा. इस हत्या को सिंह मेंशन के करीबी रहे रंजय सिंह की हत्या से जोड़कर देखा जा रहा है. नीरज के बाद उनके भाई एकलव्य सिंह एक बड़ा चेहरा हैं. अभी वे धनबाद नगर निगम के उपमहापौर हैं. सूरजदेव सिंह के छोटे बेटे संजीव सिंह हमेशा 25 अंगरक्षकों से घिरे रहते हैं. वे झरिया से भाजपा के विधायक हैं. कई कोलियरी पर इनका कब्जा है. सूरजदेव सिंह के एक अन्य भाई सकलदेव सिंह की हत्या के बाद उनके बेटे रणविजय सिंह ने कतरास के इलाके में अपना कब्जा जमा रखा है. ये भी 23 एक्स आर्मी मैन के जत्थे वाला सुरक्षा घेरा लेकर चलते हैं. इनके घर की भी मजबूत किलेबंदी है.

दरअसल, पिछले कुछ सालों में माफियाओं ने युनियन की आड़ में कोयलांचल में अपना वर्चस्व कायम कर लिया है. इन वर्षों में अगर सबसे ज्यादा मार किसी पर पड़ी, तो वे मजदूर हैं. करीब साढ़े तीन सौ से भी ज्यादा हत्याएं हुईं, कई की तो लाशें भी नहीं मिलीं. उन्हें बेदर्दी से जलती आग में फेंक दिया गया. कई हाई प्रोफाईल हत्याएं भी हुईं. आपसी जंग में माफियाओं ने एक-दूसरे का खूब खून बहाया. आज कोयलांचल में लगभग आठ बड़े गैंग हैं, जबकि सैकड़ों छोटे गैंग. वैसे, माफिया शब्द का पहली बार सरकारी भाषा में इस्तेमाल 1988 में हुआ था. बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद ने पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया. समय के साथ चेहरे बदलते गए. कोयले की काली धरती खून से लाल होती गई, लेकिन कोयलांचल की तकदीर नहीं बदली.

कोयलांचल में हत्या कोई नई बात नहीं है

झारखंड में कोयले की काली कमाई में वर्चस्व को लेकर खून से धरती लाल होती रहती है, लेकिन सरकार एवं पुलिस इसे रोकने में पूरी तरह से असफल है. कोयले की अवैध कमाई में राजनेताओं के साथ ही पुलिस-अधिकारी गठजोड़ को भी भारी-भरकम राशि मिलती है. बिहार, झारखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के भी कुख्यात अपराधी यहां अपना वर्चस्व कायम करने के लिए हिंसक वारदातों को अंजाम देते रहते हैं. अभी हाल के दिनों में वर्चस्व को लेकर भोला पाण्डेय, सुरेश सिंह, राजीव रंजन सिंह, अमरेन्द्र तिवारी, सुशील श्रीवास्तव, नीरज सिंह की फिल्मी अंदाज में हत्याएं कर दी गई. कोयले में वर्चस्व को लेकर हर साल पचास से भी ज्यादा जानें जाती हैं. पांच सौ करोड़ प्रतिवर्ष की अवैध कोयले की कमाई में वर्चस्व को लेकर हिंसा-प्रतिहिंसा का दौर कब तक जारी रहेगा, इस पर पुलिस का कब शिकंजा कसेगा, ये बताना आसान नहीं है.

1976 में श्रमिक नेता एवं माफिया के रूप में उभरे बी.पी. सिन्हा की हत्या कर सुरजदेव सिंह कोयलांचल में वर्चस्व कायम करने में पूरी तरह से सफल रहे और इनका एकछत्र राज कोयलांचल में कायम हो गया. इसके बाद अवैध कमाई का गवाह इनका निवास सिंह मेंशन बना. सूरजदेव सिंह के परिवार में वर्चस्व को लेकर खूनी जंग छिड़ी हुई है. इसमें इस परिवार के ही आधा दर्जन से अधिक लोग की हत्याएं हो चुकी है. अभी नीरज सिंह समेत चार लोगों की दिन-दहाड़े हुई हत्या ने धनबाद की पुरानी हत्याओं की यादें ताजा करा दी है. नीरज को 40 से अधिक गोलियां मारी गईं. इससे पहले भी विनोद सिंह को इसी अंदाज में गोली मारी गई थी. सिंह मेंशन के करीबी माने जाने वाले रंजय सिंह की हत्या भी इसी साल जनवरी में अपराधियों ने कर दी थी. रंजय सिंह की हत्या के प्रतिशोध के कारण ही नीरज सिंह की हत्या हुई. पुलिस भी इसी प्रतिशोध को कारण मान रही है. इस हत्या के पीछे सिंह मेंशन का नाम आ रहा है.

26 मई, 1996 को नीरज सिंह के मौसा संजय सिंह की हत्या के बाद दोनों परिवारों के बीच खटास पैदा हो गई और इसके बाद दरार धीरे-धीरे बढ़ता ही चला गया. पहले इस हत्याकांड में सुरेश सिंह पर आरोप लगा, लेकिन बाद में सूरजदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह और रामाधीर सिंह को हत्या का अभियुक्त बनाया गया. इसके प्रतिशोध में राजीव रंजन सिंह एवं सुरेश सिंह की भी हत्या फिल्मी अंदाज में शार्प शूटरों ने कर दी. सिंह मेंशन हमेशा सुर्खियों में रहा और कोयला कारोबार से लेकर राजनीति तक इस परिवार का दबदबा रहा. सिंह मेंशन के सूरजदेव सिंह कई बार धनबाद से विधायक चुने गए. उनकी पत्नी कुंति सिंह भी झरिया से विधायक रहीं. अभी उनका पुत्र संजीव सिंह झरिया से भाजपा का विधायक है. सियासत में इनके मजबूत दखल का प्रमाण ये भी है कि धनबाद नगर निगम की कुर्सी इन्हीं परिवारों के बीच रही है. धीरे-धीरे नीरज सिंह भी राजनीति में तेजी से उभरने लगा. पिछले विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के टिकट पर झरिया से उमीदवार था, जबकि उसके चचेरे भाई संजीव सिंह भाजपा के टिकट पर. जीत संजीव की हुई. इससे परिवार के बीच विवाद और खुलकर सामने आ गया. नीरज सिंह 2019 के लोकसभा चुनाव में खड़ा होने वाला था. लेकिन नीरज की हत्या करा दी गई. माना जा रहा है कि कोयले की लोडिंग प्वाईट पर आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कब्जे को लेकर हत्या हुई. आउटसोर्सिंग पर वर्चस्व के लिए बात-बात पर खून की होली खेली जाती है. आउटसोर्सिंग से इन माफियाओं को भारी कमाई होती है. आउटसोर्सिंग कम्पनियां कमीशन के रूप में करोड़ों रुपए माफिया को देती हैं और इसके बदले माफियाओं द्वारा इनको सुरक्षा प्रदान की जाती है. कोयले और सियासत में नीरज सिंह की सक्रियता से कई दुश्मन बन गए थे. नीरज उस परिवार से था, जो कोयला और झरिया की राजनीति में सबसे ज्यादा सफल रहा. इस वर्चस्व को लेकर ही दोनों परिवारों के बीच अदावत थी. इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कोयलांचल में सूरजदेव सिंह की तूती बोलती थी. सूरजदेव सिंह का सम्पर्क पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर से था.

अब धनबाद में गैंगवार पारिवारिक युद्ध में बदल गया है. परिवार के बीच चल रहे इस युद्ध में दोनों ही परिवार के पंद्रह लोगों की हत्या हो चुकी है. नीरज सिंह की हत्या के बाद अब इसके और बढ़ने की संभावना प्रबल हो गई है और इस कारण सिंह मेंशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. नीरज सिंह की हत्या बाइक पर सवार चार अपराधियों ने गोली मारकर कर दी. लगभग डेढ़ सौ राउंड गोली चली और इसमें नीरज के साथ उनका पीए अशोक यादव, निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी और ड्राइवर घोलट मारे गए. जहां पर नीरज सिंह की हत्या हुई, उसके पास ही संजीव सिंह का आवास सिंह मेंशन है. इस हत्या में नीरज सिंह के चचेरे भाई संजीव सिंह को ही मुख्य अभियुक्त बनाया गया है. इससे दो माह पूर्व ही संजीव के करीबी माने जाने वाले रंजय की हत्या अपराधियों ने कर दी थी.

कोयले की काली कमाई की चमक से सभी लोग आकर्षित होते हैं और जल्दी कमाने की होड़ में अपना गैंग बनाने में जुट जाते हैं. नए लोग बंद पड़े खदानों से अवैध उत्खनन कर करोड़ों की कमाई करते हैं और संरक्षण देने वाले अपने आकाओं को एक बड़ी राशि रंगदारी के रूप में देते हैं. ये छोटे गैंग स्थानीय लोगों से बंद पड़े खदानों से कोयला निकलवाते हैं और प्रति टन 600 रुपए उन्हें देते हैं, जबकि बाजार में इसी कोयले को 7000 रुपए में बेचते हैं. कोयले की तस्करी बनारस एवं उत्तर प्रदेश के अन्य मंडियों में होती है. राजनेता, पुलिस एवं पत्रकारों की गठजोड़ से कोयले की तस्करी कराई जाती है. पुलिस-अधिकारियों की भूमिका इसमें अत्यन्त अहम होती है. पुलिस-अधिकारियों को भी कोयला तस्कर नजराने की एवज में मोटी राशि देते हैं. इसके साथ ही लोडिंग, अनलोडिंग और कोयला खनन में लगे आउटसोर्सिंग कंपनियों को सुरक्षा प्रदान करने के एवज में माफिया तत्व करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलते हैं. आउटसोर्सिंग कंपनियां भी इन्हीं के रहमोकरम पर अपना काम कर पाती है.

कोयले की अवैध कमाई की पृष्ठभूमि 1950 में बीपी सिन्हा ने बनाई. पूरे कोयलांचल में सिन्हा का एकछत्र राज था. बरौनी निवासी विंदेश्वरी प्रसाद सिन्हा 1950 में धनबाद आए. भाषण की कला, हिम्मत, ताकत सबमें माहिर माने जाते थे. कोलियरी मालिकों के बीच उनकी जबरदस्त पैठ बनी. बीपी सिन्हा इंटक से जुड़े और ताकतवर मजबूत नेता के रूप में उभरे. युवा पहलवानों की फौज बनाई, जिसमें सूरजदेव सिंह इनके सबसे विश्वासपात्र पहलवान थे. इनका इतना दबदबा था कि इन्हीं की मर्जी से कोयला खदाने चलती थीं. लेकिन 29 मार्च, 1978 को अपने ही लोगों ने उनकी हत्या कर दी. हत्या का आरोप सूरजदेव सिंह और सकलदेव सिंह पर लगा. बीपी सिन्हा की हत्या के बाद सूरजदेव सिंह का नाम उभरा और कोयलांचल में सूरजदेव का राज कायम हो गया. पूरे कोयलांचल में इनका आतंक था और इनका आवास सिंह मेंशन कोयलांचल की राजनीति और अवैध कमाई की धुरी बना. सिंह मेंशन के इशारों पर ही कोयलांचल में पत्ता हिलता था. वे अपने विरोधियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और उन्हें अपने रास्ते से हटाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ते. चंद्रशेखर के करीब आकर कोयलांचल में उनका कद और बढ़ गया और पूरे कोयलांचल में सिंह मेंशन की तूती बोलने लगी. 1991 में हार्ट अटैक से हुई उनकी मौत के बाद परिवार के बीच ही विवाद हो गया और सभी भाइयों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई. इसके कारण परिवार में ही गैंगवार छिड़ गया और एक दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या हुई. ■

बंद पड़े खदानों से अरबों की कमाई

कोयला कंपनियों द्वारा खनन के बाद बंद की गई कोयला खदानों को कोयला तस्कर एवं माफिया निशाना बनाते हैं. रैट होल के जरिए स्थानीय मजदूरों एवं कोयला चोरों को बंद खदानों में खनन के लिए भेजते हैं. इन बंद खदानों की सुरक्षा के लिए कोयला कंपनियां करोड़ों रुपए खर्च करती हैं, इसके बाद भी कोयला तस्कर बंद खदानों से प्रतिदिन लाखों टन कोयला निकालने में सफल होते हैं. इस कोयला की तस्करी कर इसे बनारस सहित देश की अन्य मंडियों में भेजा जाता है. हर पुलिस नाके पर एक निश्चित राशि तय होती है, जिसे कोयला माफिया ईमानदारी से पुलिस को पहुंचा देते हैं. कोयलांचल में पदस्थापित पुलिस अधिकारियों की कमाई करोड़ों में होती है और ये धंधा बेरोकटोक चलता है. इस अवैध कमाई में राजनेताओं और पत्रकारों का भी हिस्सा होता है. बंद पड़े खदानों से कोयला की तस्करी कर माफिया रातों-रात करोड़पति बन जाते हैं. अब उत्तर प्रदेश के माफियाओं सहित बिहार एवं कोयलांचल के माफियाओं की भी धमक है. छोटे-छोटे कोयला तस्कर इन लोगों द्वारा संरक्षण देने के एवज में एक मोटी राशि माफियाओं को देते हैं, ताकि धंधे में कोई रुकावट न आ सके. ■

feedback@chauthiduniya.com

सबका साथ-सबका विकास में छूटा आदिवासियों का हाथ

जो कमज़ोर है लुटेगा वही टिकेगा जो बिकेगा

उद्योगपतियों को मुनाफा कमाने के लिए जमीन चाहिए. शहर में जमीन है नहीं, उनकी नजर अब आदिवासियों की जमीन पर है. यहां भू-गर्भ में छिपे खनिज संपदाओं का दोहन अभी तक नहीं हुआ है. विकास लाना है, तो किसी न किसी को तो विनाश की मार झेलनी ही पड़ेगी. सरकारी अमला सोचता है कि आदिवासियों की जमीन छीन लो, तो वे विरोध-प्रदर्शन भी नहीं करेंगे और करेंगे भी तो सुनेगा कौन? इसलिए आज निशाने पर आदिवासी और किसान हैं, कल किसी और की बारी है..

चंदन राय

गोड्डा में सत्याग्रह स्थल पर हाथों में माइक लेकर महिलाएं कोई अंगिका गीत गा रही हैं. गीत के बोल हैं-जान मोरा जइतय अडानी, जइतय मोरा परनवां, नहियैं छोड़बय हे अडानी गायघाट अंगनमा. सत्याग्रह स्थल पर हजारों महिलाएं, बच्चे, बूढ़े और जवान गीत के बोल पर झूम रहे हैं. कुछ बच्चे हाथ में काला झंडा लहराकर अडानी वापस जाओ का नारा लगा रहे हैं. आपको आश्चर्य होगा, लेकिन यहां खेतों में काम करने वाली महिलाएं हों, बच्चे, अनपढ़ जवान या फिर मजदूर सभी अडानी के नाम से बखूबी वाकिफ हैं. विश्वास न हो तो आप किसी भी नंग-धड़ंग घूमते बच्चे से पूछ लीजिए. वह बता देगा कि यही अडानी हमारी जमीन, हमारा घर छीनने आ रहा है. एक बार विरोध की आवाज गूंजती है, तो अचानक कई गांवों, घरों से हजारों महिलाएं, बच्चे, जवान, मजदूर, आदिवासी सड़कों पर निकल पड़ते हैं. जुलूस को देखकर ऐसा लगता है मानो अडानी विरोधी आंदोलन का नेतृत्व अब महिलाओं ने संभाल लिया है. जुलूस में महिलाओं के एक हाथ में लाठी, काला झंडा तो दूसरे हाथ में दरांती, हंसुली जरूर दिख जाएंगे. यहां तक कि छोटे-छोटे आदिवासी बच्चे भी सड़कों पर लाठी लेकर काफी संख्या में विरोध-प्रदर्शन करते दिखेंगे.

जंगल छिन गया, तो कहां जाएंगे आदिवासी

गोड्डा के आदिवासियों को डर सता रहा है कि अगर उनकी जमीन छिन गई, तो फिर वे क्या करेंगे? यह जमीन सिंचित और बहुफसली है. जमीन ही आदिवासियों का जीवन, उनकी संस्कृति या यूं कहें कि पहचान है. उद्योगपतियों की नजर उनकी जमीन और भू-गर्भ में छिपे खनिज-संपदाओं पर है. सरकार तर्क दे रही है कि अगर विकास चाहिए तो आदिवासियों को जमीन का मोह छोड़ना होगा. जमीन पर उद्योग-धंधे लगेंगे, तो स्थानीय इलाकों का तेजी से विकास होगा. यहां तो यह दलील भी थोथी साबित हो रही है. गोड्डा में अडानी 1600 मेगावॉट बिजली का उत्पादन करने के लिए एक हजार एकड़ से अधिक जमीन पर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं. झारखंड सरकार ने जून 2015 में एक एमओयू साइन किया था. मेक इन इंडिया के तहत यह प्रोजेक्ट स्थापित होगा, लेकिन यहां की बिजली झारखंड सरकार को नहीं, बल्कि बांग्लादेश को दी जाएगी. हालांकि स्थानीय विरोध के बाद अडानी की कंपनी राज्य सरकार को 25 प्रतिशत बिजली देने पर राजी हुई. जल, जंगल, जमीन छिनेगा आदिवासियों का, प्रदूषण की मार झेलेंगे आदिवासी, मुनाफा कमाएंगे अडानी और बिजली सप्लाई होगी बांग्लादेश को. यही गणित भोले-भाले आदिवासियों को समझ नहीं आ रही है. एक-दो नहीं, बल्कि सैकड़ों गांव इस प्रोजेक्ट की भेंट चढ़ जाएंगे. इस पर बालिया कित्ता गांव की विद्या देवी कहती हैं, अगर सरकार स्कूल, कॉलेज, रेलवे या अस्पताल के लिए जमीन मांगती, तो हम जरूर दे देते, लेकिन अडानी के पावर प्लांट को नहीं देंगे. चाहे इसके लिए हमारी जान ही क्यों न चली जाए?

पीला कार्ड से एंट्री सरकारी कार्ड अमान्य

अडानी को जमीन देने के लिए जनसुनवाई हुई थी. इसमें शामिल होने के लिए कुछ ग्रामीणों को पीला कार्ड दिया गया था. अब इस जनसुनवाई की हकीकत भी जान लीजिए. बालिया कित्ता गांव के ही रविंदर महतो बंटाई पर खेती करते हैं. वे कहते हैं कि हमें मीटिंग में नहीं जाने दिया गया. हमारे पास वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी था, लेकिन कहा गया कि बिना पीला कार्ड के नहीं जाने देंगे. अब पीला कार्ड की सच्चाई भी जान लेते हैं. एक युवा नाम नहीं बताने की शर्त पर कहता है, हमारा आस-पास के गांव में एक धुर जमीन भी नहीं है, पर जनसुनवाई में आने के लिए हमें पैसे दिए गए. पीला कार्ड मिलने के बाद हम जनसुनवाई में गए और अधिकारियों के कहे अनुसार किया. ग्रामीण अनिल मंडल कहते हैं, जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी नहीं मान रहे हैं, तो कल अडानी हमें मुआवजा क्या देगा? मुआवजा सिर्फ उनको मिलेगा, जिनके नाम पर जमीन होगी. उनका क्या, जो जमीन मालिकों का खेत जोतते हैं. पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव कहते हैं, जनसुनवाई के लिए पीला कार्ड जारी करने की इजाजत किसने दी? क्या यह लीगल है? इस कार्ड पर किसी अधिकारी का हस्ताक्षर नहीं है और न ही कोई सरकारी मुहर. छह दिसंबर 2016 को हुई जनसुनवाई फर्जी थी. इसे रद्द किया जाना चाहिए. अगर जनसुनवाई होनी है तो खुले मैदान में हो, जहां सभी गांवों के लोगों को बुलाया जाए. जनसुनवाई के लिए कंपनी के अधिकारियों को डोर टू डोर जाना था. रैयतों से जमीन लेने के लिए सीधे बात करनी थी. क्या कभी इन गांवों में कंपनी का कोई प्रतिनिधि आया?

प्रदीप यादव कहते हैं, हम सरकार को दिसंबर तक का समय देते हैं. तब तक हम देखेंगे कि सरकार रैयतों के हित में फैसले लेती है या नहीं. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम अनिश्चितकालीन अनशन करेंगे. वहीं प्रदीप यादव के सहयोगी अनिल आर्या कहते हैं कि भू-अधिग्रहण के लिए 80 प्रतिशत रैयतों की सहमति जरूरी है. अपने लोगों को पीला कार्ड जारी कर जनसुनवाई करा कर रैयतों की सहमति भी दिखा दी गई. अडानी का साथ केवल वही लोग दे रहे हैं, जो शहरों में बसे हैं और जिन्हें जमीन से कोई मतलब नहीं है. जबकि 600 रैयतों ने शपथ पत्र देकर कहा था कि वे अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं.

अडानी कंपनी के एक अधिकारी प्रभाकर झा ने बताया कि जीतपुर कोल ब्लॉक आवंटित होने के कारण इस परियोजना को गुजरात के कच्छ के मुंद्रा से यहां लगाने की योजना बनाई गई. फिलहाल पुराने हिसाब से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत प्रति एकड़ 14 लाख रुपए रैयतों को दिए जाएंगे. इस पर अनिल आर्या कहते हैं कि यहां 2014 में जमीन की कीमत 41 लाख रुपए प्रति एकड़ थी, जिसे 2015 में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 3.25 लाख रुपए प्रति एकड़ कर दिया गया. इस हिसाब से प्रति एकड़ डेढ़ करोड़ रुपए से ज्यादा अडानी कंपनी को फायदा पहुंचाया गया.

गोड्डा समाहरणालय के समक्ष जनसुनवाई रद्द करने की मांग को लेकर हाल में विशाल प्रदर्शन हुआ था. जमीन बचाओ, किसानी बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले रैली निकाली गई. हाथों में बैनर व तख्ती लिए हजारों आदिवासी नारे लगाते हुए रैयत समाहरणालय परिसर पहुंचे. प्रदर्शनकारियों ने डीसी से भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का पालन कराने की मांग की. प्रदीप यादव ने कहा कि कुछ बिचौलिए जबरन रैयतों की जमीन अडानी के पास बेचने का काम कर रहे हैं, लेकिन प्रभावित गांवों के रैयत अपनी मांगों से पीछे नहीं हटेंगे. कंपनी के लोग जबरन जमीन हथियाना चाहते हैं. जांच रिपोर्ट आने तक अधिग्रहण की प्रक्रिया रोक देनी चाहिए. वहीं पूर्व विधायक प्रशांत कुमार इसे जेवीएम की रैली बताते हैं. वे कहते हैं कि पोड़ैयाहाट विधायक भयभीत हो गए हैं. उन्होंने विधानसभा व जिला प्रशासन को गुमराह करने का काम किया है. गायघाट में सत्याग्रह स्थल के पास समरूआ व सोनडीहा आदि गांवों में जिला प्रशासन की टीम अधिग्रहण के लिए जमीन की मापी करने गई थी. इन लोगों के खेतों में उतरने की सूचना मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए. सैकड़ों ग्रामीण पारंपरिक हथियार के साथ मौके पर पहुंचे और अडानी, जिला प्रशासन व पुलिस पदाधिकारियों की टीम को खदेड़ दिया. इस दौरान उन्होंने चिन्हित भूमि की रेखा को भी मिटा दिया. मोतिया से वक्सरा तक निकाली गई महारैली में महिलाओं व बच्चों ने 'अडानी वापस जाओ' का नारा बुलंद किया.

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोतिया हाई स्कूल में 5 मार्च को पर्यावरण जनसुनवाई रखी गई थी. इस दौरान जनसुनवाई स्थल पुलिस छावनी में बदल दी गई थी. जिला प्रशासन, अडानी कंपनी के कुछ पदाधिकारी और पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली से आए कुछ अधिकारी भी उपस्थित थे. पर्यावरण जनसुनवाई में करीब 8 हजार ग्रामीण पहुंचे थे. अचानक हंगामा शुरू हो गया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर लाठियां भांजी और आंसू गैस के गोले छोड़े. रैयतों को भड़काने का आरोप लगाकर प्रदीप यादव को भी 22 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रदीप यादव के सहयोगी अनिल आर्या ने बताया कि प्रदीप यादव कई दिनों से आमरण अनशन पर थे. जेल में उनका उपवास जबरन तुड़वाया गया, लेकिन काफी कमजोर हो जाने के कारण वे अभी रिम्स में इलाज करा रहे हैं.

पूंजीपति मुनाफे के लिए अपनी लूट जारी रखे हैं. इनके इशारे पर ही सरकार अपने अमलों को आदिवासियों के शोषण और विस्थापित करने की छूट देती है. वहीं सरकारी कारिंदे सरकार का हुक्म बजाने में मानवाधिकार उल्लंघन की सभी सीमाएं लांघ जाते हैं. नक्सलवाद की जड़ भी आदिवासियों के इसी आक्रोश में छिपा है. इसे हवा देकर ही नक्सली आदिवासी गांवों में अपने पैर जमा रहे हैं. ऐसे में क्या अब सरकार से यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्यों पूंजीपतियों के मुनाफे के लिए आदिवासियों और पुलिस को आपस में भिड़ाया जा रहा है. विकास तो हो, लेकिन आदिवासियों के विस्थापन और विनाश की शर्त पर नहीं, क्या यह सरकार तय करेगी. ■

feedback@chauthiduniya.com

ऊर्जा सचिव पर था दबाव, छुट्टी पर गए

झारखंड के ऊर्जा सचिव एसके रहाते पर जब पावर प्रोजेक्ट को फायदा पहुंचाने के लिए दबाव डाला गया, तब वे लंबी छुट्टी पर चले गए. ऊर्जा मंत्रालय अभी मुख्यमंत्री रघुबर दास के पास है. सचिव से कहा गया था कि अडानी पावर और सरकार के बीच एमओयू में कुछ परिवर्तन किया जाए. ऊर्जा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि अडानी पावर कंपनी एमओयू के शर्तों में कुछ परिवर्तन करना चाहती थी. रहाते कुछ हद तक शर्तों में परिवर्तन के लिए तैयार थे, लेकिन सभी शर्तों को मानने के लिए राजी नहीं हुए. नियम के अनुसार कोई कंपनी जो पावर प्रोजेक्ट लगाती है, उसे अपने उत्पादन की 25 प्रतिशत बिजली राज्य सरकार को देनी होती है. इसके अनुसार नियामक इकाई द्वारा तय कीमत पर पावर कंपनी राज्य सरकार को बिजली देगी और उत्पादन के एक हिस्से की कीमत कंपनी खुद तय करेगी. इतना ही नहीं, अडानी पावर यह भी चाहती थी कि राज्य सरकार को 25 प्रतिशत बिजली इस प्रोजेक्ट के अलावा किसी अन्य सोर्स से उपलब्ध कराया जाए. रहाते तमाम शर्तों को मानने के लिए तैयार थे, लेकिन वे कंपनी द्वारा बिजली की कीमत तय किए जाने पर अड़ गए. ■

अंधेरे में झारखंड, रौशन होगा बांग्लादेश

गौतम अडानी झारखंड के गोड्डा में एक पावर प्लांट लगाना चाहते हैं. इसमें पैदा होने वाली 1600 मेगावाट बिजली बांग्लादेश को बेची जाएगी. इसके लिए अडानी और बांग्लादेश बिजली बोर्ड के बीच जून 2015 में समझौता हुआ है. उस दौरान नरेंद्र मोदी ढाका यात्रा पर गए थे. स्थानीय समाजसेवक रामप्रसाद कहते हैं कि इस प्लांट से उत्पादित बिजली बांग्लादेश को बेचा जाएगा. अडानी को उत्पादित बिजली की बांग्लादेश में ज्यादा कीमत मिलेगी. यहां का पानी, यहां का कोयला, जमीन हमारी, प्रदूषण की मार झेलें हम और मुनाफा कमाए अडानी. यह नहीं चलेगा. यहां से कम से कम एक साल में 2100 करोड़ रुपए का मुनाफा अडानी को होगा. विपक्ष का आरोप है कि इस पावर प्लांट से झारखंड को धुआं और विस्थापन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा. झाविमो के महासचिव बंधु तिर्की ने कहा है कि अब यह आंदोलन संथाल तक ही सीमित न रहकर पूरे राज्य का बनेगा. सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर रहे अन्य संगठनों को भी इस आंदोलन से जोड़ा जाएगा. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित पावर प्लांट की जद में 273 गांवों की 3.25 लाख आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आ रही है. ऐसे में सरकार को अडाणी पावर के मामले में पुनर्विचार करना चाहिए व भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की न्यायिक जांच करानी चाहिए. ■

यह आदिवासियों पर थोपा गया युद्ध है

नियमतः आदिवासियों की ज़मीन सरकार बिना आदिवासियों की ग्राम सभा की अनुमति के नहीं ले सकती है. संविधान की पांचवीं सूची और छठवीं अनुसूची ने आदिवासियों को उन इलाकों की सारी भूमि का मालिक बनाया है. संथाल परगना टेनेंसी एक्ट के अनुसार, इस इलाके की जमीन को न तो बेचा जा सकता है और न ही इसका हस्तांतरण किया जा सकता है, चाहे वह आदिवासियों की जमीन हो या गैर आदिवासियों की. लेकिन विकास का मॉडल दूसरे की ज़मीन छीन कर ही चल सकता है. सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद भी एक तरह से आर्थिक वर्चस्व की ही लड़ाई हैं. ताकतवर आबादी कमज़ोर आबादी को दबाने के लिए प्रशासनिक अमले का इस्तेमाल करती है. भगत सिंह ने कहा था कि जब तक लोगों की मेहनत और उनकी जमीनों को लूटने वाले हैं, तब तक लड़ाई जारी रहेगी. ■

कश्मीर में इंटरनेट बंद करने के उल्टे परिणाम

हारून रेशी

घाटी में सरकार की ओर से इंटरनेट सेवाओं को आए दिन बंद करना कोई नई बात नहीं है. पिछले चार वर्षों के दौरान सरकार ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर 31 बार इंटरनेट पर पाबंदी लगाई है. लेकिन अभी हाल ही में पहली बार सरकार ने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीटर, स्काईप और यूट्यूब समेत सोशल नेटवर्किंग की 22 वेबसाइट्स को एक महीने के लिए बंद कर देने की घोषणा की. राज्य सरकार ने 25 अप्रैल को एक लिखित आदेश जारी कर ये पाबंदी लागू की है. दिलचस्प बात ये है कि सरकार ने एक ऐसे समय में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई है, जब यहां लगभग एक महीने पहले से 3जी व 4जी इंटरनेट बंद है. फिलहाल घाटी में केवल 2जी इंटरनेट सुविधा ही उपलब्ध है. जम्मू कश्मीर सरकार ने सोशल मीडिया पर ये पाबंदी 132 वर्ष पुराने क़ानून इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत लगाई है. अंग्रेज़ी शासन के इस क़ानून के तहत सरकार टेलीग्राफ संदेशों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने पर रोक लगा सकती थी. अब घाटी में कानूनी विशेषज्ञों के बीच ये बहस छिड़ गई है कि क्या इस क़ानून के तहत आधुनिक तकनीक पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

दिलचस्प बात ये है कि सरकार ने एक ऐसे समय में घाटी में इंटरनेट सेवाएं बंद की है, जबकि एक सप्ताह पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सेवाओं को नागरिकों का मूल अधिकार बताया था. सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक केस की सुनवाई के दौरान फैसला देते हुए स्पष्ट किया था कि इंटरनेट सुविधाएं अभिव्यक्ति की आज़ादी से जुड़ी हुई हैं. लिहाज़ा सरकार किसी भी स्थिति में नागरिकों की इंटरनेट सुविधा छीन नहीं सकती है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेट सुविधाओं को मानवाधिकार में शामिल कर दिया था. भारत में केरल पहला राज्य है, जिसने अपने नागरिकों के लिए इंटरनेट को मूल अधिकार स्वीकार किया है.

इंटरनेट पर पाबंदी के कारण आम कश्मीरियों में सरकार के विरूद्ध आक्रोश बढ़ता जा रहा है. सोशल नेटवर्किंग साइट्स बंद होने से कुछ देर पहले ही कुछ पत्रकारों ने फेसबुक पर अपने आख़िरी संदेश में सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा और आलोचना की. युवा पत्रकार गौहर गीलानी ने लिखा कि लड़कियों और लड़कों के स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती से बौखलाहट का शिकार हुई पीडीपी-भाजपा सरकार एक महीने के लिए सोशल मीडिया की 22 वेबसाइट्स बंद कर रही है. दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र, कश्मीर का सच बाहर आने से भयभीत है. युद्ध अपराधों को छिपाया जा रहा है. मशहूर महिला पत्रकार हरेन्द्र बावेजा ने सरकार के इस फैसले पर व्यंग्य करते हुए लिखा, कश्मीर में ई-कर्फ्यू (इलेक्ट्रनिक कर्फ्यू) लागू. सोशल मीडिया पर पाबंदी. अब आगे क्या करोगे. टीवी चैनलों पर भी पाबंदी लगाओ, ताकि घाटी से कोई ख़बर बाहर ना आए. एक कश्मीरी नौजवान इरशाद नबी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि भारत सरकार ने कश्मीर में इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी. अब आप हमारे पोस्ट कश्मीर के हर कोने और हर इलाक़े में दीवारों पर पढ़ेंगे. अब हर जगह हमारी टाइमलाइन होगी. एक नौजवान हाजुक क़ादरी ने लिखा, आपने पिछले वर्ष कर्फ्यू लागू किया था, तब हम खाद्य पदार्थों और अन्य चीज़ों के बिना रहे. इंटरनेट को बंद करना कोई बड़ी बात नहीं है. हम इसके बिना भी अपना संघर्ष जारी रख सकते हैं.

गौरतलब है कि क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर इंटरनेट बंद करने के बावजूद, फिलहाल घाटी में न कहीं शांति है और न क़ानून लागू नज़र आता है. हर बीते दिन के साथ हालात और बदतर होते जा रहे हैं. इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने के बाद अफ़वाहबाज़ी को रोकना सरकार के लिए नई चुनौती है. कई बार सुरक्षाबलों से जुड़ी हिंसा व अत्याचार की झूठी ख़बरें फैलाई जाती हैं. अब जबकि लोगों के पास ख़बरों की पुष्टि के लिए इंटरनेट की सुविधा मौजूद नहीं है, तो अफ़वाहें जंगल की आग की तरह फैल जा रही हैं. दिलचस्प बात ये है कि इंटरनेट सेवाओं के न होने से सरकार भी अफवाहों का खंडन नहीं कर पा रही है. 19 अप्रैल को पूरी घाटी में अचानक ये अफवाह फैल गई कि पुलवामा ज़िले में सुरक्षा बलों ने 100 स्टूडेंट्स के साथ मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिनमें कई की हालत नाज़ुक है. ये अफवाह फैलते ही घाटी के अन्य क्षेत्रों के स्टूडेंट्स सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया. दिन भर झड़पें जारी रहीं. बाद में पता चला कि पुलवामा में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था. जिस दिन श्रीनगर संसदीय चुनाव हो रहे थे, उस दिन घाटी में अफवाह फैल गई कि केंद्र ने महबूबा सरकार को बर्खास्त कर दिया है. लेकिन बाद में पता चला कि ये झूठ है. इसी प्रकार, 15 अप्रैल को जब चुनाव परिणाम आए और फारूक़ अब्दुल्ला सांसद चुने गए, तो अचानक ये अफवाह फैली कि सेना के अत्याचारों के विरोध में फारूक़ अब्दुल्ला ने चुनाव जीतने के कुछ देर बाद ही संसदीय सीट से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है. लेकिन ऐसा कुछ नहीं था. 21 अप्रैल को श्रीनगर में अफ़वाह फैल गई कि कुछ दिनों पूर्व सुरक्षा बलों के हाथों इक़रा नाम की जो लड़की घायल हो गई थी, वो दम तोड़ चुकी है. ये अफवाह फैलते ही श्रीनगर के डाउन टाउन में कई जगहों पर नौजवानों ने सुरक्षा बलों पर पथराव शुरू कर दिया.

इसी प्रकार की कई झूठी अफवाहें यहां थोक के हिसाब से दिन भर गर्दिश करती रहती हैं. इंटरनेट पर पाबंदी लागू कर सरकार ने ख़ुद अफवाहों के बाजार खोल दिए हैं, क्योंकि जब आज़ाद और विश्वसनीय सूत्रों तक जनता की पहुंच बंद की जाती है, तो वे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं. पहले लोग कोई भी ख़बर सुनने के बाद यहां के बड़े अख़बारों की वेबसाइट्स चेक करते थे कि इन अख़बारों ने ये ख़बर अपलोड की है या नहीं. जब वो ख़बर बड़े अख़बारों की वेबसाइट्स पर नहीं मिलती थी, तो लोग समझ जाते थे कि ये झूठी ख़बर है. लेकिन अब ख़बर की पुष्टि का कोई प्रभावी तरीका नहीं है.

2016 में पूरी घाटी में सरकार विरोधी लहर फैलने के बाद सरकार ने लगभग पांच महीने तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी थी. आज भी कुछ पुलिस अधिकारी निजी बातचीत में स्वीकार करते हैं कि 2016 में हालात हद से ज्यादा ख़राब हो जाने के कई कारणों में एक कारण ये भी था कि जनता को सूचना के अधिकार से वंचित रखा गया. यानि इंटरनेट बंद करके इंफॉर्मेशन तक उनकी पहुंच छीन ली गई. एक उच्च पुलिस अधिकारी ने चौथी दुनिया को बताया कि 2016 में हर पल सुरक्षा बलों की ओर से जनता पर अत्याचार व हिंसा की सच्ची-झूठी कहानियां गर्दिश करती रहती थीं. उस समय हमारे पास भी लोगों तक असली बात पहुंचाने का कोई जरिया नहीं था. इन अफवाहों के कारण लोग आक्रोशित हो जाते थे और सुरक्षा बलों के खिलाफ जनाक्रोश बना रहता था. यही कारण भी था कि छह महीने तक हालात ठीक नहीं हो पाए.

इंटरनेट पर पाबंदी के जो दूसरे परिणाम इन दिनों घाटी में देखने को मिल रहे हैं, वो ये है कि पीडीपी, नेशनल कांफ्रेंस और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भी जनता तक पहुंच बंद हो गई है. पहले ये पार्टियां अपने प्रेस रिलीज़ को सोशल मीडिया के जरिए भी जारी करती थीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होता. नेशनल कांफ्रेंस के क्षेत्रीय प्रवक्ता इमरान नबी डार का कहना है कि हम व्हाट्सऐप के जरिए अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क में रहते थे, लेकिन अब वो संपर्क टूट गया है. इंटरनेट बंद होने की वजह से अब हम बैठकों का आयोजन भी नहीं कर पाते हैं. उल्लेखनीय है कि नेशनल कांफ्रेंस के कार्यवाहक अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला आमतौर पर ट्वीटर पर सक्रिय रहते थे और इसी के द्वारा वे अपने विचार जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन अब वे भी ऐसा नहीं कर पाएंगे. अनंतनाग संसदीय सीट के लिए चुनाव होना बाकी है. इंटरनेट बंद हो जाने का प्रभाव चुनाव प्रचार पर भी पड़ेगा. चूंकि इस क्षेत्र में हालात खराब रहने के कारण राजनीतिक नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया के द्वारा ही चुनावी मुहिम चला रहे थे, जो अब बंद हो चुकी है. कांग्रेस के एक नेता ने चौथी दुनिया को बताया कि हम अजीब उलझन में पड़ गए हैं. चुनाव प्रचार के लिए तो पहले से ही अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे थे और अब सोशल मीडिया के द्वारा भी जनता तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं.

इंटरनेट बंद हो जाने के कारण पत्रकारों को भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है. अख़बारों के कार्यालयों में कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. विभिन्न ज़िलों में काम करने वाले अखबारों के प्रतिनिधि अपनी रिपोर्ट्स कार्यालय को नहीं भेज पा रहे हैं. दिल्ली के अखबारों के लिए काम करने वाले पत्रकारों को भी इसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. इंटरनेट पर पाबंदी लगने से दूरसंचार कंपनियां भी निरंतर घाटे में चल रही हैं. उल्लेखनीय है कि 2016 में इंटरनेट पर रोक लगने से जम्मू-कश्मीर में दूरसंचार कंपनियों को 180 करोड़ रुपए का नुक़सान उठाना पड़ा था. टेलीकॉम रेगूलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 31 दिसंबर 2016 तक जम्मू-कश्मीर में एक करोड़, 12 लाख, 72 हज़ार, 751 मोबाइल उपभोक्ता रजिस्टर्ड थे. जाहिर है कि इतनी बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की इंटरनेट सेवाएं बंद हो जाने का नुकसान प्रत्यक्ष रूप से कंपनियों को ही उठाना पड़ रहा है.

इंटरनेट पाबंदी का सबसे अधिक नुकसान राज्य में आईटी क्षेत्र को हो रहा है. पहले भी हज़ारों नौजवान हालात ख़राब हो जाने और इंटरनेट बंद हो जाने के कारण अपने रोज़गार से हाथ धो बैठे थे. अब फिर से वही सिलसिला शुरू हो चुका है. वे व्यापारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिनके बिजनेस का संबंध प्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट से है. यहां फिलहाल ऑनलाइन शॉपिंग की कल्पना भी नहीं की जा सकती. कुरियर कंपनियों का भी कामकाज प्रभावित हो रहा है. लोग इंटरनेट की सहायता से बिजली, पानी और अन्य चीज़ों के बिल भुगतान करने में असमर्थ हैं. बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है. वे अपने कॉलेजों और युनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट तक पहुंच से वंचित हैं. ये कहा जा सकता है कि इंटरनेट पर रोक ने कश्मीर को व्यवहारिक रूप से कई दशक पीछे धकेल दिया है. कश्मीरी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष मुश्ताक़ अहमद ने सरकार से मांग की है कि वो इंटरनेट और सोशल मीडिया पर पाबंदी के कारण व्यापारियों को हो रहे नुक़सान की भरपाई करे. उन्होंने कहा कि सरकार जब इंटरनेट पर पाबंदी लागू करती है, तो उन्हें उन लोगों को मुआवज़ा भी देना चाहिए, जिन्हें इसके कारण नुकसान उठाना पड़ रहा है.

इधर सरकार का कहना है कि इंटरनेट को बंद करने का उसका फैसला घाटी में शांति स्थापना के लिए है. लेकिन सवाल ये है कि अगर इंटरनेट बंद करने से शांति स्थापित हो जाती, तो पिछले चार वर्षों में 31 बार ऐसा करने से यहां शांति क्यों नहीं हुई. सच्चाई तो ये है कि कश्मीर के हालात सुधारने और यहां वास्तविक शांति स्थपित करने के लिए इंटरनेट बंद करना जरूरी नहीं है, बल्कि बातचीत के दरवाज़े खोलना ज़रूरी है. ■

कश्मीर : बेनतीजा बातचीत का सिलसिला

- **2000 :** सर्वदलीय शिष्टमंडल का कश्मीर दौरा. लेकिन, मामला नहीं सुलझा.
- **2001 :** केसी पंत समिति. पाकिस्तान को पक्ष बनाने की हुर्रियत की मांग. बातचीत असफल रही.
- **2002 :** राम जेठमलानी की अगुवाई वाली समिति कश्मीर गई. इस समिति में दिलीप पडगांवकर, शांति भूषण, अशोक भान, जावेद लइक, फली एस नरीमन, एम जे अकबर शामिल थे. समिति ठोस बातचीत करने में नाकाम रही.
- **2003 :** एन एन वोहरा समिति बनी. वोहरा समिति हुर्रियत के नरम धड़े से बातचीत करने में सफल रही. तत्कालीन गृहमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के साथ कश्मीरी नेताओं ने बातचीत की, लेकिन गतिरोध टूटा नहीं.
- **जुलाई 2003 :** अरुण जेटली को बातचीत की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन वे सफल नहीं हुए और कोई समाधान नहीं पेश कर पाए. इसके बाद पूर्व रॉ अध्यक्ष ए एस दौलत और पत्रकार आर के मिश्रा ने भी बातचीत की पहल की, लेकिन वे किसी ठोस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए.
- **फरवरी 2006 :** दिल्ली में एक गोलमेज सम्मेलन हुआ. कश्मीरी पार्टियों ने स्वागत तो किया और कहा कि इसे सफल बनाने के लिए केन्द्र को अपनी नीति बदलनी होगी. नरम धड़े ने स्वागत किया, लेकिन गरम धड़े ने विरोध किया.
- **मई 2006 :** फिर से बैठक हुई. मीर वाइज ने कश्मीरी अवाम से बात करने की मांग की. पीओके को भी बातचीत में शामिल करने की मांग की, इससे गतिरोध बरकरार रहा.
- **अक्टूबर 2010 :** दिलीप पडगांवकर की अगुवाई वाली समिति में राधा कुमार, एम एम अंसारी शामिल थे. इस समिति ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट दी. समिति ने शांति बहाली के लिए कई रास्ते सुझाए, लेकिन, इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा नहीं हुई.
- **2016 :** यशवंत सिन्हा समिति. समिति ने कई समाधान सुझाए, जैसे कश्मीर में मानवाधिकार को बेहतर बनाया जाए, लेकिन इन सुझावों पर अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है.

वनाधिकार कानून

जंगल का अधिकार ज़मीन पर उतरता ही नहीं

कुमार कृष्णन

वन व अन्य प्राकृतिक संपदा पर आश्रित समुदायों के स्वतंत्र एवं पूर्ण अधिकार का विषय वनाधिकार आंदोलन में हमेशा से प्रमुख रहा है. अंग्रेज़ी राज के ज़माने में ही इन संपदाओं पर उपनिवेशिक शासकों ने पूरा कब्ज़ा जमा लिया. उन समुदायों का प्राकृतिक संपदा के साथ जो पारंपरिक रिश्ता है, उसमे दख़ल-अंदाज़ी कर उन्हें उनकी विरासत से बेदख़ल कर दिया गया. वनाश्रित समुदाय के सार्वभौमिक अधिकार को स्थापित करने के लिए पिछली दो सदी से वनाधिकार आंदोलन चल रहा है और आज भी ज़ारी है. अंग्रेज़ी शासनकाल की समाप्ति के बाद सत्तासीन हुई आज़ाद भारत की सरकार ने भी प्राकृतिक संपदा की इस लूट को बरक़रार रखा और आर्थिक राजनैतिक ढांचे में किसी प्रकार के कोई भी बुनियादी परिवर्तन नहीं किए. यानि एक ऐतिहासिक अन्यायपूर्ण व्यवस्था आज़ाद भारत में भी चलती रही और इसके खिलाफ जनांदोलन के ज़रिए वनाश्रित समुदाय भी अपनी मांग उठाते रहे. इन संघर्षों की आख़िरकार जीत हुई और आज़ादी के साठ साल बाद भारत की माननीय संसद ने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) कानून यानि वनाधिकार कानून-2006, 15 दिसम्बर 2006 को पारित किया. इस विशेष कानून का मुख्य उद्देश्य वनाश्रित समुदायों पर किए गए ऐतिहासिक अन्याय को खत्म करना और पर्यावरण की सुरक्षा में समुदायों की भूमिका को मज़बूत करना है. इस ऐतिहासिक कानून के पारित होने पर वनाश्रित समुदायों में एक नई चेतना विकसित हुई और साथ-साथ एक विश्वास भी कि अब जल-जंगल-ज़मीन पर लोगों के मालिकाना अधिकार स्थापित होंगे. वनाधिकार कानून में दो प्रमुख अधिकारों को मान्यता दी गई है. पहला, वनक्षेत्र के अंदर जिस जमीन और जंगल पर लोग अपनी आजीविका चला रहे हैं, उस पर और उनकी आवासीय ज़मीन पर मालिकाना अधिकार और दूसरा, पूरे वनक्षेत्र में पहुंच और लघुवनोपज पर वनाश्रित समुदाय का सामुदायिक मालिकाना अधिकार. वनाधिकार कानून में यह भी कहा गया है कि ये अधिकार, समुदाय द्वारा चुनी गई ग्रामसभा ही तय करेगी, जहां शासन-प्रशासन का किसी प्रकार का दख़ल नहीं होगा.

लेकिन आज भी ज़मीनी स्तर पर ठीक इसका उल्टा हो रहा है. सरकारी तंत्र इस कानून के विरोध में काम कर रहा है. वर्तमान केन्द्र सरकार तो एक कदम आगे बढ़कर, इस पूरे कानून को ही बदलने की दिशा में काम कर रही है. लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है. चूंकि वनाधिकार कानून एक विशिष्ट कानून है, इसलिए इसे बदलने के लिए संसद में पास कराना ज़रूरी है. इस सच्चाई से बचने के लिए मौजूदा सरकार ने नए-नए नाजायज तरीकों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है. जैसे, कैम्पा कानून लाकर वनाधिकार कानून के मुकाबले में कम्पनियों को वृक्षारोपण के कार्यों में शामिल करना. चूंकि कैम्पा के तहत 43 हजार करोड़ की पूंजी है और इस पूंजी के आधार पर वनक्षेत्र में वनाधिकार समितियों को निष्प्रभावी किया जा रहा है. एक तरह से वनक्षेत्रों में वनविभाग द्वारा पूंजीवादी व्यवस्था को स्थापित करके परंपरागत वन संरक्षण व्यवस्था को खत्म किया जा रहा है और बहुमूल्य वन एवं खनिज संपदा कम्पनियों को सौंपी जा रही है. इसके कारण वनक्षेत्रों में वनविभाग व कम्पनियों के साथ ग्रामसभा का सीधा टकराव शुरू हो चुका है. इसके फलस्वरूप, वनाधिकार कानून में प्राप्त वनभूमि से समुदायों को विस्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जंगल क्षेत्रों में नक्सलवाद की आड़ लेकर सलवाजुडूम और पी.आर.डी जैसी संस्थाएं खड़ी की जा रही हैं, जिनके जरिए समुदायों के हाथ समुदायों का कत्ल-ए-आम कराया जा रहा है.

समुदायों द्वारा वनाधिकार कानून नियमावली संशोधन-2012 के तहत किए गए व्यक्तिगत दावों को भी बिना किसी कानूनी अड़चन के लम्बित किया जा रहा है. आदिवासी मंत्रालय द्वारा ज़ारी किए गए आंकड़ों से यह साफ ज़ाहिर होता है कि अभी तक कानून की किस प्रकार अनदेखी की गई है. देश में कुल मिला कर 41,71,788 दावे किए जा चुके हैं, जिसमें से 17,20,742 व्यक्तिगत व केवल 62,520 सामुदायिक दावों का ही निष्पादन किया गया है. किए गए दावों में से भी 84.82 प्रतिशत ही निर्धारित किए गए हैं और शेष को निरस्त कर दिया गया या वे लम्बित हैं. व्यक्तिगत दावों के तहत 1,36,12,921 एकड़ एवं 95,45,386 एकड़ वनभूमि पर मालिकाना हक़ प्रदान किया गया है. केवल उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां स्थिति बेहद ही दयानीय है. प्रदेश में कुल 93,644 दावे ही किए गए, जिसमें से केवल 18,555 दावों को ही निर्धारित किया गया है. इन दावों में से सोनभद्र जिले से सबसे अधिक

कानून की अनदेखी से संकट में आदिवासी

वनाश्रित समुदायों पर अन्याय का सबसे बड़ा मामला मानवाधिकार हनन, उत्पीड़न, फर्जी मुकदमों, एनकाउंटर, व अत्याचार का है, जो वन विभाग द्वारा अंग्रेजी कानून 1927 को आधार बनाकर किया जाता है. उन मुकदमों को समाप्त करने व उत्पीड़न को खत्म करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है. साथ ही आदिवासियों के लिए ग्राम सभा के उन अधिकारों को खत्म करने की दिशा में भी सरकार काम कर रही है, जो इन्हें कानूनी रूप से मजबूत बनाते हैं. कानून में उल्लेखित ग्राम सभा के अधिकारों वाले प्रावधान के कारण ही उड़ीसा में नियामगिरी पहाड़ व समुद्र तट में पास्को स्टील कम्पनी को जमीन नहीं मिल सकी थी, क्योंकि ग्राम सभा ने इसके लिए अनुमति नहीं दी. वन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे वनाश्रित समुदायों की एक मांग ये भी है कि 7,000 वनग्रामों को भी राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाय. कानून की अनदेखी के कारण इन्हें हो रही समस्याओं को आदिवासी मंत्रालय ने भी स्वीकार किया है. मंत्रालय द्वारा कहा गया है कि वनों के अंदर वनसम्पदा पर समुदाय का हक न होने की वजह से वनाश्रित समुदाय घोर गरीबी की चपेट में है. वनोपज से लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपए की सालाना आय है. अगर ये राशि सीधे वनाश्रित समुदाय के पास जाए, तो उनकी जीवनशैली में काफी बदलाव आ सकते हैं व उनका विकास हो सकता है. ■

90 हज़ार दावे हैं. बाकि अन्य जिलों से केवल 843 सामुदायिक दावे ही हैं. अगर जांच पड़ताल की जाए, तो पता चलेगा कि प्राप्त दावा पत्रों में भी लोगों को आंशिक रूप से ही भौमिक अधिकार मिले हैं. जिला सहारनपुर में वनग्रामों के दावे अभी तक समाज कल्याण अधिकारी व उपजिलाधिकारी कार्यालय में ही पड़े सड़ रहे हैं. उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े बसपा सरकार के कार्यकाल के ही हैं. उसके बाद इस कानून को लेकर उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की प्रगति नहीं हुई है.

मध्यप्रदेश में भी वनाधिकार अधिनियम का ठीक तरह से अमल नहीं हो पा रहा है. जिन जनजातियों के पास पट्टे हैं, उन पर दबंगों का कब्जा है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र बुधनी में 10 हजार से ज्यादा लोग भूमि का पट्टा पाने के लिए आवेदन दे चुके हैं, लेकिन उसपर अमल नही हो रहा है. मंडला जिले के जोगी सोढा ग्राम पंचायत के इंद्रावन वनग्राम में वनाधिकार कानून का माखौल उड़ाया जा रहा है. दरअसल, वनों में रहने वाले भोले-भाले आदिवासियों को शासन ने वनाधिकार के पट्टे के तहत इंदिरा आवास योजना से नवाज तो दिया, लेकिन आवास की दूसरी किश्त के लिए इन लोगों को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है. बताया जा रहा है कि एक साल पहले इन्द्रावन वनग्राम के 74 लोगों को जिला प्रशासन द्वारा इंदिरा आवास स्वीकृत कर आवास की पहली किश्त के रूप में 24 हजार रुपए दिए गए. इन पैसों से हितग्राहियों ने मैटेरियल खरीद लिया और दूसरी किश्त के 24 हजार मिलने की निश्चिंतता में साहूकारों से ब्याज पर रुपए लेकर घर बनाना शुरू कर दिया. लेकिन न उनका घर बन पाया और न ही इन्हें आवास की दूसरी किश्त मिली. एक्टिविस्ट, लेखक और शोधकर्ता ग्लैडसन डुंगडुंग बताते हैं कि यदि खारिज किए गए दावों को राज्य स्तर पर देखें, तो प्रतिशत के हिसाब से कर्नाटक पहले पायदान पर है. कर्नाटक में 95.7 प्रतिशत दावों को खारिज किया गया है. राज्य में 1,97,246 निष्पादित दावों में से 1,88,943 दावों को खारिज कर दिया गया है. लेकिन यदि इसे संख्या के आधार पर देखें, तो छत्तीसगढ़ इसमें सबसे आगे है, जहां 8,55,696 निष्पादित दावों में 5,07,907 दावों को खारिज कर दिया गया है. इसी तरह 6,08,930 निष्पादित दावों में से 3,74,732 खारिज दावों के साथ मध्यप्रदेश दूसरे स्थान पर है और 3,40,980 निष्पादित दावों में से 2,30,732 खारिज दावों के साथ महाराष्ट्र तीसरे पायदान पर. इसमें एक गंभीर पहलू यह है कि वनाधिकारों का दावा उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा खारिज किया गया है, जहां सबसे ज्यादा खनन कार्य चल रहा है या भविष्य में खनन की ज्यादा संभावनाएं हैं. क्या खनिज सम्पदा पर कब्जा करने के लिए आदिवासी एवं अन्य वनाश्रित लोगों के अधिकारों को नकारा जा सकता है?

सामुदायिक अधिकार के सवाल पर ग्लैडसन डुंगडुंग कहते हैं कि भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी एफआरए स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार 31 अगस्त 2016 तक देशभर में 1,12,051 सामुदायिक दावा पेश किया गया था, जिनमें 47,443 सामुदायिक पट्टा शामिल है, जबकि 64,608 दावों को खारिज कर दिया गया है, जो कुल दावा का 57.6 प्रतिशत है. छत्तीसगढ़, बिहार, केरल, राजस्थान एवं तमिलनाडु में सामुदायिक अधिकार के तहत एक भी पट्टा जारी नहीं किया गया है. असल में जंगलों पर सामुदायिक अधिकार नहीं देने का मूल कारण खनिज सम्पदा है, क्योंकि अधिकांश खनिज जैसे लौह-अयस्क, बॉक्साईट, कोयला इत्यादि जंगल या पहाड़ों में मौजूद हैं. सामुदायिक अधिकार को लेकर एक दिलचस्प मामला छत्तीसगढ़ में उभर कर सामने आया है. छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के परसाकेते गांव एवं सरगुजा जिले के घाटबर्रा गांव को निर्गत सामुदायिक पट्टा को रद्द कर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं अदानी मिनरल्स प्रा.लि. को कोयला खनन हेतु वनभूमि दे दिया गया. इसी तरह का मामला सारंडा जंगल का है, जहां देश का 25 प्रतिशत लौह-अयस्क है. यहां खनन कंपनियां 14,410.09 हेक्टेयर जंगल में खनन कार्य कर रही हैं. यहां 416 आदिवासियों को 315.74 एकड़ वनभूमि का व्यक्तिगत पट्टा निर्गत किया गया है तथा 415 दावों को दखल कब्जा नहीं होने का कारण बताकर खारिज कर दिया गया है. जबकि वहीं 22 नए खनन परियोजनाओं को 9,337.54 हेक्टेयर वनभूमि लीज पर दे दिया गया है. देश में इस तरह के उदाहरण भरे पड़े हैं, जहां आदिवासियों के अधिकारों को नकारते हुए खनन कंपनियों को जंगलों को सौंपा जा रहा है.

शंकर गुहा नियोगी के साथ काम कर चुके और राजगोपाल पी.वी के जनादेश तथा जन सत्याग्रह में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले सीताराम सोनवानी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में वन अधिकार मान्यता पत्र के लिए आठ लाख से अधिक आवेदन आए थे, जिनमें केवल 40 प्रतिशत वन अधिकार मान्यता पत्रों का वितरण किया गया है और बाकी 60 फीसदी आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं. यह शंकाओं को जन्म देता है, जिसकी समीक्षा जरूरी है. प्रदेश में कुल 12 हजार वन आश्रित गांवों में से केवल चार हजार गांवों को सामुदायिक वन अधिकार पत्र दिया गया है. कानून में विशेष पिछड़ी जनजातियों को बसाहट का अधिकार दिया गया है, लेकिन सरकार उन्हें अधिकार न देकर अन्याय कर रही है. ऐसे में आदिवासियों की अस्मिता, संस्कृति, आजीविका आदि सब कुछ खतरे में आ जाएंगे. आदिवासियों को उनका अधिकार न देना उनके हितों के साथ कुठाराघात होगा. पूरा सरकारी तंत्र व उसके सहयोगी जमींदार, भू-माफिया व अन्य निहित स्वार्थ भी पूंजीवाद के अधीन हैं. इसलिए चाहे वो केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, इस तरह के प्रगतिशील जनहितकारी कानून को लागू करने में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है. वनाधिकार कानून 2006 को पारित हुए ग्यारह साल पूरे हो चुके हैं और ये स्पष्ट हो गया है कि वनाधिकार कानून लागू करना एक राजनैतिक संघर्ष है, चूंकि ये व्यापक रूप से भूमि अधिकार आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें करीब 4 करोड़ हेक्टेयर वनभूमि का आवंटन वन समुदायों के लिए सामूहिक रूप से होना निर्धारित है. इसीलिए वनाधिकार आंदोलन में भूमि का सवाल भी अंतर्निहित है. ■

feedback@chauthiduniya.com

सपा के टूटने का हो गया औपचारिक ऐलान, मुलायम करेंगे नई पार्टी का नेतृत्व

बन गया समाजवादी सेकुलर मोर्चा

चौथी दुनिया ब्यूरो

अब यह तय हो गया कि कद्दावर समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव का संरक्षण बेटे अखिलेश यादव को नहीं, बल्कि भाई शिवपाल यादव को मिलेगा. मुलायम की मौजूदगी में शिवपाल यादव ने पांच मई को समाजवादी सेकुलर मोर्चा के नाम से नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया. नई पार्टी बनाने की घोषणा इटावा में हुई. 'चौथी दुनिया' के पिछले अंक में प्रकाशित कवर स्टोरी में संतोष भारतीय ने यह लिख दिया था कि मई महीने में नई पार्टी की घोषणा हो जाएगी. इसप्रकार 'चौथी दुनिया' की खबर एक बार फिर सच और प्रामाणिक साबित हुई. विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद से ही शिवपाल लगातार अखिलेश पर यह दबाव बना रहे थे कि वे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दें और नेताजी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालें. लेकिन अखिलेश ने उनकी बात नहीं मानी, उल्टे प्रो. रामगोपाल यादव ने शिवपाल पर तीखे प्रहार शुरू कर दिए. आखिरकार पांच मई को इटावा में ही मुलायम के बहनोई के घर में जरूरी मंत्रणा के बाद शिवपाल ने नई पार्टी समाजवादी सेकुलर मोर्चा के गठन की घोषणा कर दी.

शिवपाल ने कहा कि नेता जी मुलायम सिंह यादव ही समाजवादी सेकुलर मोर्चा के अध्यक्ष होंगे. शिवपाल बोले कि नेताजी का साथ और आशीर्वाद हमें मिल चुका है. अब आगे की कार्रवाई होगी. पिछले दिनों शिवपाल ने संकेत किया था कि अगर अखिलेश नहीं माने, तो समाजवादी पार्टी में विभाजन हो जाएगा. फिर साफ-साफ कहा था कि मुलायम सिंह यादव को दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो पार्टी से अलग एक सेकुलर मोर्चा बनेगा. शिवपाल ने कहा कि नेता जी की मेहनत से ही समाजवादी पार्टी बनी और खड़ी हुई थी. रामगोपाल की तीखी प्रतिक्रियाओं के जवाब में शिवपाल ने उन्हें शकुनी बताया और कहा कि इस आधुनिक शकुनि को गीता पढ़नी चाहिए. आप जानते ही हैं कि बेटे अखिलेश यादव के हाथों पिता मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटवाने में रामगोपाल यादव ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी. शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव ने पत्रकारों से कहा था कि वह केवल तीन महीने के लिए अध्यक्ष बने हैं और चुनाव के बाद वह नेताजी को राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद लौटा देंगे. लेकिन उन्होंने अपने पिता का अपमान किया. शिवपाल बोले, 'हम लोग नेता जी का सम्मान उन्हें वापस दिलाएंगे.' मुलायम परिवार में अखिलेश की इकाई छोड़ कर बाकी सब मुलायम के साथ खड़े हैं. मुलायम की छोटी बहू अपर्णा यादव भी कह चुकी हैं कि नेता जी को अध्यक्ष पद लौटा दिया जाना चाहिए था. आज स्थिति यह है कि मुलायम समेत उनकी पत्नी साधना (गुप्ता) यादव, छोटे बेटे प्रतीक यादव, बहू अपर्णा यादव सब शिवपाल के साथ खड़े हैं. परिवार में कलह की शुरुआत के समय से मुलायम और शिवपाल साथ हैं.

नई पार्टी के ऐलान के साथ ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई. शिवपाल ने कहा भी कि समाजवादी सेकुलर मोर्चे के गठन की औपचारिकताएं शुरू की जा रही हैं और उम्मीद जताई कि उसमें देश और प्रदेशभर के समाजवादी शरीक रहेंगे. शिवपाल ने दोहराया कि नेताजी के सम्मान की खातिर ही नई पार्टी का गठन किया जा रहा है.

नई पार्टी के ऐलान के साथ ही मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव के तकनीकी तौर पर समाजवादी पार्टी से अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई. शिवपाल ने कहा भी कि समाजवादी सेकुलर मोर्चे के गठन की औपचारिकताएं शुरू की जा रही हैं और उम्मीद जताई कि उसमें देश और प्रदेशभर के समाजवादी शरीक रहेंगे. शिवपाल ने दोहराया कि नेताजी के सम्मान की खातिर ही नई पार्टी का गठन किया जा रहा है. हम देश और प्रदेश स्तर के सभी सेकुलर लोगों से बातचीत करेंगे. हम नई पार्टी के माध्यम से पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय दिलाएंगे. मोर्चे से देश के सभी बड़े सेकुलर नेताओं को जोड़ेंगे. शिवपाल ने कहा कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा सामाजिक न्याय के संघर्ष को तेज करने के इरादे से बन रहा है और संघर्ष के नए दौर का नेतृत्व नेता जी मुलायम सिंह यादव ही संभालेंगे. आप एक बार फिर याद करते चलें कि विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश ने कहा था कि नेता जी केवल तीन महीने के लिए उन्हें सारे अधिकार सौंप दें, चुनाव के बाद वह सारे अधिकार उन्हें लौटा देंगे. लेकिन चुनाव में महज 47 सीटें पाने के बाद भी अखिलेश को अपना कहा याद नहीं रहा. इस बीच उन्होंने मुलायम से मशविरा किए बगैर पार्टी के संविधान में भी फेरबदल कर दिया और मुलायम शिवपाल को ताक पर रख कर नए सिरे से सदस्यता अभियान भी शुरू कर दिया. ■

'चौथी दुनिया' की ख़बर सच साबित हुई

95वीं जयंती समारोह

समाजवादी राजनीति को गति देने के संकल्प के साथ

याद किए गए मधु लिमये

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

भारत में समाजवादी राजनीति के प्रमुख स्तम्भ रहे मधु लिमये की 95वीं जयंती 1 मई को मनाई गई. इस अवसर पर समाजवादी साहित्य न्यास ने यूनिटी आंफ प्रोगेसिव फोर्सेज के नाम से दिल्ली के कंस्टीट्यूशन क्लब में एक कार्यक्रम आयोजित किया. इस कार्यक्रम में समाजवादी राजनीति से जुड़े विभिन्न पार्टियों के नेताओं के साथ कांग्रेस और वाम दल के नेता भी शामिल हुए. वरिष्ठ टीवी पत्रकार कुर्बान अली ने कार्यक्रम में मंच संचालन किया. कार्यक्रम की शुरुआत प्रसिद्ध इतिहासकार इरफान हबीब के उद्बोधन से हुई. इरफान हबीब ने भारत में समाजवादी राजनीति के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला और उसमें मधु लिमये जी की भूमिका को रेखांकित किया. इरफान हबीब ने ये भी कहा कि ये सौभाग्य की बात है कि 1 मई मजदूर दिवस के साथ-साथ उस मधु जी की जयंती भी है, जिन्होंने आजीवन मजदूरों और वंचितों की लड़ाई लड़ी. मधु

लिमये जी के करीबी रहे रघु ठाकुर ने उन्हें याद करते हुए कहा कि वे एक सच्चे समाजवादी, सच्चे राष्ट्रभक्त और सच्चे नैतिक व्यक्ति थे. उन्होंने देशहित और जनहित में जिन सवालों को उठाया, उन्हें निष्कर्ष तक पहुंचाया. कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने वर्तमान समय में मधु लिमये जी के विचारों को आत्मसात करने की बात कही. बांग्लादेश की आजादी के लिए पाकिस्तान से युद्ध के समय इंदिरा गांधी को मधु जी के समर्थन का हवाला देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि मधु लिमये जी सदा ही मुद्दों और सरोकार की राजनीति के पक्षधर रहे.

दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर ने मधु लिमये के साथ अपनी दोस्ती और आंदोलन के दिनों में उनके साथ बिताए गए पलों को याद किया. उन्होंने कहा कि आज के समय में अगर मधु लिमये से कुछ सीखना हो, तो कथनी और करनी में अंतर मत लाइए. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मधु जी के करीबी रहे डीपी त्रिपाठी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में मधु जी जैसा विचारवान और बुद्धिजीवी नेता कोई नहीं हुआ. कम ही लोगों को पता होगा कि मधु जी को शास्त्रीय संगीत और नृत्य की भी अद्भुत समझ थी. उन्हें भारत की सांस्कृतिक विरासत में बहुत आस्था थी. डीपी त्रिपाठी ने कहा कि राजनीतिक विचारों में संस्कार का समावेश ही मधु जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने मधु जी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि छात्र जीवन में मुझे मधु लिमये जी ने बहुत प्रभावित किया. जब वे संसद में थे, तब मैं छात्र हुआ करता था. उन दिनों टीवी या रेडियो पर संसद की कार्यवाही का प्रसारण नहीं होता था, लेकिन अखबारों में टुडे इन पार्लियामेंट के नाम से एक पन्ने पर संसद की गतिविधियों के बारे में जानकारी होती थी. उसमें हर दिन मधु जी के बारे में कुछ न कुछ होता था. मैं संसद में कही गई मधु जी की बातों को जानने के लिए यो गौर से पढ़ता था. सीपीआई के नेता अतुल अंजान ने भी मधु जी से जुड़े कई प्रसंगों को याद किया. उन्होंने इसपर दुख जताया कि सक्रिय राजनीति से दूर होने के बाद जब वे पंडारा रोड में साधारण तरीके से रहने लगे तो उनसे मिलने आने वालों की संख्या कम हो गई, जबकि राजनीति में रहते हुए हर दिन सैकड़ों लोग उनसे मिलने आया करते थे. अतुल अंजान ने कहा कि जनहित और सरोकार के मामले में वे सोशलिस्ट भी थे और कम्युनिस्ट भी थे.

इस कार्यक्रम के मौके पर जदयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने भी मधु जी को याद किया. शरद यादव समाजवादी आंदोलन में मधु लिमये जी के साथी रहे हैं. दोहरी सदस्यता के सवाल पर जब मधु जी ने संसद से इस्तीफा दिया, तो शरद यादव ने भी उनका साथ दिया था. शरद यादव ने कहा कि आज जबकि देश में गाय, घर वापसी, लव जेहाद जैसे बिना मतलब के मुद्दों को तवज्जो दी जा रही है, आज अगर मधु जी होते तो मुखरता से इनका विरोध करते, न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि अपने लेखों और विचारों के द्वारा भी. जनहित और देशहित के मुद्दों पर उन्होंने हमेशा अपने सामर्थ्य से आगे जाकर लड़ाई लड़ी. शरद यादव ने कहा कि मधु जी को हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपनी साझा विरासत को बचाएं, लोकशाही और लोकतंत्र को बचाएं. कार्यक्रम के अंत में अपने अध्यक्षीय भाषण में समाजवादी नेता राजकुमार जैन ने मधु जी से जुड़े कई प्रसंगों को याद किया. उन्होंने कहा कि मधु जी ने भारत की आजादी के आंदोलन में शामिल होने के साथ-साथ नेपाल से राजशाही को खत्म करने के लिए भी संघर्ष किया. दिल्ली में नेपाल एम्बेसी के सामने प्रदर्शन करने के कारण उन्हें जेल में भी बंद होना पड़ा. गोवा आज आजाद है और भारत का हिस्सा है, इसमें सबसे बड़ा योगदान मधु जी का ही है. इन सबके अलावा मधु जी के साथी रहे सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष प्रो. प्रेम सिंह, बसपा नेता सुधींद्र भदौरिया, लोक दल के नेता त्रिलोक त्यागी, किसान नेता हरभजन सिंह सिद्धू, अशोक सिंह, कम्युनिस्ट नेता हन्नान मोल्लाह और कॉमरेड अमरजीत कौर ने भी मधु जी को याद किया. ■

कश्मीर में शांति के लिए व्हाइट अम्ब्रेला मार्च

सफ़ेद छातों के सहारे कश्मीर में शांति की मांग

हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि गोली-बारूद के जरिए कश्मीर मामले को नहीं सुलझाया जा सकता. बातचीत और मोहब्बत का हाथ बढ़ा कर ही समाधान निकाला जा सकता है. ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर के बिगड़ते हालात का प्रभाव सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही है, इससे देश के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ देश के बाहर भी भारत के बारे में गलत संदेश जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

कश्मीर के बिगड़ते हालात को बातचीत के जरिए सुलझाने की सरकार से मांग को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में 3 मई को एक कार्यक्रम आयोजित किया गया. लहर संस्था द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कई सामाजिक कार्यकर्ता, वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीर से जुड़े नेता शामिल हुए. इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए लहर के डायरेक्टर बसीर असद ने कहा, हम ये चाहते हैं कि कश्मीर के लोगों के साथ वार्तालाप शुरू की जाय और वहां के युद्ध जैसे हालात को खत्म किया जाय. हमारा मानना है कि अब बातचीत ही एकमात्र रास्ता है. सरकार से इसी मांग के लिए हम आज ये सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं. वहां फौज के जवान मारे जा रहे हैं,

मासूम बच्चे मर रहे हैं. दोनों तरफ से जो लोग मर रहे हैं, वे हमारे अपने ही हैं. इस सांकेतिक प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने भी बातचीत के जरिए कश्मीर मामले को सुलझाने पर बल दिया. उन्होंने कहा कि सरकार को इसपर विचार करने की जरूरत है कि कश्मीर के युवा हाथों में पत्थर उठाने पर क्यों मजबूर हुए. उन्होंने कहा कि बीते दिनों जब मैं कश्मीर गया, तो वहां के युवाओं का यही कहना था कि भारत सरकार कश्मीर से संबंधित सभी पक्षों से बात कर के इसका रास्ता निकाले. सामाजिक कार्यकर्ता शबनम हाशमी ने कहा, हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि गोली बारूद के जरिए कश्मीर मामले को नहीं सुलझाया जा सकता. बातचीत और मुहब्बत का हाथ बढ़ा कर ही समाधान निकाला जा सकता है. ऐसा भी नहीं है कि कश्मीर के बिगड़ते हालात का प्रभाव सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक ही है, इससे देश के दूसरे हिस्सों के साथ-साथ देश के बाहर भी भारत के बारे में गलत संदेश जा रहा है. इस प्रदर्शन में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा और विनोद शर्मा के साथ-साथ कश्मीर के कम्युनिस्ट नेता यूसुफ तारिगामी और कई अन्य नेता व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए.■

बड़े बदलाव जल्दबाज़ी में नहीं होते

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मुलायम सिंह यादव ने बयान दिया है कि वे एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं. शिवपाल सिंह यादव ने भी यही बात कही है. समाजवादी पार्टी कई बार उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज़ रही है. 2012 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया. चुनाव के मौके पर अखिलेश यादव को लगा कि वे बहुत लोकप्रिय हैं. परिवार में दरार आ गया और उसके बाद चुनाव के जो नतीजे आए, वो सबके सामने हैं. उम्र के इस पड़ाव पर यदि मुलायम सिंह यादव नई पार्टी बना रहे हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है. शिवपाल सिंह उनके साथ हैं. वे संगठन के आदमी हैं. पार्टी के कार्यकर्त्ता उनके साथ हैं. यादव समाज के लोग और समाजवादी सोच के लोग उनके साथ हैं. लिहाज़ा, ऐसा नहीं होगा कि इसका कोई प्रभाव न हो, इसका कुछ न कुछ प्रभाव ज़रूर होगा. लेकिन इससे विपक्ष का वोट बंटेगा और इसका सीधा फायदा भाजपा को होगा. सभी विपक्षी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला कर महागठबंधन बनाने की बात चल रही है. नीतीश कुमार इसके लिए कोशिश कर रहे हैं. अन्य लोग भी कोशिश कर रहे हैं. राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोनिया गांधी सबसे बात कर रही हैं. यदि ऐसी स्थिति में वे दूसरी पार्टी बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं है. बहरहाल, हम बहुदलीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं. यहां हर व्यक्ति अपनी पार्टी बनाने के लिए आज़ाद है. इसलिए मुलायम सिंह यादव भी अपनी पार्टी बना सकते हैं. लेकिन बहुत अच्छा होता, यदि अखिलेश अपने पिता और चाचा से बात करते और किसी समझौते पर पहुंचते. पार्टी अपने आप को मज़बूत करती और अगले चुनाव की तैयारी करती. देखते हैं, क्या होता है.

दूसरा मुद्दा है, आधार कार्ड का. जब कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आधार कार्ड जारी करने की शुरुआत की थी, तो इस पर विवाद हुआ. तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, खास तौर पर अरुण जेटली ने इसका ज़बर्दस्त विरोध किया था. व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठा करने का काम तानाशाही और सैनिक शासन में होता है. इंग्लैंड में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन उसे जल्द ही रोक दिया गया, क्योंकि उस कार्ड का फायदा कम नुकसान ज्यादा था. सरकार में आने के बाद भाजपा ने आधार को और मज़बूत कर दिया. नंदन निलेकणि की बात तो मैं समझ सकता हूं, क्योंकि वे इससे पैसा हासिल कर रहे हैं. जब मोदी पेटीएम की बात करते हैं या किसी अन्य डिवाइस की बात करते हैं, तो उसमें पैसा लगता है. केवल कैश के आदान-प्रदान में पैसा नहीं लगता. कार्ड द्वारा हर लेन-देन में पैसा लगता है. उसी तरह आधार कार्ड के कई खतरे हैं. इस कार्ड में आपके बायोमेट्रिक डाटा हैं, फिंगर प्रिंट्स हैं, आंखों की पुतली की तस्वीर है. कोई एक बटन दबाएगा, आपकी हर जानकारी उसके पास होगी. मान लीजिए, यदि मेरे पास आधार कार्ड है, तो मेरी हर जानकारी एक बटन दबाने से हासिल की जा सकती है. ये अच्छी बात हो सकती है, लेकिन यह खतरनाक भी है. यदि आधार का डाटा किसी ने चुरा लिया, तो बिना किसी परिश्रम के एक ही जगह से सारी जानकारियां हासिल कर लेगा. लिहाज़ा, इसे लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है. मैं मोदी और उनके कैबिनेट के जोश को समझ सकता हूं, क्योंकि वे दिखाना चाहते हैं कि वे कार्यकुशल और बहुत अच्छे हैं. यदि सुप्रीम कोर्ट सावधानी बरतने की बात करता है, तो सावधानी बरती जानी चाहिए. ये रिपोर्ट आ रही है कि 13 करोड़ लोगों के डाटा चुराए जा चुके हैं. 13 करोड़ तो दुनिया के अधिकतर देशों की आबादी भी नहीं है और 13 करोड़ हमारी जनसंख्या का भी 10 प्रतिशत है. सरकार को एक समिति बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. चाहे संसदीय समिति हो, स्थायी समिति हो या सर्वदलीय समिति हो, आधार कार्ड पर गहराई से विचार होना चाहिए. मैंने अखबार में पढ़ा था कि एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा. मैं देश के उन लोगों में से एक हूं, जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है. इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं फ्लाइट से कहीं नहीं जा सकता. यह बहुत हास्यास्पद चीज़ है. यदि मेरे पास पासपोर्ट है, तो क्या पासपोर्ट दिखा कर मैं एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता? मैं दुनिया भर की यात्रा अपने पासपोर्ट पर कर सकता हूं. इन सारी चीज़ों के नकारात्मक दूरगामी प्रभाव हैं. इनमें कुछ भी सकारात्मक नहीं है. आधार से क्या हासिल होने जा रहा है? पहले उन्होंने कहा कि सरकारी लाभ के लिए आधार की जरूरत है, जैसे एलपीजी या राशन सब्सिडी आदि. मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर मुझे आधार कार्ड की क्या ज़रूरत है? मैं सरकार को टैक्स अदा कर रहा हूं. अब वे कह रहे हैं कि टैक्स अदा करने के लिए भी आधार कार्ड की ज़रूरत होगी. मुझे नहीं लगता कि इस पर सरकार की सोच सही है. सरकार को आधार पर अवश्य ही पुनर्विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने भी पुनर्विचार की बात कही है.

ये रिपोर्ट आ रही है कि 13 करोड़ लोगों के डाटा चुराए जा चुके हैं. 13 करोड़ तो दुनिया के अधिकतर देशों की आबादी भी नहीं है और 13 करोड़ हमारी जनसंख्या का भी 10 प्रतिशत है. सरकार को एक समिति बनाने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए. चाहे संसदीय समिति हो, स्थायी समिति हो या सर्वदलीय समिति हो, आधार कार्ड पर गहराई से विचार होना चाहिए. मैंने अखबार में पढ़ा था कि एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल होगा. मैं देश के उन लोगों में से एक हूं, जिन्होंने आधार कार्ड नहीं बनवाया है.

तीसरा बिन्दु है, नीति आयोग. स्वदेशी जागरण मंच, जो आरएसएस का एक सहयोगी है, ने एक बयान दिया है कि नीति आयोग राष्ट्र विरोधी है, नीति आयोग के सुझाव राष्ट्र विरोधी हैं. नीति आयोग ऐसी चीजों का सुझाव दे रहा है, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हित में हैं. मुझे ख़ुशी है कि आरएसएस के अन्दर से किसी ने अपनी बात रखी. बेशक, ये बातें मोदी को पसंद नहीं आएंगी. हो सकता है कि इन लोगों को खरी-खोटी भी सुननी पड़े. अरविंद पनगढ़िया नीति आयोग के मुखिया हैं. वे अमेरिका से आए हैं, शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से. उनके विचार अमेरिकन हैं. उन्हें भारत से कोई लेना-देना नहीं है. योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन ही एक बुरा विचार था. मैंने हाल में कहीं पढ़ा कि नीति आयोग उत्तर प्रदेश सरकार को उसकी नीतियों पर सलाह देने जा रही है. ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण बात है! ऐसा करने के लिए नीति आयोग से किसने कहा, किसने ये अधिकार दिया? ये एक केन्द्रीय थिंक टैंक है. इसका राज्य सरकार से कोई लेना देना नहीं है. राज्य सरकार के अपने योजना बोर्ड हैं. लेकिन अभी ऐसा लगता है कि हर चीज अराजकता की स्थिति से गुजर रही है. नरेंद्र मोदी बहुत जल्दबाजी में हैं और वे दिखाना चाहते हैं कि वे भारत को बदल सकते हैं. जो बदलाव सत्तर साल में नहीं हुए, वे उस बदलाव को सात साल में कर देना चाहते हैं. नरेंद्र मोदी एक नेक नीयत व्यक्ति हैं, वे भ्रष्ट नहीं हैं, लेकिन उनके पास विचारों की कमी है. वे बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति नहीं हैं. उन्होंने काफी विदेश यात्राएं की हैं. आरएसएस ने भी देश के हर गांव की यात्राएं की है. इतनी यात्राएं करने के बाद मोदी ने नोटबंदी की घोषणा कर दी. उन्होंने सोचा कि इससे लोगों को मदद मिलेगी, लेकिन कैसे? उन्हें भी मालूम था कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है. ठीक है कि नोटबंदी का मामला अब खत्म हो चुका है. यह अब कोई मुद्दा नहीं है. जितनी जल्दी हो एक थिंक टैंक का गठन करना चाहिए, भले ही उस में आरएसएस के लोग हों. इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि यह आपकी सोच के मुताबिक है. आखिर लोगों ने आपको चुना है. यदि आप कांग्रेस के लोगों को नहीं रखना चाहते हैं, मत रखिए, अपने लोगों को रखिए. लेकिन गहराई से सोचने की आवश्यकता है. बिना सोच-विचार के प्रतिदिन लोगों के ऊपर आप नीतियां थोप रहे हैं. कल अरुण जेटली ने घोषणा की कि कैबिनेट ने एक अध्यादेश को स्वीकृति दी है, ताकि बैंकिंग रिवॉल्यूशन एक्ट को संशोधित किया जा सके और बैंक को ये अनुमति दी जा सके कि वे एनपीए के मामले को रफा-दफा कर सकें. इस काम के लिए अध्यादेश की क्या जरूरत थी? बैंक के चेयरमैन को ये अधिकार है. लेकिन आपको एक कवर की ज़रूरत है, ताकि बड़े लोगों को दिए गए बड़े ऋण को माफ़ किया जा सके. आप इसे कानूनी सुरक्षा देना चाहते हैं. देश की अर्थव्यवस्था के लिए ये चीज़ें सही संकेत नहीं हैं. ये ठीक है कि अरुण जेटली एक कॉरपोरेट वकील हैं और इन चीजों को बेहतर समझते हैं. एक तरफ तो आप आईडीबीआई के चेयरमैन को इसलिए गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में लोन दिया था. आपने सभी चेयरमैन को डरा दिया और अब उनकी सुरक्षा के लिए एक कानून ला रहे हैं. मेरे मुताबिक, मोदी सरकार ने पहले समस्या पैदा करने और फिर बाद में उसका समाधान खोजने में विशेषज्ञता हासिल कर ली है. यदि वे देश को वैसे ही चलने दें, जैसे चलना चाहिए, तो बेहतर होगा. हमें ऐसी आशा करनी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

नाज़ुक दौर में भाजपा-पीडीपी गठबंधन

शुजात बुख़ारी

हालांकि अभी सब कुछ साफ़ नहीं है, लेकिन जम्मू और कश्मीर की गठबंधन सरकार का भविष्य तय लगता है. वहां पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का गठबंधन भले ही अभी खत्म न हुआ हो, लेकिन मार्च 2015 (जब से यह गठबंधन बना है) से आज तक इन दोनों के बीच तालमेल का आभाव रहा है. पीडीपी के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने खुद इस गठबंधन को उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का गठबंधन कहा था, जिसके कारण उनके विरोधियों को इसे अपवित्र गठबंधन कहने का मौक़ा मिल गया. मुफ्ती का एकमात्र तर्क यह था कि वे उस जम्मू को अलग-थलग नहीं करना चाहते थे, जिसने भाजपा को 36 सीटों में से 25 सीटें दी थी. पीडीपी को कश्मीर घाटी से 25 सीटें और जम्मू के मुस्लिम-बहुल पीर पंजाल क्षेत्र से तीन सीटें मिली थीं. लिहाज़ा, मुफ्ती का मानना था कि राज्य को एकजुट रखने के लिए, सरकार बनाने का यही एकमात्र तरीका था. अब दो साल बाद, ऐसा लगता है कि राज्य तो एकजुट है, लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर और शक्तिहीन हो गया है.

24 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तभी से इस सरकार के भविष्य पर अटकलें लगनी शुरू हो गईं थीं. इस मुलाक़ात का मकसद कश्मीर के हालात पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित कराना और बीतचीत के दरवाज़े खोलने के महत्त्व पर जोर देना था. लेकिन मुलाक़ात के बाद उन्होंने मीडिया से जो कुछ भी कहा, उससे इसका कोई संकेत नहीं मिला कि उन्हें केन्द्र सरकार से ऐसा कोई आश्वासन मिला हो. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि स्थिति को ठीक करने के लिए अगले दो से तीन महीने का समय काफी महत्वपूर्ण है. उनकी या उनकी पार्टी की तरफ से किसी भी स्पष्टीकरण के अभाव में, यह समझना मुश्किल है कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन बातचीत की भाषा बता रही है कि आने वाले समय में ये गठबंधन राजनीतिक परिदृश्य में एक संभावित बदलाव की दिशा में आगे बढ़ रहा हैं. भाजपा ने अपने गठबंधन साथी के साथ मतभेदों को ज्यादा महत्व नहीं दिया और ये धारण बनी कि भले ही गठबंधन की यात्रा थोड़े उबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर रही हो, लेकिन फिर भी यात्रा ठीक से चल रही है.

बहरहाल, जब महबूबा श्रीनगर लौटीं, तो उन्होंने अपनी पार्टी की दो महत्वपूर्ण बैठकें बुलाईं. पहली कोर समूह (जिसमें वरिष्ठ नेता और मंत्री शामिल थे) और दूसरी विधायकों की. अगर इन बैठकों में शामिल होने वाले लोगों के आकलन को सही माना जाए, तो पीडीपी इस गठबंधन को ले कर असहज है. इस असहजता का आधार भाजपा का व्यवहार है. महबूबा कश्मीर मसले के लिए बातचीत का रास्ता चाहती हैं. इन लोगों के मुताबिक महबूबा ने ये कहा कि अगर ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाता है, तो वे मुख्यमंत्री का पद त्याग देंगी. बैठक में पार्टी असहाय और निराश दिखी. हालांकि, श्रीनगर संसदीय सीट के लिए हाल ही में हुए उप चुनाव में सबसे कम मतदान, मुख्यधारा के दलों की दयनीय स्थिति को दर्शाता है. ये यह भी दर्शाता है कि उस वक्त प्रशासनिक रूप से स्थिति कितनी खराब थी.

गठबंधन के पहले दिन से ही भाजपा ने अपने साथी को बदनाम करना शुरू कर दिया था. जब मुफ्ती ने अलगाववादियों के बारे में बात की और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने में पाकिस्तान की सराहना की, तब भाजपा ने उन पर हमला किया. उन्हें उस मसरत आलम को दुबारा जेल भेजने पर मजबूर किया गया, जो 2010 के आंदोलन का चेहरा था. उसकी रिहाई पर संसद में काफी शोर-शराबा भी हुआ था. 7 नवंबर, 2015 को जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नीचा दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है, इसे लेकर मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है.

राजनीतिक परिदृश्य पर पीडीपी का उदय अभूतपूर्व था. लोगों के साथ जुड़ना और यहां तक कि अलगाववादियों के स्पेस में दाखिल होना, ऐसी वजहें रहीं जिसने नेशनल कांफ्रेंस जैसी पुरानी पार्टी के मुकाबले पीडीपी को एक प्रमुख राजनैतिक ताकत बना दिया. राज्य की हिंसा से पीड़ित लोगों के साथ सहानुभूति दिखाने का काम मुख्यधारा के दलों ने पहले नहीं किया था. यह महबूबा ही थीं, जो राज्य के दमन से पीड़ित लोगों की आवाज़ के रूप में उभर कर सामने आईं और अलगाववादियों के जनसमर्थ में सेंध लगाने में कामयाब हुईं थीं. लेकिन जैसे ही पीडीपी ने भाजपा के साथ गठबंधन किया, उसका ग्राफ एकदम से नीचे चला गया. भाजपा कश्मीर के हितों के विरूद्ध रहने वाली एक पार्टी के रूप में जानी जाती थी. भाजपा कश्मीर की किसी मुख्यधारा की पार्टी की सहायता से ही सत्ता में आ सकती थी. मुफ्ती ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके विशाल जनादेश पर बहुत विश्वास किया और गठबंधन कर लिया. एक तरह से उन्होंने मोदी और उनके दृष्टिकोण पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया. मोदी सरकार की कश्मीर नीति एक खास मानसिकता के जरिए बनाई गई है, जहां कश्मीर उनके लिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक मसला है. मोदी केवल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इंसानियत, कश्मीरियत और जम्हूरियत की बात करते हैं, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते.

गठबंधन के पहले दिन से ही भाजपा ने अपने साथी को बदनाम करना शुरू कर दिया था. जब मुफ्ती ने अलगाववादियों के बारे में बात की और विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण कराने में पाकिस्तान की सराहना की, तब भाजपा ने उन पर हमला किया. उन्हें उस मसरत आलम को दुबारा जेल भेजने पर मजबूर किया गया, जो 2010 के आंदोलन का चेहरा था. उसकी रिहाई पर संसद में काफी शोर-शराबा भी हुआ था. 7 नवंबर, 2015 को जब उन्होंने पाकिस्तान के साथ बातचीत की वकालत की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें नीचा दिखाते हुए कहा कि पाकिस्तान से कैसे निपटना है, इसे लेकर मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है. मोदी जब कश्मीर दौरे पर गए, तो मुफ्ती ने वहां उनके लिए भारी भीड़ का इंतजाम किया था. कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कश्मीरी लोग क्रिकेट स्टेडियम में मोदी के लिए लाइन लगा कर खड़े होंगे. मुफ्ती बातचीत और सुलह चाहते थे, लेकिन मोदी उस चीज को पहचान नहीं सके.

हालांकि, दोनों पार्टियां एजेंडा ऑफ एलायंस के आधार पर सत्ता में आईं. लेकिन पिछले दो सालों में केवल भाजपा और इसके घोषणापत्र से संबंधित मुद्दे ही क्रियान्वित हुए. जैसे, पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की पहचान, कश्मीर के दूसरी तरफ से आए शरणार्थियों के पुनर्वास और कश्मीरी पंडितों के लिए राहत उपाय इत्यादि. भाजपा ने पीडीपी के साथ जिन महत्वपूर्ण राजनैतिक मुद्दों पर सहमति जताई थी, उनको नहीं छुआ गया या उन्हें नकार दिया गया. उदाहरण के लिए, पाकिस्तान और हुर्रियत पर एजेंडा ऑफ एलायंस में लिखा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ सम्बंधों को सामान्य करने के लिए कई कदम उठाए हैं. गठबंधन सरकार सुलह का वातावरण बनाने और उप-महाद्वीप के भीतर शांति और विकास के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण और पहलों को समर्थन देगी और उसे मजबूत करने की कोशिश करेगी. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने 'इंसानियात, कश्मीरियत और जम्हूरियत' की भावना के तहत हुर्रियत समेत सभी राजनीतिक समूहों के साथ संवाद प्रक्रिया शुरू की थी. एजेंडा ऑफ एलायंस में भी इन्हीं सिद्धांतों के मुताबिक, सभी आंतरिक हितधारकों (सभी राजनीतिक दल, विभिन्न विचारधारा वाले समूहों) के साथ निरंतर और सार्थक बातचीत शुरू करने की बात कही गई है. कहा गया है कि बातचीत के जरिए जम्मू-कश्मीर के सभी मुद्दों के समाधान के लिए आम सहमति बनाने की कोशिश की जाएगी. इसलिए महबूबा आज जो पूछ रही हैं, वह एजेंडा ऑफ एलायंस के ढांचे के भीतर है.

इस निरंतर अस्वीकृति को देखते हुए जाहिर है, महबूबा पर दबाव बढ़ता जा रहा है. जो सरकार चुनाव नहीं करवा सकती है, उसके पास कानून और व्यवस्था की बहाली के लिए कोई जादुई तरीका तो नहीं ही होगा. एक तरफ महबूबा भाजपा की वजह से परेशान हैं, तो वहीं खुद उनकी पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. गुटबाजी हावी है. अगर दिल्ली की रिपोर्टों पर भरोसा किया जाए, तो आज (जैसा कि 2016 की शुरुआत में) अगर महबूबा गठबंधन तोड़ती हैं या इस्तीफा देती हैं, तो उनकी पार्टी के कुछ सदस्य भाजपा को सरकार चलाने में अपना समर्थन देने के लिए तैयार हैं. लेकिन पार्टी के भीतर मजबूत संदेश ये है कि महबूबा दिल्ली को बताएं कि वे अपने राजनीतिक एजेंडे से समझौता नहीं करेंगी, क्योंकि पार्टी पहले से ही एक स्तर पर बदनाम हो चुकी है. यदि महबूबा कोई कदम उठाती हैं, तो जाहिर है ये भाजपा के लिए नुकसान होगा और भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी. तब राजनैतिक मुद्दे को अस्वीकार करना दोनों के लिए महंगा साबित हो सकता है. ■

-लेखक राइजिंग कश्मीर के संपादक हैं.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

अब सर्वोच्च नहीं रहा सर्वोच्च न्यायालय

सुप्रीम कोर्ट ताक़तवर है या भारत सरकार, इसका पता बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है. समय-समय पर ऐसे मौके आते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और संसद में तकरार होती है कि संसद प्रमुख है या सुप्रीम कोर्ट. यह बात तो समझ में आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद भी अगर सरकार लगातार क़दम उठाती चली जाए और सुप्रीम कोर्ट को अनदेखा करे, तब यह समझ में आता है कि सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट की बातों को न केवल अनदेखा कर रही है, बल्कि अमान्य भी कर रही है.

आधार कार्ड का मसला बिल्कुल ऐसा ही है. जब मनमोहन सिंह की सरकार ने आधार कार्ड को लागू किया, तभी से यह आलोचना का विषय बना हुआ है. सुप्रीम कोर्ट इस सवाल पर सुनवाई दर सुनवाई करती जा रही है. उसने यह आदेश दिया कि जब तक इसका फैसला न हो जाए, तब तक आधार कार्ड अनिवार्य न किया जाए. मनमोहन सिंह के ज़माने में जो ढीठता शुरू हुई, वो आज तक जारी है. मनमोहन सिंह ने आधार कार्ड क्यों अनिवार्य किया, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर यह टिप्पणियां की हैं कि आधार कार्ड निजता का उल्लंघन करता है. दरअसल अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को एक मज़बूत बाजार के आधार का निर्माण करने के लिए इस पूरी योजना को लागू किया गया. जितनी जानकारी सरकार आधार कार्ड के ज़रिए अपने पैसे खर्च करके इकट्ठा कर रही है, वो सारी जानकारी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे रही है, जिससे वो पैसा कमा रही हैं. इस सारी जानकारी को देने के एवज़ में भारत सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है. हां, उन लोगों को ज़रूर मिल रहा होगा, जिन्होंने इसका फैसला लिया. नन्दन निलेकणि इस योजना के जनक रहे हैं.

जब आधार कार्ड लागू हुआ था, तब आज के प्रधानमंत्री और तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरजते, चिंघाड़ते हुए यह घोषणा की थी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो आधार कार्ड को वाइड-अप करेगी यानि उस पूरी योजना को समेट लेगी. मनमोहन सिंह हारे, नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री बने, लेकिन आधार कार्ड चलता रहा. वित्तमंत्री अरुण जेटली के साथ नन्दन निलेकणि की दो घंटे की मीटिंग हुई और भारत सरकार फौरन अपने प्रधानमंत्री के सार्वजनिक रूप से किए गए वादे को भूल गई. इसके बाद प्रधानमंत्री इस योजना को और ज्यादा मज़बूती के साथ लागू करने की बात करने लगे. वैसे तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बहुत सारे वादों को भुलाया, उन्हें जुमला कह दिया, उनका जिक्र करना भूल गए, लेकिन आधार एक ऐसा मसला है जिसने भारत के हर नागरिक की जानकारी को प्लेट पर रखकर अमेरिका को सौंप दिया है. यह जानकारी अमेरिका की व्यापारिक कंपनियों के बाद सीआईए के पास पहुंच गई और उस जानकारी को भारत के दुश्मनों के हाथ बेचने का रास्ता खुल गया.

> **सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सरकार नहीं मान रही है. सरकार अपनी गति से आधार कार्ड को हर चीज़ से जोड़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट चुप है. सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पर सबूत पेश हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का खुला उल्लंघन होने पर भी किन वजहों से चुप है, यह समझ में नहीं आ रहा. चारों तरफ अफवाहें हैं कि इसी आधार कार्ड की जानकारी का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमज़ोर नसें न केवल भारत सरकार के खुफिया महकमे ने अपनी मुट्ठी में जकड़ ली हैं, बल्कि विदेशी शक्तियों ने भी उन कमज़ोरियों को अपनी फाइलों में कैद कर लिया है. इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जो छोटी-छोटी बातों पर दहाड़ता है, अपनी इतनी बड़ी अवमानना होते हुए, अपने फैसलों का उल्लंघन होते हुए देखकर भी खामोश है. ये बात बहुत चिंताजनक है.**

सुप्रीम कोर्ट ने फिर रोक लगाई कि इसे अनिवार्य न किया जाए, लेकिन भारत सरकार ने इस कार्ड को उतना अनिवार्य कर दिया कि अगर किसी ने ग़लती से आधार के साथ अपने बैंक अकाउंट को नहीं जोड़ा या उसकी जानकारी नहीं दी तो बैंकों ने बैंक खाते का इस्तेमाल करने से ही रोक दिया. आधार को लेकर जितनी चिंताएं सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, उतनी चिंता इस देश के मंत्री और पत्रकार नहीं कर रहे हैं.

आधार कार्ड इतना ख़तरनाक है कि अगर यह जानकारी साम्प्रदायिक दंगा फैलाने वालों के हाथों में पहुंच जाए, तो वो एक-एक को चुनकर जिसे भी मारना चाहें, उसे मार सकते हैं. आधार कार्ड में आंखों का रंग, रक्त ग्रुप, व्यक्ति का अपना चेहरा, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर यानि व्यक्ति की निजी जासूसी के जितने रहस्य हैं, वो सब आधार के ज़रिए हमारे दुश्मनों, विदेशियों और व्यापारिक संस्थानों के हाथों बंधक बने हुए हैं. ये इतनी खतरनाक जानकारी है कि अगले आठ साल में कौन व्यक्ति भारत का मुख्य न्यायाधीश बन सकता है, कौन व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है, कौन व्यक्ति राजनीतिक तौर पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकता है. इतना ही नहीं, कौन लोग भारत की राजनीति और व्यापार को नियंत्रित कर सकते हैं, इन सबका विश्लेषण वो लोग जो सारी दुनिया पर बाजार के माध्यम से क़ब्जा करना चाहते हैं या वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं और चिन्हित कर हमारे ऊपर दबाव डाल सकते हैं या ऐसे सारे व्यक्तित्वों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाकर अपना मानसिक गुलाम बना सकते हैं, हम इस ताक़त को दूसरों को दे रहे हैं. सेना में कौन-कौन ऐसे लोग हैं, जो रणनीति बनाने में सक्षम हैं, कौन ऐसे हैं जो युद्ध करने में सक्षम हैं? वायु सेना, थल सेना, जल सेना इन सबको नियंत्रित करने वाले लोगों को किस तरीके से प्रभाव क्षेत्र में लिया जा सकता है, ये सब जानकारी हम उनके हाथों में दे रहे हैं, जो हमें व्यापारिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभाव क्षेत्र में लेने की ताक़त रखते हैं.

अभी एक बड़े उद्योगपति द्वारा जारी किए गए कार्ड बनाने का ज़िम्मा लेते ही 13 करोड़ लोगों की जानकारियां सार्वजनिक हो गईं. ख़बरें बता रही हैं कि इसके पीछे रिलायंस जियो का हाथ है. 13 करोड़ लोगों की जानकारियां बिना उनकी अनुमति के ज़बरदस्ती संपूर्ण विश्व को लीक करने का काम रिलायंस जियो ने किया. यही ख़तरा बार-बार सुप्रीम कोर्ट बताता रहा है और इसी ख़तरे को लेकर वो सुनवाई कर रहा है.

लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला सरकार नहीं मान रही है. सरकार अपनी गति से आधार कार्ड को हर चीज़ से जोड़ती जा रही है और सुप्रीम कोर्ट चुप है. सुप्रीम कोर्ट के सामने सबूत पर सबूत पेश हो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश का खुला उल्लंघन होने पर भी किन वजहों से चुप है, यह समझ में नहीं आ रहा. चारों तरफ अफवाहें हैं कि इसी आधार कार्ड की जानकारी का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की कमज़ोर नसें न केवल भारत सरकार के खुफिया महकमे ने अपनी मुट्ठी में जकड़ ली हैं, बल्कि विदेशी शक्तियों ने भी उन कमज़ोरियों को अपनी फाइलों में कैद कर लिया है. इसीलिए वो सुप्रीम कोर्ट जो छोटी-छोटी बातों पर दहाड़ता है, अपनी इतनी बड़ी अवमानना होते हुए, अपने फैसलों का उल्लंघन होते हुए देखकर भी खामोश है. ये बात बहुत चिंताजनक है. क्या इसके पीछे भारत के वित्तमंत्री अरुण जेटली या स्वयं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं या इसके पीछे सारी दुनिया की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हिन्दुस्तान में एकमात्र प्रतिनिधि नन्दन निलेकणि हैं. नन्दन निलेकणि इन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठते हैं, इसका मतलब वो देश के उन चन्द सर्वशक्तिशाली व्यक्तियों में हैं, जो देश के बारे में फैसले लेते हैं. क्या प्रधानमंत्री कार्यालय ये तय कर चुका है कि वो देश के सारे लोगों की निजता को चौराहे पर नीलाम करेगा और दूसरी तरफ़ सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के आधार कार्ड से संबंधित किसी भी बात पर ध्यान नहीं देगा और अपनी योजना पर काम करता रहेगा.

सबसे बड़ा सवाल कि इस सवाल को मीडिया, विपक्षी दल, क़ानून के बड़े-बड़े भाष्यकार उठाने में न केवल हिचक रहे हैं बल्कि डर भी रहे हैं. इसलिए हमें उस स्थिति के लिए तैयार होना चाहिए कि अब अगर सरकार कुछ भी करेगी तो सुप्रीम कोर्ट जुबानी भले ही उसे रोकने की कोशिश करे, पर उसकी बात अब भविष्य में सरकार मानेगी ही, इसकी कोई गारंटी नहीं है. यह फैसला लगभग हो चुका है कि अब लड़ाई संसद या सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता की नहीं है, बल्कि भारत सरकार सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च नहीं है, शायद अब यह साफ़ हो गया है.■

editor@chauthiduniya.com

आर या पार

गायों की गिनती, इंसानों की हत्या

परंजय गुहा ठाकुरता

एक अप्रैल को अलवर में पशुपालन करने वाले किसाना 55 वर्षीय पहलू खान को दिनदहाड़े भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला. कुछ लोग इस भीड़ को गोरक्षा समूह का नाम दे रहे हैं. उनकी मौत गौरक्षा के नाम पर हो रही हत्याओं की सूची में एक और नाम जोड़ने वाली है. इसकी शुरुआत अक्टूबर, 2015 में दिल्ली से सटे दादरी में मोहम्मद अख़लाक की हत्या से हुई थी. उस वक्त से लेकर अब तक भारत की गाय पट्टी में मानवाधिकारों पर गाय के अधिकार वरीयता हासिल करते जा रहे हैं. क्योंकि गौ रक्षा के नाम पर पशुओं की आवाजाही का पता लगाकर चुनिंदा तरीके से या तो मुसलमानों को पीटा जा रहा है या दलितों को. जब यह सब होता है कि कानून लागू करने वाले तमाशा देखते रहते हैं. इसमें भी सबसे बुरा पक्ष यह है कि प्रभावित को ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है और हमला करने वालों को अनाम व्यक्ति कहकर छोड़ दिया जा रहा है.

अखलाक की हत्या के बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गाय पर आक्रामक राजनीति की जा रही है. इन राज्यों में से कर्नाटक को छोड़कर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें पशु रक्षा कानूनों में बदलाव की मांग की गई है. महाराष्ट्र में इस संबंध में 1976 का जो कानून है उसमें गौ रक्षा के नाम पर अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के छूट जाने की व्यवस्था है. जिन छह राज्यों का जिक्र इस याचिका में किया गया है, उनके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में भी गौरक्षा के नाम पर हिंसा के मामले सामने आए हैं. इनमें से आखिरी के दो राज्यों में हुई घटना के वीडियो भी हैं. पहलू खान पर हमले के वीडियो भी हैं. ये दिखाते हैं कि किस निर्ममता से भीड़ हमले कर रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है. जम्मू कश्मीर के रियासी जिले का वीडियो हृदयविदारक है. इसमें एक मां भीड़ से अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही है जबकि भीड़ उनके गौपालन के अस्थाई ढांचे को तहस-नहस कर रही है.

> **अखलाक की हत्या के बाद गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में गाय पर आक्रामक राजनीति की जा रही है. इन राज्यों में से कर्नाटक को छोड़कर हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है. सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसी जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही है जिसमें पशु रक्षा कानूनों में बदलाव की मांग की गई है. महाराष्ट्र में इस संबंध में 1976 का जो कानून है उसमें गौ रक्षा के नाम पर अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के छूट जाने की व्यवस्था है.**

किसी भी सभ्य समाज में ये घटनाएं गुस्से को जन्म देंगी. लेकिन भारत में जब भी इनके खिलाफ आवाज उठी है तो अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, बल्कि इन घटनाओं को बढ़ावा देने का ही काम हो रहा है. अलवर की घटना के बाद राजस्थान के भाजपा विधायक ज्ञान देव ने कहा कि उन्हें इस घटना पर कोई अफसोस नहीं है. जबकि राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने सदन में कहा कि खान पशुओं की तस्करी करते थे. राजस्थान के पुलिस प्रमुख ने ही जो बातें कहीं उससे पता चलता है कि कटारिया झूठ बोल रहे थे. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की चुप्पी तब टूटी जब राज्यसभा में इस पर काफी हंगाम हुआ और 21 पूर्व नौकरशाहों ने कड़ा बयान जारी किया. क्या ऐसे नापाक गठजोड़ और दोहरे रवैये के दौर में क्या खान जैसे आम लोगों या उनके परिजनों के लिए न्याय की कोई संभावना है?

भले ही गाय हिंदुत्व की राजनीति के केंद्र में हो लेकिन मूल मुद्दा गाय नहीं है. दरअसल, गाय की इतनी अहमियत है कि सरकार आधार की तरह ही एक पहचान संख्या इनके लिए जारी करने वाली है. इसके लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की एक समिति ने रिपोर्ट भी दी है. इसमें कहा गया है कि बांग्लादेश को होने वाली पशुओं की अवैध तस्करी को रोकने का रास्ता यही है. अगर सॉलिसिटर जनरल से यह सूचना उच्चतम न्यायालय में खुद नहीं दी होती तो हम सब इस सूचना को झूठी खबर मानकर खारिज कर देते.

यह सरकार की चुनिंदा न्याय की नीति को दिखाता है. जहां कानून का क्रियान्वयन उसके अनुकूल हो, वहां इसे सख्ती से लागू किया जाता है. कश्मीर में भारत सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर करने वाले नौजवानों के खिलाफ कानून का पालन कड़ाई से किया जा रहा है. लेकिन गौरक्षा के नाम पर लोगों को मौत के घाट उतार रहे लोगों पर कानून खामोश है. राजस्थान की एक प्रमुख गौरक्षक साध्वी कमल दीदी ने तो गौरक्षकों की तुलना खुलेआम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद से कर डाली.

यह सरकार के एकपक्षीय होकर काम करने का उदाहरण है. सरकार को अल्पसंख्यकों की राय की कोई चिंता नहीं है. यह देश में लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरनाक है. हमें पहले से ही बिखरे हुए समाज को और तोड़ने के लिए सांप्रदायिक दंगों की जरूरत नहीं है. लेकिन हम गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसक घटनाओं से लगातार उस ओर बढ़ रहे हैं. अलवर, दिल्ली, दादरी, लातेहार, उना, सोनीपत, मंदसौर और देश के किसी अन्य हिस्सों में होने वाली घटनाएं महज संयोग नहीं हैं. ये घटनाएं नरेंद्र मोदी के उस नए भारत का हिस्सा हैं, जहां एक पवित्र गाय इंसानी जीवन से ज्यादा अहम है.■

(लेखक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के संपादक हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

सहारनपुर और आगरा की घटनाओं से कानून व्यवस्था पर उठे सवाल

अपनों से ही बेज़ार हो रहे योगी

दीनबंधु कबीर

योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर तमाम कवायद शुरू हो गई. एंटी रोमियो स्क्वायड के गठन से लेकर एसपी के दफ्तरों में अलग से एफआईआर सेल खोले जाने और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायतें देने का दौर शुरू हुआ. इसका शुरुआत में असर भी हुआ, लेकिन भाजपा से जुड़े संगठनों के लोगों पर चढ़ा सत्ता का बुखार, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की योगी की कोशिशों पर पानी फेरने लगा. सहारनपुर और आगरा जैसी कई घटनाओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिंता में डाल दिया है. एक तरफ संगठन है तो दूसरी तरफ दायित्व. कानून के तराजू पर संगठन और दायित्व के दो पलड़ों का संतुलन बनाना योगी के माथे पर बल दे रहा है. खास तौर पर सहारनपुर के एसएसपी लव कुमार के आवास पर पिछले दिनों हुए हिंसक हमले ने योगी सरकार को काफी शर्मसार किया है. विडंबना यह है कि इस हमले का नेतृत्व भाजपा का सांसद ही कर रहा था.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबसे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, कई बार यह कह चुके हैं कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है. कानून व्यवस्था को न तो चरमराने दिया जाएगा और न कानून व्यवस्था के साथ कोई समझौता किया जाएगा. उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित करना भाजपा का लक्ष्य है. योगी ने घोषणा कर रखी है कि थाने की बागडोर उसे दी जाएगी, जो परिणाम देगा, चाहे वह उप-निरीक्षक (सब-इंसपेक्टर) हो या निरीक्षक (इंसपेक्टर). योगी ने पुलिस महानिरीक्षकों और पुलिस अधीक्षकों को भी निर्देश दिया है कि थानों पर परिश्रमी, निष्ठावान और समर्पण भाव से काम करने वाले पुलिस अफसरों को तैनात किया जाए, जो कानून-व्यवस्था पर नियंत्रण रख सकें. गोरखपुर की सभा में भी मुख्यमंत्री योगी ने बड़ी तल्खी से कहा कि जिन्हें कानून-व्यवस्था पर भरोसा नहीं, वो प्रदेश छोड़ कर चले जाएं.

योगी की मंशा, उनके आदेशों और बयानों के बरक्स हम सहारनपुर और आगरा की दो घटनाएं सामने रखते हैं. पहले सहारनपुर की घटना देखते चलें. बीते 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर सहारनपुर के तुथली गांव के दलितों ने एक शोभा यात्रा निकाली थी. इस पर गांव के ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला बोल दिया. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की झांकी लेकर चल रहे लोगों पर जबरदस्त पथराव किया गया. पथराव में सहारनपुर के भाजपा सांसद राघव लखनपाल और एसएसपी लव कुमार समेत कई लोग घायल हुए. खूनी हिंसा पर उतारू हमलावरों के बीच से किसी तरह लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका.

इस भारी पत्थरबाजी की घटना पर नाराजगी जताने के लिए भाजपा सांसद के नेतृत्व में उग्र भीड़ ने एसएसपी लव कुमार के बंगले पर धावा बोल दिया और वहां पर भीषण तोड़फोड़ मचाई. एसएसपी के परिवार को किसी तरह गोशाले में छुप कर जान बचानी पड़ी. सहारनपुर में पिछले कुछ वक्त से लगातार दलितों को उकसाने वाली घटनाएं हो रही थीं. देवबंद के एक गांव में कुछ ही दिन के अंतराल में दूसरी बार अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने की घटना घटी. सहारनपुर के तत्कालीन एसएसपी लव कुमार का कहना है कि शोभायात्रा की अजाजत प्रशासन ने नहीं दी थी, इसके बावजूद शोभायात्रा निकाली गई. इसी दौरान एक समूह ने पथराव शुरू कर दिया. शोभायात्रा को बाधित किए जाने और उसकी दूरी में काट-छांट किए जाने से नाराज हुई भीड़ ने एसएसपी के आवास पर हमला बोल दिया. भीड़ ने सीसीटीवी कैमरे और कुर्सियां तोड़ डालीं, एसएसपी की नेम प्लेट उखाड़ दी और पथराव करने वाले समुदाय के गांव के रास्ते से ही यात्रा निकालने पर अड़े रहे. सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र का गांव सड़क दुर्घटना काफी समय से संवेदनशील माना जाता है. दस साल पहले भी इस गांव में संत रविदास जयंती पर शोभायात्रा निकालने को लेकर दो समुदायों में हिंसक विवाद हो चुका है. एसएसपी ने कहा कि स्थानीय भाजपा सांसद राघव लखनपाल शर्मा के नेतृत्व में भीड़ उनके घर में घुसी और सांसद ने उन्हें नौकरी से निकलवाने की धमकी दी. हमले के वक्त उनके रिश्तेदार और परिवार के सदस्य अपने ही घर में आतंक की स्थिति में थे, 'मेरे परिवार ने ऐसा कभी नहीं देखा था. मेरे बच्चे भीषण डरे हुए थे.' एसएसपी की पत्नी शक्ति कुमार ने कहा, 'मैंने अपने दोनों बच्चों की आंखों में खौफ देखा है. सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाने वाली एसएसपी की कोठी पर ढाई घंटे तक जो मंजर मैंने देखा, उससे मैं खुद सहम गई हूं.'

दूसरी तरफ सांसद लखनपाल ने कहा कि एसएसपी अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपना दोष मुझ पर डाल कर खुद बचने की कोशिश कर रहे हैं. एसएसपी लव कुमार ने माहौल खराब किया और हिंसा के दौरान मौके से भाग खड़े हुए. पुलिस ने मुझ पर गलत एफआईआर दर्ज की है. कार्रवाई पत्थरबाजों पर होनी चाहिए थी. मौके से भाग खड़े हुए एसएसपी अब मनगढ़ंत कहानियां सुना रहे हैं. वे परिवार को कवच के रूप में इस्तेमाल करके अपनी नाकामियां ढंक रहे हैं. सांसद ने बेसाख्ता कहा कि उनके घर पर कोई हमला नहीं किया गया था. सांसद ने कहा कि सहारनपुर के जिलाधिकारी शफाकत कमाल और एसएसपी लव कुमार बाबा साहेब अंबेडकर में आस्था नहीं रखते हैं. इसीलिए उन्होंने नेतागीरी अधिक की और ड्यूटी कम. सांसद का आरोप है कि इस इलाके में कश्मीर की तरह पत्थरबाज पनप रहे हैं और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है. भाजपा के ही सांसद व मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर सत्यपाल सिंह ने इस घटना पर कहा कि सहारनपुर जैसी घटनाओं का पुलिस के मनोबल पर नकारात्मक असर पड़ता है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 15 साल बाद भाजपा की सरकार बनी है. खराब कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाकर ही पार्टी सत्ता में आई है. ऐसे में पार्टी के हर कार्यकर्ता का कर्तव्य है कि वो कोई ऐसा काम न करे जिससे पार्टी और सरकार बदनाम हो.

उधर, आगरा में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला बोल कर योगी सरकार की कानून व्यवस्था को कठघरे में डाला. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला कर एक दारोगा की पिस्तौल भी छीन ली. बजरंग दल के उग्र कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर सीकरी के सदर थाने के हवालात में बंद पांच लोगों को छुड़ाने के लिए पुलिस पर हमला बोला था. हमलावरों ने पुलिस की पिटाई करने के साथ-साथ एक दारोगा की सरकारी पिस्तौल भी छीन ली. पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब गोरखपुर में थे, तो उनकी सभा में मंच पर माफिया अमरमणि त्रिपाठी का बेटा अमनमणि त्रिपाठी भी मौजूद था. इससे भी योगी की काफी किरकिरी हुई. अमनमणि अपनी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोप में जेल में था. उस मामले की सीबीआई जांच चल रही है. अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी और मां मधुमणि त्रिपाठी कवयित्री मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं.

महज संजीदगी से अपराध नहीं रुकने वाला

उत्तर प्रदेश में भाजपा करीब 15 साल बाद सत्ता में वापस आई है. भाजपा के चुनावी नारों में यह नारा भी शामिल था, 'न गुंडाराज न भ्रष्टाचार'. लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के इन शुरुआती दो महीने में अपराध कहीं थमता नहीं दिखा. हालांकि योगी कानून व्यवस्था को लेकर काफी संजीदा दिख रहे हैं. इन दो महीनों में पुलिस थानों या चौकियों पर हमले की 20 वारदातें दर्ज हुईं. हमलों में पुलिस थानों के भीतर घुसकर पुलिसकर्मियों को पीटा गया. हमलों में आधा दर्जन लोगों की मौत भी हुई. इस दरम्यान चार हजार से अधिक विभिन्न किस्म के अपराध हुए, जिनमें दो सौ हत्याएं, करीब तीन सौ बलात्कार, वाराणसी में 10 करोड़ की लूट, इलाहाबाद में 16 लाख की लूट जैसी बड़ी घटनाएं शामिल हैं. ■

साम्प्रदायिक अराजक गुंडों पर लगाम योगी की बड़ी चुनौती

विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था प्रमुख चुनावी मुद्दा थी. इससे समाजवादी पार्टी को भारी नुकसान हुआ और भाजपा के सत्ता में आने का रास्ता खुला. पांच बार सांसद रह चुके योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने से लोगों की उम्मीदें बढ़ीं, क्योंकि जनता के मन में योगी की छवि 'नो-नॉनसेंस एडमिनिस्ट्रेटर' की रही है. योगी ने गोरखपुर में कानून का राज स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्हें 90 के दशक के अराजक गोरखपुर को कानून पसंद शहर में बदलने का श्रेय जाता है. लिहाजा, यूपी की कानून व्यवस्था योगी के लिए चैलेंज की तरह है. अखिलेश सरकार ने अपने शासनकाल में कानून व्यवस्था को अपराधियों और गुंडों के आगे समर्पित कर दिया था. गुंडों ने प्रदेश में समानांतर सत्ता स्थापित कर रखी थी और शासन के हनक की धुर्रियां बिखेर दी थीं. इसका परिणाम चुनाव में सामने आ गया. अखिलेश सरकार ने प्रदेश में अपराध को कम दिखाने के लिए भी आंकड़ों की बाजीगरी की थी. ज्यादातर जघन्य अपराध दर्ज ही नहीं किए गए या उन्हें एफआईआर के बजाय सनहे में दर्ज कर निपटा दिया गया, जिससे वे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के दायरे में न आ पाएं. एनसीआरबी ने 2015 में उत्तर प्रदेश के अपराध के आंकड़ों में इस गाइडबी को उजागर किया. एनसीआरबी में देश के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय दंड विधान (इंडियन पेनल कोड-आईपीसी) के तहत 112 मामले ही दर्ज थे जबकि उस दौरान दिल्ली में यह आंकड़ा 917 था. जब सनहों के आंकड़े देखे गए तब असलियत का पता चला. दोनों आंकड़ों को मिलाकर उत्तर प्रदेश में जघन्य अपराध के आंकड़े 1293 पर पहुंच गए. बाकि, आईपीसी के तहत दर्ज आंकड़ों के मुकाबले दस गुना ज्यादा अपराध यूपी में हुए. अखिलेश राज में दंगा, अपहरण, फिरौती, बलात्कार और हत्या जैसे मामले बढ़े लेकिन शासन इससे लगातार इन्कार करता रहा. यहां तक कि सपा के बुजुर्ग नेता आजम खान ने बुलंदशहर में मां और बेटी के सामूहिक बलात्कार को 'राजनीतिक साजिश' करार देने का शर्मनाक बयान दिया था. गायत्री प्रजापति जैसे भ्रष्ट, बलात्कार और हत्यारोपी मंत्री को संरक्षण देने के कारण भी अखिलेश सरकार की छवि बेजार हुई. इन्हीं कमियों ने भाजपा को मौका दिया. भाजपा के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर सक्रिय तो हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन का जर्जर ढांचा ठीक करने में सरकार को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी. पुलिस पर हमले, आगजनी, सरकारी सम्पत्ति का नुकसान और अधिकारियों को मारने-पीटने और धमकाने की घटनाएं सरकार को संकट में डाल रही हैं. भारी जीत से हिंदुत्ववादी संगठनों में पैदा हुआ गुरूर भी योगी की राह को कठिन बनाएगा, ऐसा लग रहा है. ■

पुलिस को दुरुस्त करने के नए नुस्खे

का नून व्यवस्था सुधारने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई प्रयोगात्मक प्रक्रियाएं शुरू की हैं. नए फैसले के अनुसार अब हर थानेदार को हर महीने एक परीक्षा पास करनी होगी. इस परीक्षा में कोई पेपर नहीं होगा, लेकिन सौ पूर्णांक का यह इम्तिहान थानेदार की कार्यकुशलता साबित करेगा. इस परीक्षा में ज्यादा नम्बर पाने वालों को जिलावार पुरस्कार मिलेगा, वहीं फेल होने वालों की लाइन में वापसी होगी. थानेदारों की परीक्षा लिए जाने का सिलसिला भी योगी की कर्मभूमि गोरखपुर से ही शुरू किया जा रहा है. कुछ समय पहले तक जिलावार थानों की ग्रेडिंग हुआ करती थी. सालभर के दर्ज मुकदमे, गिरफ्तारी, लंबित प्रकरणों का निपटारा, नशीले पदार्थों की जब्ती सहित अपराध संख्या के आधार पर यह ग्रेडिंग की जाती थी. लेकिन मार्क्स के आधार पर थानेदारों के काम-काज को आंकने की प्रक्रिया अब शुरू होने जा रही है. इस प्रक्रिया के तहत अब हर महीने जिला स्तर पर इसकी समीक्षा की जाएगी. कमजोर थानेदारों की पहचान के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था में मूल्यांकन के दौरान केस डायरी की स्थिति, विवेचना निस्तारण, बदमाशों की गिरफ्तारी, अपराध नियंत्रण, जनता से व्यवहार की समीक्षा होगी. इनके अलावा थानेदारों को एक मूल्यांकन प्रपत्र भी दिया जाएगा, जिसे भर कर वे एसपी को देंगे. इसका मिलान किया जाएगा. इस मूल्यांकन प्रक्रिया में थानों की साज-सज्जा और सफाई पर 20 अंक, थानों पर आने वाले शिकायतकर्ताओं के लिए सुविधा-व्यवस्था पर 10 अंक, थानों के रजिस्टर, दस्तावेजों के रख-रखाव पर 10 अंक, थानों के कार्य की समीक्षा और कार्रवाई की समीक्षा पर 10 अंक, निरोधात्मक कार्रवाई के पारदर्शी विवरण पर 10 अंक, विभिन्न अपराधों में की गई कार्रवाई और उनके ब्यौरे पर 10 अंक, लंबित विवेचनाओं की प्रगति और उसके ऑनलाइन रिकॉर्ड पर 10 अंक, पुरस्कार घोषित अपराधियों की धर-पकड़ पर 5 अंक, माफियाओं पर कार्रवाई पर 10 अंक और अतिक्रमण हटाने से लेकर ट्रैफिक सुधार के काम पर 5 अंक निर्धारित किए गए हैं. ■

अखिलेशवादी सपा ने मुलायम को दूध की मक्खी बनाने का नतीजा भुगत लिया

बौखलाई पार्टी का बेचैन अभियान

प्रभात रंजन दीन

अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी में चुनाव हारने की बौखलाहट के साथ-साथ पार्टी बचाने की बेचैनी भी है. सपा के टूट कर अलग पार्टी बनने की सुगबुगाहटें जैसे-जैसे तेज होती जा रही हैं, वैसे-वैसे अखिलेश-रामगोपाल खेमे की बेचैनी बढ़ती जा रही है. हाल में शिवपाल यादव ने अखिलेश को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद मुलायम सिंह यादव के लिए छोड़ देने का अल्टीमेटम देकर बौखलाहट और बढ़ा दी है. बौखलाए रामगोपाल तो यहां तक बोल पड़े कि शिवपाल का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है. शिवपाल के पास मुलायम के सिवा कुछ नहीं है. ऐसा बोल कर रामगोपाल ने संदेश दिया कि अखिलेश और उन्हें मुलायम के व्यक्तित्व का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं रह गई है. मुलायम के व्यक्तित्व का सहारा लेकर मुख्यमंत्री बने पुत्र अखिलेश और उसी व्यक्तित्व के बूते राज्यसभा तक पहुंचे भाई रामगोपाल को अपने वजूद का मूल स्रोत याद नहीं रहा. इसी अपसंस्कृति का खामियाजा अखिलेश को भुगतना पड़ा. इसका कोई आत्ममंथन भी नहीं हो रहा. अपने पिता को दरकिनार कर पुत्र अखिलेश अपनी पत्नी डिम्पल, फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन और चचेरे चाचा रामगोपाल का सहारा लेकर पार्टी की सदस्यता बढ़ाना चाह रहे हैं. अखिलेशवादी सपा के सदस्यता अभियान के आंकड़े उसी तरह बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए जा रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े प्रदेश के विकास को लेकर गढ़े गए और उन फर्जी आंकड़ों के कारण पार्टी गड्ढे में चली गई.

दफ्तर में बैठे-बैठे आंकड़े गढ़ने में माहिर मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि 15 अप्रैल से शुरू हुए अभियान में केवल 15 दिन में ही 42 लाख प्रारंभिक सदस्य बन गए. यानि, विधानसभा चुनाव हारने के बाद अखिलेशवादी समाजवादी पार्टी का लोगों में क्रेज इतना बढ़ गया कि प्रति दिन दो लाख 80 हजार की दर से लोग सपा के सदस्य बन रहे हैं. सपा का सदस्य बनने के लिए तो जैसे प्रदेश में बाढ़ आ गई है. चौधरी को इस तरह के अतार्किक और अतुकांत आंकड़े गढ़ने में कोई झिझक भी महसूस नहीं होती. सपा का सदस्यता अभियान 15 जून तक चलना है. ऐसे में पार्टी को एक करोड़ सदस्य मिलना तो तय हो गया है. जब पार्टी सत्ता में थी, तब सदस्य बनने का उतना क्रेज नहीं था. खुद राजेंद्र चौधरी ही कहते हैं कि 01 जुलाई 2014 से 30 सितम्बर 2014 तक चलाए गए तीन महीने के सदस्यता अभियान में 75 लाख प्रारम्भिक सदस्य बने थे. इस बार तो 15 दिन में ही 42 लाख सदस्य बन गए. दिलचस्प यह भी जानना है कि सदस्यता अभियान को अखिलेश यादव खुद मॉनिटर कर रहे हैं. राजेंद्र चौधरी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी भारत के संविधान में सच्ची निष्ठा रखती है और गांधी लोहिया के आदर्शों से प्रेरणा लेकर लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता एवं समाजवाद में आस्था रखती है. ऐसा कहते हुए राजेंद्र चौधरी मुलायम सिंह के समाजवादी सिद्धांतों और उनके योगदानों के प्रति श्रद्धा की तनिक चिंहुक तक नहीं लेते. चौधरी कहते हैं कि अखिलेश के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी लोकतांत्रिक तरीकों से विरोध प्रकट करने के अधिकार को मान्यता देती है. मुलायम की नसीहतों और शिवपाल के विरोध पर तीखे विद्रोही तेवर अख्तियार करने का विरोधाभासी चरित्र पार्टी ने क्यों दिखाया, चौधरी इस बारे में कुछ नहीं कहते.

बहरहाल, समाजवादी पार्टी के स्वयंभू मुखिया अखिलेश यादव सदस्यता अभियान के जरिए डैमेज कंट्रोल करना चाहते हैं. उन्हें लगता है कि इस तरह के अभियान से उन्हें अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस मिल जाएगी. हाईटेक पद्धति से सपा का सदस्यता अभियान चल रहा है. ऑनलाइन या मिस्ड कॉल देकर भी लोग सदस्य बन रहे हैं. इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है. अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव ने पिछले दिनों सदस्यता अभियान का उद्घाटन किया. इस अभियान में अखिलेश ने फिल्म अभिनेत्री व राज्यसभा सदस्य जया बच्चन का भी सहारा लिया. खूब फोटो खींचे गए. खूब प्रचार हुआ. लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव का किसी ने नाम तक नहीं लिया. पापा मुलायम और चाचा शिवपाल किनारे हो गए और पत्नी डिम्पल व आन्टी जया बच्चन के सहारे पार्टी प्रतिमान स्थापित करने की यात्रा पर चल पड़ी है. अखिलेश-डिम्पल के पोस्टर हर जगह दिख रहे हैं. तस्वीरों में जया बच्चन दिख रही हैं. लेकिन मुलायम-शिवपाल कहीं नहीं दिख रहे. मुलायम की कहीं होर्डिंग लगी भी, तो उन्हें बिलकुल ही किनारे रखा गया है.

जया बच्चन की मार्केटिंग और सपा में महिला सम्मान का यथार्थ

फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन चाहे जितना कहती रहें कि समाजवादी पार्टी में ही महिलाओं को उचित सम्मान मिलता है, लेकिन असलियत यह है कि समाजवादी पार्टी के नेता पार्टी की महिला नेता को अपमानजनक तरीके से मंच से उतारने की कोशिश करते हैं और महिला नेता जब अपना सम्मान बचाने के लिए जद्दोजहद करती हैं, तो सपा नेता मंच छोड़ कर चले जाते हैं. इसके लिए वे सदस्यता अभियान की बैठक की ऐसी-तैसी करने से भी नहीं हिचकते. इस घटना पर पार्टी के सामान्य नेता भी कहते हैं कि अखिलेश ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी जबरन ले ली, तो क्या कोई महिला नेता किसी बैठक में मंच की कुर्सी पर बैठ भी नहीं सकतीं! सपा के सदस्यता अभियान के दौरान झांसी में हो रही बैठक में ऐसा ही हुआ. जिस पार्टी में महिलाओं को उचित सम्मान मिलता है, यह कह कर फिल्म अभिनेत्री जया बच्चन अखिलेश यादव की मार्केटिंग करती हो, उसी पार्टी की एक महिला नेता को मंच से नीचे उतारने की सार्वजनिक कोशिश की गई और वे अपना सम्मान बचाने के लिए जूझती रहीं. एक महिला नेता का मंच पर बैठना नेताओं को इतना नागवार लगा कि वे मंच से उतर कर चले गए और सभा भंडूल हो गई. सदस्यता अभियान के लिए झांसी के राजकीय संग्रहालय में जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह ने पिछले दिनों बैठक बुलाई थी. बैठक में राज्यसभा सांसद चन्द्रपाल सिंह यादव, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह, एमएलसी श्यामसुन्दर सिंह जैसे कई वरिष्ठ नेता मंच पर बैठे थे. इसी दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य रहीं सुषमा यादव भी मंच पर खाली पड़ी एक कुर्सी पर बैठ गईं. सुषमा यादव को मंच पर बैठना नेताओं को नहीं सुहाया. वे सुषमा यादव को मंच से नीचे जाने के लिए कहने लगे. महिला नेता ने कहा कि वह भी संवैधानिक पद पर रही हैं और वे मंच पर बैठ सकती हैं. सुषमा यादव के ऐसा कहते ही मंच पर बैठे अधिकांश पदाधिकारियों ने बैठक बीच में ही रोक दी और मंच से उतर कर चले गए. अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी में महिलाओं का यही सम्मान है और इसीलिए महिलाओं को सपा में हमेशा बने रहना चाहिए. ■

सदस्यता अभियान के किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी सभा में मुलायम सिंह यादव शामिल नहीं हुए और न उन्हें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया. डिम्पल को स्थापित करने की कोशिश जरूर हो रही है. जया बच्चन ने अखिलेश की छवि को संभालने की कोशिश की और कहा कि महिलाओं का उचित सम्मान सपा में ही है और महिलाओं को सपा में हमेशा बने रहना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

» विधानसभा चुनाव में गठबंधन का ऐतिहासिक परिणाम रचने के बाद »

ये दोस्ती अब नहीं झेलेंगे

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में गठबंधन का खामियाजा भुगतने के बाद अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ती और अधिक झेलने के मूड में नहीं दिख रही है. सपा कांग्रेस गठबंधन के शीघ्र टूट जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने पिछले दिनों लखनऊ में ही इस बात का संकेत दे दिया. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि गठबंधन रखना है कि तोड़ना है, इसका फैसला आलाकमान के हाथ में है. राज बब्बर ने यह जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अकेले हिस्सा लेगी. स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस सपा के साथ गठबंधन नियम का पालन नहीं करेगी. राज बब्बर के इस ऐलान से यह करीब-करीब साफ हो गया है कि विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में सपा-कांग्रेस का गठबंधन टूटने की कगार पर है. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस-सपा गठबंधन को राज्य की जनता ने सिरे से नकार दिया और दोनों पार्टियों को विपक्ष लायक भी नहीं छोड़ा. इस हार के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस को कोस रही है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी को. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने पिछले दिनों लखनऊ में कहा कि अब यूपी में स्थानीय निकायों के चुनाव हैं. कांग्रेस ने तय किया है कि राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव अकेले ही लड़ा जाए. बब्बर ने बात संभालते हुए कहा कि निकाय चुनाव कार्यकर्ता के व्यक्तिगत सम्बंधों के आधार पर लड़े जाते हैं. बब्बर ने कहा कि सिंबल के साथ पार्टी और व्यक्ति की पहचान होती है. हम इसे बढ़ाना चाहते हैं और इसी से संगठन और पार्टी मजबूत होती है. इस चुनाव में हम जनता से कार्यकर्ता का रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं. पार्टी कार्यकर्ता जमीन पर लोगों से सीधे सम्पर्क में रहते हैं. कार्यकर्ताओं के जरिए कांग्रेस की नीतियों की पहचान बनती है. पार्टी कार्यकर्ताओं का जनता से जुड़ाव ही पार्टी का जनता से जुड़ाव होता है. कांग्रेस को चुनाव हारने के बाद यह बात समझ में आई है.

बहरहाल, स्थानीय निकाय चुनाव अकेले बूते लड़ने के कांग्रेस के ऐलान के निहितार्थ जो भी हों, लेकिन अभी गठबंधन तोड़ने का ऐलान किसी भी पक्ष से नहीं हुआ है. अखिलेश यादव कह चुके हैं कि गठबंधन बरकरार रहेगा. हालांकि इस संदर्भ में कांग्रेस की चुप्पी सधी हुई है. राज बब्बर के बयान के बाद ऐसा ही लगता है कि राज्य में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन टूट गया है. यूपी चुनाव में हार के बाद से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों की एक महीने में कई बैठकें हो चुकी हैं. बब्बर ने कहा कि किसी तरह का फैसला लेने से पहले यह पार्टी नेतृत्व के लिए जरूरी है कि वह गठबंधन पर विचार करे. कांग्रेस पार्टी अब अकेले ही चुनाव लड़ेगी. उसे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है. बब्बर की बातों से साफ-साफ जाहिर हुआ कि कांग्रेस-सपा का नारा 'यूपी को ये साथ पसंद है' अब बीते दिनों की बात हो जाएगी. राज बब्बर बोले कि स्थानीय निकाय चुनाव में हम बिना किसी पार्टी से गठबंधन किए चुनाव लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि यूपी विधानसभा चुनावों की हार के बाद पार्टी ने काफी विचार करने के बाद यह फैसला किया है. विधानसभा चुनाव में हारने के बाद अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हार से सपा-कांग्रेस गठबंधन पर कोई असर नहीं पहुंचेगा. गठबंधन बना रहेगा. लेकिन राज बब्बर के ताजा बयान के बाद गठबंधन पर ग्रहण साफ-साफ दिखने लगा है. आप याद करते चलें कि विधानसभा चुनाव में सपा-कांग्रेस गठबंधन ने महज 54 सीटें जीतीं. उनमें कांग्रेस के खाते में केवल 7 सीटें आईं. उल्लेखनीय है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का फैसला अखिलेश यादव का था. मुलायम सिंह यादव ने इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि कांग्रेस से गठबंधन सपा के लिए आत्मघाती साबित होगा. ऐसा ही हुआ. चुनाव में गठबंधन का भट्ठा बैठ गया. उसी समय अखिलेश सरकार के कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया ने भी कहा था कि सपा को कांग्रेस से गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है. ■

गंगा-जमुना के मिलन से अब निकल रहा विकास का कचरा

गठबंधन करने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ-साथ अवतरित हुए और कहा कि कांग्रेस-सपा का गठबंधन गंगा-जमुना का मिलन है और इसमें से विकास की सरस्वती निकलेगी. चुनाव में हार के बाद फिर गंगा अलग रास्ते और जमुना अलग रास्ते चल पड़ने के लिए उद्यत हो रही है. अब दोनों में से विकास की सरस्वती के बजाय विकास का कचरा निकलता दिख रहा है. गठबंधन के बाद लखनऊ में बड़ा नाटकीय प्रेस कॉन्फ्रेंस था वह, जिसमें राहुल और अखिलेश ताज होटल पहुंचे, एक-दूसरे को गुलदस्ता दिया, साझा रोड शो का ऐलान किया और फिल्म-प्रमोशन शो की तरह थीम सॉन्ग लॉन्च किया. इसके बाद राहुल गांधी ने गठबंधन की तुलना गंगा-यमुना के मिलन से की और कहा कि इससे विकास की सरस्वती निकलेगी. अखिलेश ने अपने पिता की कलई खोली और कहा कि कांग्रेस के साथ केंद्र में भी हम साथ रहे हैं. यह विकास का गठबंधन है, जनता का गठबंधन है. कांग्रेस के साथ और तेजी से काम होगा. हम और राहुल साइकिल के दो पहिए हैं. राहुल और मैं देश को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे और प्रदेश को भी. अखिलेश और राहुल की बातें हमें याद रखनी चाहिए, ताकि सनद रहे. ■

feedback@chauthiduniya.com

महागठबंधन के किंगमेकर बनने की चाहत में लालू

सुनील सौरभ

राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अब राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में जुटे हैं. बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में राजद के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से यह बात उभर कर सामने आई है. भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर लालू प्रसाद यादव वैसी ही भूमिका निभाना चाहते हैं, जैसी वे यूपीए 1 में सभी भाजपा विरोधी दलों को एकजुट कर केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनाने में सफल हुए थे. इसके लिए लालू प्रसाद यादव आगामी अगस्त महीने में पटना के गांधी मैदान में रैली का आयोजन करेंगे, जिसमें बंगाल की तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, ओडीशा के बीजू जनता दल के नवीन पटनायक, बसपा की मायावती तथा सपा के अखिलेश यादव तथा सोनिया गांधी को आमंत्रित किया जाएगा. इस रैली के जरिए वे 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को उखाड़ फेंकने की तैयारी करने के लिए सभी दलों को एकजुट होने का आह्वान भी करेंगे. वर्तमान में राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा विरोधी दलों में बढ़ती लोकप्रियता और इन दलों को एकजुट करने के प्रयास में नीतीश कुमार को केन्द्र स्तर पर बनने वाले संभावित महागठबंधन का श्रेय मिल सकता है. ऐसा माना जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता में इज़ाफ़ा किया है. विशेषकर आधी आबादी शराबबंदी से सुकून महसूस कर रही है. जो लोग लालू प्रसाद यादव के राजद से नीतीश के गठबंधन करने की वजह से विरोध में थे, वैसे लोग भी शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार के समर्थन में बोलने लगे हैं. इन्हीं सब बातों को देख-सुनकर लालू प्रसाद यादव के मन में कहीं न कहीं पुन: यूपीए 1 की तरह किंगमेकर बनने की इच्छा उबाल मारने लगी. इसकी शुरुआत लालू ने नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा जिले के राजगीर में तीन दिवसीय राजद प्रशिक्षण शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 2 से 4 मई 2017 तक आयोजित कर की.

लालू ने राजगीर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के बहाने सबसे पहले अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया है, ताकि वे अगस्त में पटना के गांधी मैदान में भाजपा विरोधी दलों की होने वाली रैली में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा सकें. इसमें लालू कितने सफल हो पाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन राजगीर में राजद के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मूल एजेंडा यह रहा कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का श्रेय लालू को मिले. हाल में नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था. इस दौरे में बिहार में शराबबंदी की सराहना सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी की. भाजपा विरोधी दलों के बीच नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता ने लालू को कहीं न कहीं विचलित किया है.

राजद के इस शिविर का आयोजन कर लालू ने एक तरह से नीतीश कुमार को चुनौती दे डाली, क्योंकि राजद नेताओं को पहले जानकारी थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और प्रशिक्षण शिविर बोधगया में आयोजित होगा, बाद में आयोजन स्थल बदल कर राजगीर कर दिया गया. इससे स्पष्ट है कि देश स्तर पर भाजपा विरोधी दलों के महागठबंधन बनने या बनाने का श्रेय लेने की होड़ लालू और नीतीश में लगी है. लालू ने राजगीर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर के बहाने सबसे पहले अपनी पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया है, ताकि वे अगस्त में पटना के गांधी मैदान में भाजपा विरोधी दलों की होने वाली रैली में अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास करा सकें. इसमें लालू कितने सफल हो पाएंगे यह तो समय बताएगा, लेकिन राजगीर में राजद के तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का मूल एजेंडा यह रहा कि भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने का श्रेय लालू को मिले. हाल में नीतीश कुमार ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया था. इस दौरे में बिहार में शराबबंदी की सराहना सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने भी की. भाजपा विरोधी दलों के बीच नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता ने लालू को कहीं न कहीं विचलित किया है. इससे इंकार नहीं किया जा सकता है कि राजद के राजगीर सम्मेलन के सहारे लालू प्रसाद यादव एक बार पुन: खुद को राष्ट्रीय राजनीति का सिरमौर बनने का प्रयास कर रहे हैं. प्रशिक्षण शिविर के सहारे लालू प्रसाद यादव ने अपने ऊपर लगे परिवारवाद के आरोप को कुछ कम करने का प्रयास किया. उद्घाटन सत्र में राबड़ी देवी और स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव मौजूद नहीं थे. अगर वे आते तो आगे की पंक्ति में ही बैठते. ऐसे में अगली पंक्ति में सिर्फ लालू, उनकी राज्य सभा सदस्य बड़ी बेटी मीसा भारती और पुत्र एवं बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बैठे थे. इसी कतार में प्रेमचंद गुप्ता, जयप्रकाश यादव, बुलोमंडल, तसलीमुद्दीन, जगदानंद सिंह, मंगनीलाल मंडल, मुद्रिका सिंह यादव, कमर आलम, मनोज झा आदि भी बैठे थे. बिहार में राजद कोटे के सभी मंत्री पीछे की कतार में बैठे थे. मंच पर नेताओं के बैठने की जो व्यवस्था की गई थी, उससे भी लालू कुछ अमौखिक संदेश देने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन उद्घाटन सत्र में राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉ. रघुवंश सिंह के नहीं रहने का कारण लोग समझ नहीं पाए. शिविर में बोलते हुए राजद के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद जगदानंद सिंह ने इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि हमारे विचारों में धुंधलापन आया है और प्रशिक्षित लोगों की जमात खत्म हुई है, जिसके कारण राजद कमजोर हुआ है. सबसे बड़ी बात यह हुई कि शिविर के माध्यम से लालू ने देश व प्रदेश की राजनीति के बदलते परिवेश और वोटरों की बदलती मानसिकता को ध्यान में रखते हुए अपनी छवि को बदलने का प्रयास किया. क्योंकि लालू ने शिविर में अपने भाषण में अनुशासन शब्द का कई बार इस्तेमाल किया. लालू ने कहा कि अनुशासन के साथ ही पार्टी आगे बढ़ेगी. राजद में दुलमुल और आया राम, गया राम नेताओं की अब नहीं चलेगी. अनाप-शनाप बयान नहीं चलेगा. हमारा मिशन देश से भाजपा का खात्मा व धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को सत्ता में लाना है. ज्ञात हो कि लालू-राबड़ी के कथित जंगलराज में राजद के नेता-कार्यकर्ता कितने अनुशासनप्रिय थे, यह बताने की जरूरत नहीं है. अब राजद ने चौक-चौराहों पर राजद कार्यकर्ताओं व नेताओं से बहस करने की बात कही है, ताकि हर जगह राजद की चर्चा रहे. यह बात पूर्व सांसद जगदानन्द सिंह ने कही, लेकिन शिविर में लालू और उनके पुत्र बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के निशाने पर भाजपा ही रही. लालू ने इस शिविर से भाजपा के विरोधी दलों से केन्द्र स्तर पर एकजुटता के लिए बिहार मॉडल अपनाने का आग्रह किया. लालू ने राजद की बैठक में कहा कि आज समाजवादियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है. देश खतरे के दौर से गुज़र रहा है. हर जगह राम मंदिर, गाय, कब्रगाह और श्मशान की राजनीति हो रही है. दलदल में फंसे देश को बाहर निकालने के लिए हम सभी को साथ आना होगा. नीतीश कुमार के साथ मेरी बहुत लड़ाई थी, लेकिन बिहार में भाजपा को पराजित करने के लिए हमने गठबंधन किया और सफल रहे. आज देश के स्तर पर इसी तरह का गठबंधन बनाने की जरूरत है, तभी भाजपा-आरएसएस को पराजित किया जा सकता है. तीन दिवसीय शिविर में परिवारवाद पर किसी भी राजद नेता ने कुछ भी नहीं बोला. साम्प्रदायिक शक्तियों को सत्ता से बाहर करने की बात करने वाले राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्रों ने शिविर के दूसरे दिन पूरी तरह परिवारवाद, जातिवाद पर ही आ गए. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने स्पष्ट कहा कि देश में साम्प्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में यादव इंजन हैं, तो अन्य लोग बोगी. शिविर के दूसरे-तीसरे दिन तो पूरी तरह से लालू परिवार ही छाए रहे. राजद के बड़े नेताओं की उपस्थिति के बावजूद मंच पर पहली पंक्ति में लालू के अलावा मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप बैठे थे. लालू पुत्र उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने भी राजद कार्यकर्ताओं को विशेष कर यादवों को एकजुट करने के लिए वही रणनीति का ऐलान किया, जिसकी शुरुआत उनके पिता ने दो दशक पूर्व की थी. तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को लाठी से लैस होने की बात कही. साथ में इतना जोड़ा कि लैपटॉप भी देंगे. लालू दो दशक पूर्व पटना के गांधी मैदान में राजद कार्यकर्ताओं की लाठी रैली कर देश भर में चर्चा में आए थे. राजद के राजगीर शिविर से स्पष्ट हो गया है कि लालू प्रसाद यादव में एक तरफ बिहार की सत्ता पर पूर्णत: काबिज होने की छटपटाहट है, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी दलों की एकजुटता का श्रेय लेने की होड़ भी. इस चाहत में दर्द बस इतना है कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता होने के कारण वे खुद चुनाव लड़ने से वंचित हैं, लेकिन किंगमेकर तो बन ही सकते हैं. कह सकते हैं कि राजद की तीन दिवसीय प्रशिक्षण शिविर-सह-राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 'कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना' साधने का प्रयास लालू प्रसाद यादव ने किया. यह तो अगस्त में पटना के गांधी मैदान में आयोजित भाजपा विरोधी दलों की रैली में पता चलेगा कि लालू का निशाना 'टारगेट' पर लगा कि नहीं. फिलहाल लालू अपनी राजनीतिक चाल से भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करने के प्रयास में लगकर नीतीश की बढ़ती लोकप्रियता पर भी लगाम लगाना चाहते हैं. राजद का प्रशिक्षण शिविर और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नीतीश के गढ़ में कर के लालू ने कुछ इसी तरह का संदेश देने का प्रयास किया है. ■

feedback@chauthiduniya.com

www.vastuvihar.org
वास्तु विहार®
एक विश्वस्तरीय टाउनशिप
AN ISO : 9001 : 2008 : 14001 : 18001 : 2007 COMPANY

बिहार, झारखंड, बंगाल,
उड़ीसा एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश
के 63 शहरों में 117 आवासीय
परियोजनाओं की श्रृंखला
Call : 95340 95340

मनोज तिवारी

मोतिहारी चीनी मिल प्रकरण

आत्मदाह के बाद मज़दूर आन्दोलन ने लिया विशाल रूप

● सत्याग्रह शताब्दी समारोह केवल फरेब: स्वामी अग्निवेश ● पूंजीवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद से भी ख़तरनाक : पप्पू यादव

राकेश कुमार

मोतिहारी चीनी मिल के दो मजदूरों के आत्मदाह की घटना के बाद आन्दोलन ने विशाल रूप ले लिया है. स्वामी अग्निवेश, जन अधिकार पार्टी प्रमुख सह सांसद पप्पू यादव, समाजसेवी और झारखण्ड के एडीजी रह चुके पीके सिद्धार्थ, गांधीवादी और भागलपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रामजी सिंह जैसे लोगों ने मजदूर-किसानों की मांगों को उठाया और आत्मदाह की घटना की न्यायिक जांच की मांग की. चीनी मिल गेट पर सोमवार को मजदूर दिवस पर आयोजित सत्याग्रह सभा में मिल मजदूरों के साथ बच्चे, महिलाएं, किसान और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. चम्पारण विकास मोर्चा के नेता राय सुन्दरदेव शर्मा की पहल पर मजदूर आन्दोलन को व्यापक रूप देने का जिम्मा उक्त नेताओं और समाजसेवियों ने संभाल लिया है.

सत्याग्रह सभा के मंच से किसानों-मजदूरों का आह्वान करते हुए स्वामी अग्निवेश ने वर्तमान परिवेश में सत्याग्रह की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आन्दोलन के नए रूप तलाशे जाने की बात कही. उन्होंने सत्याग्रह पर बोलते हुए कहा कि गांधी जी ने अन्त्योदय का नारा दिया था. गांधी जी ने वसीयत की थी कि सत्ता में जो रहें, वे अपने काम का आकलन इससे करें कि उनके काम व नीतियों से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है. लेकिन गांधी जी के उत्तराधिकारियों ने इसे भुला दिया.

क्या है घटना

2002 से बकाया वेतन और मिल चालू करने की मांग को लेकर मजदूर आन्दोलन कर रहे हैं. कई बार मिल प्रबंधन के साथ समझौता और न्यायालय के आदेश के बाद भी मजदूरों के बकाया वेतन और किसानों के गन्ना की कीमत का भुगतान नहीं हुआ. विगत 7 अप्रैल से पुन: आन्दोलन शुरू हुआ. मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव ने आन्दोलन की जानकारी देते हुए जिला प्रशासन, पुलिस से लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक को चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो 9 अप्रैल की अर्धरात्रि के बाद मजदूर आत्मदाह करेंगे. लेकिन किसी ने सुध नहीं ली और 10 अप्रैल को नरेश श्रीवास्तव और मजदूर सूरज बैठा ने आत्मदाह कर लिया. नरेश ने इलाज के दौरान 11 को दम तोड़ दिया, जबकि सूरज बैठा की भी मौत 19 अप्रैल को हो गई थी. एक तरफ चम्पारण सत्याग्रह के सौ वर्ष पूरे होने पर पूरे राज्य में समारोहों का आयोजन हो रहा था और दूसरी तरफ अपनी मजदूरी की मांग को लेकर मजदूर आत्मदाह कर रहे थे.

आन्दोलन ने लिया विशाल रूप

सत्याग्रह सभा के मंच से किसानों-मजदूरों का आह्वान करते हुए स्वामी अग्निवेश ने वर्तमान परिवेश में सत्याग्रह की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए आन्दोलन के नए रूप तलाशे जाने की बात कही. उन्होंने सत्याग्रह पर बोलते हुए कहा कि गांधी जी ने अन्त्योदय का नारा दिया था. गांधी जी ने वसीयत की थी कि सत्ता में जो रहें, वे अपने काम का आकलन इससे करें कि उनके काम व नीतियों से समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को कितना लाभ मिलता है. लेकिन गांधी जी के उत्तराधिकारियों ने इसे भुला दिया. आज सत्याग्रह शताब्दी वर्ष समारोह मनाया जा रहा है. करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, राष्ट्रपति आए, मुख्यमंत्री आए, लेकिन दोनों मजदूरों के शहादत ने बता दिया कि यह सत्याग्रह समारोह केवल फरेब है. मृतक सूरज बैठा का अंतिम समय में लोगों ने मोबाइल पर बयान रिकॉर्ड किया, जिसमें वह चीख-चीख कर आत्मदाह की बात कह रहा है, लेकिन पुलिस ने बार-बार कहने के बाद भी बयान रिकॉर्ड नहीं किया. उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बात कर घटना की न्यायिक जांच करने और मिल की जमीन को नहीं बेचने देने की बात कही. उन्होंने आह्वान किया कि हम लोग इस आन्दोलन को अंजाम तक पहुचाएंगे.

हमारी लड़ाई राजनीतिज्ञों के ख़िलाफ

इस सभा की एक विशेष बात यह रही कि सांसद पप्पू यादव ने इस आन्दोलन को आगे बढ़ाने की बात कही. चम्पारण विकास मोर्चा के राय सुन्दरदेव शर्मा ने बताया कि उन्होंने पप्पू यादव से इस आन्दोलन में शिरकत करने का आग्रह किया था. सत्याग्रह सभा को सम्बोधित करते हुए पप्पू यादव ने आर्थिक आजादी के लिए आन्दोलन का शंखनाद किया. उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के साथ चम्पारण की धरती से ही आर्थिक आजादी की लड़ाई भी शुरू करनी होगी. सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चम्पारण की धरती कभी केन, कैश और क्राइम को लेकर जानी जाती थी. आजादी के समय बिहार में 38 चीनी मिलें थीं, जिसमें से आज केवल 12 बची हैं. उसमें भी कई मिलें जर्जर हालत में हैं. किसानों की स्थिति दिल्ली के जन्तर-मन्तर पर देखने को मिली, जहां किसान नंगा होकर पेशाब पीते हैं, पर किसी नेता को उनका दर्द महसूस नहीं होता. मीडिया भी किसानों की पीड़ा को तवज्जो नहीं देता.

लोकपक्ष को करना होगा मजबूत

पूर्व एडीजीपी के सिद्धार्थ ने इस लड़ाई का समर्थन करते हुए कहा कि मजदूर देश के रीढ़ की हड्डी की तरह होता है, लेकिन उसे वह प्रतिष्ठा कभी नहीं मिली. जैसे काशी भोले शंकर के त्रिशूल पर टिका है, उसी तरह चम्पारण की धरती भी गांधी की लाठी पर टिकी है. यहां की पुलिस बर्बर हो गई है. यह मिल बिड़ला परिवार की है और सरकार की गर्दन इन पूंजीपतियों के हाथ में है. ऐसे मे न्याय पक्ष के साथ ही लोकपक्ष को मजबूत करना किसानों की जरूरत बन गई है. खेती से लखपति बनाने का गुरुमंत्र देने के लिए विख्यात रहे श्री सिद्धार्थ ने मिल स्थित परिसर में ही किसानों को प्रशिक्षण देने की बात कही. उन्होंने बताया कि स्थानीय चिकित्सकों ने अपने अस्पताल में किसानों को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की बात कही है.

जनसुनवाई में किसानों का लिया बयान

मंगलवार को चीनी मिल के शिवमंदिर में जनसुनवाई की गई, जहां स्वामी अग्निवेश, रामजी सिंह, पीके सिद्धार्थ और राय सुन्दरदेव शर्मा ने एक-एक कर सभी मजदूरों का बयान लेकर वीडियोग्राफी कराई. सुन्दरदेव शर्मा ने कहा कि बयान के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर सरकार और जांच एजेंसियों समेत न्यायालय को दिया जाएगा. बयान में सभी मजदूरों और उनके परिजनों ने कहा कि अगर प्रशासन सतर्क होता तो ये घटना नहीं होती. वहीं पुलिस बर्बरता की बात भी किसानों ने खुलकर कही. पुलिसिया कार्रवाई से डरे-सहमे मजदूरों को अब न्याय की उम्मीद जगने लगी है. जनसुनवाई से एक बात तो स्पष्ट हो गई कि अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने गलत रास्ता अख्तियार किया है. अलबत्ता सरकार ने पुलिस और प्रशासन के लोगों की ही विशेष जांच दल गठित की है.■

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में पर्यटन विकास की योजनाएं अधूरी

सुनील सौरभ feedback@chauthiduniya.com

बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. यहां देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए दर्जनों प्राकृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक पर्यटन स्थल हैं. इन स्थलों को देखने के लिए प्रतिवर्ष देश के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी बिहार आते हैं. लेकिन इन पर्यटकों को दो-चार दिन यहां रुकने के लिए भी बिहार का पर्यटन विभाग कोई व्यवस्था नहीं कर सका है. जबकि बिहार में यूनेस्को ने दो स्थलों बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर तथा नालंदा स्थित प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है. अगर बिहार में पर्यटन स्थलों का विकास कर पर्यटकों को आकर्षित करने की व्यवस्था की जाए तो यहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है. बिहार के बौद्ध सर्किट के तहत सबसे अधिक देशी-विदेशी पर्यटक बोधगया आते हैं. लेकिन बिहार का पर्यटन विभाग या पर्यटन विकास निगम बौद्ध सर्किट को बढ़ावा देने में विफल साबित हुआ है. बोधगया में विभिन्न योजनाएं भी पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गईं. इस पर करोड़ों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन पर्यटकों को विशेष लाभ नहीं मिल सका. कई योजनाएं आज भी अधूरी पड़ी हैं. बोधगया स्थित बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के होटलों की भी हालत बहुत ही खराब है. गया-बोधगया के अलावे बिहार के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर लग्जरी बस चलाने के लिए डेढ़ करोड़ रुपए में निगम ने चार बसें खरीदी थीं. वे सभी बसें पटना के निगम मुख्यालय में जंग खा रही हैं. ये बसें बोधगया-पटना-गया- कोलकाता-गया व कोलकाता-बोधगया-पटना रूट पर चलनी थीं. इसके लिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने प्रति बस 15 हजार रुपए मासिक दर से पीपीपी मॉडल पर परिचालन के लिए जुलाई 2011 में टेंडर निकाला था. मई 2012 में वर्क ऑर्डर व लाइसेंस भी निर्गत किया गया. इसके बाद भी बसें नहीं चलीं क्योंकि टेंडर लेने वालों का एग्रीमेंट ही नहीं हुआ.

राज्य पर्यटन निगम के बोधगया के होटल तथागत बिहार में 45 कमरों के लिए तीन अटेंडेंट हैं, जबकि मानक संख्या चार कमरों पर दो अटेंडेंट का है. इसी होटल के परिसर में टूरिस्ट कांप्लैक्स के 13 कमरा व 75 डोरमेटरी बेड के लिए मात्र पांच अटेंडेंट हैं. यहां कोई नियमित हाउसकीपर भी नहीं है. इसी प्रकार निगम ने बोधगया स्थित अपने होटल बुद्ध विहार को तारांकित (स्टार) होटल की श्रेणी में लाने के लिए 2006 में विस्तार की योजना बनाई थी. इसके तहत अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 6.21 करोड़ की राशि खर्च कर इस काम को दिसम्बर 2013 में पूरा करना था, लेकिन अभी तक यह काम पूरा नहीं हो सका है. इसी प्रकार बोधगया आनेवाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए टूरिस्ट कांप्लेक्स में 1.49 करोड़ की राशि से स्वीमिंग पुल बनाने की योजना 2008-2009 में शुरू हुई थी. इसे जून 2011 में पूरा होना था, लेकिन आजतक यह कार्य पूरा नहीं हो सका है. बोधगया के माया सरोवर परिसर का विकास केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय की पहल पर डेढ़ करोड़ की लागत में हुआ. इसमें वोटिंग की सुविधा के साथ सरोवर, उद्यान व मुक्ताकाश रंगमंच की भी सुविधा है. वोटिंग की सुविधा के लिए पर्यटन निगम ने 2007 में वार्षिक 10,20,30 और 40 फीसदी वृद्धि दर से डेढ़ लाख रुपए में पांच साल के लिए इस सरोवर को लीज पर दिया. 2012 के बाद लीज का नवीकरण नहीं हुआ. इससे निगम को सालाना दो लाख रुपए का नुकसान हुआ तथा 1.70 लाख रुपए में खरीदे गए वोट भी बर्बाद हो गए. पर्यटन निगम की लापरवाही के कारण बहुत दिनों तक माया सरोवर परिसर में लेजर शो नहीं हो सका. 2015 में यह सुविधा दी गई थी. वर्तमान में इस लेजर शो को किसी तरह से चलाया जा रहा है. इन सारी बातों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने 2015 में अपनी रिपोर्ट में कड़ी टिप्पणी की थी. इसके बाद भी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम या पर्यटन विभाग पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास नहीं कर रहा है. ज्ञात हो कि कभी गोवा के बाद देश में सबसे अधिक विदेशी पर्यटक बोधगया आते थे. लेकिन पिछले दो-तीन वर्षों में झारखंड में बिहार से अधिक विदेशी पर्यटकों का आना हो गया है. बिहार में मगध ही ऐसा क्षेत्र है, जहां ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं. नालंदा, राजगीर, पावापुरी, गया और नवादा, औरंगाबाद में ज्यादातर धार्मिक-ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हैं. दुनिया भर से हिंदू, जैन, सिख, मुसलमान श्रद्धालु इन स्थलों को देखने के लिए प्रति वर्ष बड़ी संख्या में यहां आते हैं. नवादा के काकोलत जलप्रपात को तो बिहार का कश्मीर तक कहा जाता है. गर्मी के दिनों में यहां बड़ी संख्या में पर्यटक प्रकृति की अनुपम छटा का आनंद लेने, जलप्रपात में स्नान करने आते हैं. परन्तु इन पर्यटकों को यहां रुकने के लिए पर्यटन विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की है. यदि मगध के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों का ठहराव होने लगे, तो बिहार की अर्थव्यवस्था के लिए यह एक महत्वपूर्ण बात होगी.■

मासिक के प्रति सजगता
सेहतनामा
ariskon Pharma Pvt.Ltd.
An ISO 9001 : 2008 Certified Co.

डॉ. रीना सिंह
मगध मेडिकल कॉलेज गया
शिवम नर्सिंग होम, गया

गया के शिवम नर्सिंग होम की डॉ. रीना सिंह ने महिलाओं में मासिक धर्म में बरती गयी कोताही को लेकर चिंतित दिखीं और बतायी की महिलाएँ पीरियड के समय होने वाले दर्द को इग्नोर कर देती हैं हलांकि हल्का दर्द सामान्य बात है लेकिन असहनीय दर्द या थोड़ा सा भी दर्द महसूस हो तो महिलाओं को गायनो डॉक्टरनी से सम्पर्क अवश्य करना चाहिए। अक्सर महिलाएं पेट दर्द की शिकायत करती हैं और कुछ तो दर्द की गोली भी खाती हैं। दर्द का एक प्रमुख कारण बच्चेदानी में सिकुड़न माना गया है। लेकिन महिलाओं में बाद में भी यदि इस तरह दर्द की समस्या आये तो अवश्य गायनो डॉक्टरनी से सम्पर्क करना चाहिए। यह यूटरस में बीमारी का संकेत है। कई महिलाओं को अति मासिक (ज्यादा रक्त स्राव) की समस्या होती है उसके प्रति भी जागरूक होना आवश्यक है। एक स्वस्थ्य नारी की पहचान उसके मासिक धर्म के नियत समय पर होना है। इसका चक्र 28 दिनों का होता है और 50 के उम्र के आसपास बन्द हो जाता है। निश्चित समय पर या मासिक अन्तराल पर औरतों में होने वाले अति रक्त प्रवाह को जो लम्बे समय तक होता है उसे मेनोराजिया कहते हैं (जब रक्त 80 एम.एल. या 7 से 8 दिनों तक हो) सामन्य तौर पर यह समझा जा सकता है कि मासिक धर्म के समय अतिरक्त स्राव हो तो आप एक अच्छे ग्यानोकोलोजिस्ट से सम्पर्क करें और इसका इलाज करायें इनका मानना है कि बच्चे एक या दो ही रखें इससे अधिक होने पर भी अति रक्तस्राव की समस्या हो सकती है बच्चेदानी में संक्रमण न पकड़ने दें। इसके लिए मासिक पिरियड के समय पैड का प्रयोग करें। यदि देहात में हैं तो साफ सूती कपड़े को गर्म पानी में उबालकर फिर सूखा कर ही इसे प्रयोग करें। डॉ. राखी ने महिलाओं को सलाह देते हुआ बताया कि इसके प्रति सजग रहें और मासिक की अनियमितता के अलावा यदि अति रक्तस्राव की समस्या है तो तुरन्त अच्छे ग्यानोकॉलोजिस्ट से सम्पर्क करें। फास्ट फूड की लत, हमेशा तनाव में रहना या शराब पीना या गर्भाशय से सम्बन्धित कोई बीमारी होना. मासिक के दौरान भी कई महिलाओं को बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता है। आइये अब जानते हैं कुछ कुछ घरेलू उपाय ●करेले का नियमित सेवन करें. ● पीरियड के दौरान ड्राई फ्रूट्स और नट्स खाएँ. ग्रीन टी पिएँ. ● इस दौरान आपको केला खाना चाहिए. इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और दर्द भी दूर होगा ● पालक, पत्ता गोभी, कद्दू आदि खाएँ. ●कब्ज पैदा करने वाले चीज पीरियड्स के दौरान न खाएँ. ● खट्टी चीजों, भूने हुए चीजों और प्रोटीन से भरी दालों का सेवन न करें. ▪ भारती

Carbo - XT Drops Susp.
Ferrous Ascorbate100 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamine B5 mcg Tab.
A Colic Drops.
Simethocone Emulsion, Dil Oil Fennel Oil
Siliplex Syp.
Silymarin, vitamin B Complex Calcuium & Lactic Acid Bacillus
Oflogyl-OZ Susp. (60 ml)
Ofloxacine 100 mg & Omindazole 125 mg
Acoba Syp.
Methylocobalamine, Lycopene, Multivitamine Multimineral & Antioxident
NOKSIRA Pharma Pvt.Ltd.
A Division of AriskonPharma

साहित्यिक विरासत सहेजने की पहल

अनंत विजय

हिंदी की विपुल साहित्यिक विरासत पर अगर नजर डालें, तो इस वक्त उसको संरक्षित करने की बेहद आवश्यकता दिखाई देती है. संरक्षण के साथ-साथ जरूरत इस बात की भी है कि हिंदी साहित्य को समृद्ध करने वाली रचनाओं को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम भी किया जाए. आज पूरे देश में हिंदी के पक्ष-विपक्ष में बयानबाजी हो रही है. लेकिन अगर हिंदी के लिए कुछ ठोस करना है, तो उसकी विरासत को समकालीन बनाने का यत्न किया जाना बेहद जरूरी है. हिंदी के व्याकरण को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, हिंदी में शब्दों की युग्म-रचना को लेकर भी बहसें होती रहती हैं. इन सारे प्रश्नों का जिस किताब में उत्तर है, वो पुस्तक अब लगभग अप्राप्य है. पंडित किशोरीदास वाजपेयी की किताब 'हिन्दी शब्दानुशासन' अहम है, लेकिन वो अब मिलती नहीं है. अगर बहुत जतन के बाद आप इस पुस्तक तक पहुंच भी गए, तो इसकी छपाई के अक्षर काफी पुराने हैं, लिहाजा आपको पढ़ने में कठिनाई होगी. नागरी प्रचारिणी सभा वाराणसी से प्रकाशित इस पुस्तक के पुनर्प्रकाशन और पाठकों तक इसकी जानकारी पहुंचाने की कोशिश की जानी चाहिए. इसी तरह से अगर आप हमारे वेदों को देखें, तो वो उपलब्ध तो हैं लेकिन उनको समकालीन बनाने की आवश्यकता है. प्रस्तुतिकरण में समकालीन, छपाई में बेहतर अक्षरों का प्रयोग और इन सबसे अलग जो हिंदी में इसका अनुवाद छपा है, उसको फिर से देखकर आज के जमाने की हिंदी के अनुसार करना होगा, ताकि हमारी आज की युवा पीढ़ी उसको पढ़ समझ सके.

इसी तरह से अगर हम विचार करें, तो हमारे कई ऐसे कवि-लेखक हैं जिनके बारे में, जिनकी रचनाओं के बारे में युवा पीढ़ी को बताने के लिए काम करना होगा. अपनी परंपरा और विरासत को सहेजकर ही उसकी मजबूत जमीन पर बुलंद इमारत खड़ी की जा सकती है.

अभी हाल ही में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के सहयोग से अयोध्या में जगन्नाथदास रत्नाकर पर दो दिन की राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई. इस गोष्ठी में जगन्नाथदास रत्नाकर और हिंदी साहित्य में उनके योगदान पर गहन चर्चा हुई. जगन्नाथदास रत्नाकर को ज्यादातर लोग रीतिकालीन कवि और उद्धव शतक के रचयिता के तौर पर जानते हैं, परंतु उनका रचना संसार काफी व्यापक है. कहा जाता है कि उन्होंने जयपुर राजघराने से लेकर बिहारी सतसई का भाष्य प्रस्तुत किया. कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सूर सागर के संपादन और संकलन का बड़ा हिस्सा उन्होंने ही किया था. उद्धव शतक के रचयिता कविवर जगन्नाथदास रत्नाकर की कर्मभूमि अयोध्या है. वो करीब तीन दशकों तक अयोध्या में रहे और वहीं रहकर उन्होंने उद्धव शतक, गंगालहरी, गंगावतरण, बिहारी सतसई की टीका जैसे कई महत्त्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की. अच्छी बात यह रही कि इस गोष्ठी में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने रत्नाकर के बिखरे साहित्य को सहेजने एवं पुनर्प्रकाशन का ऐलान किया. जगन्नाथदास रत्नाकर के बारे में यह तथ्य अभी तक सामने है कि वो आजादी पूर्व 1902 में अयोध्या के राजा के निजी सचिव होकर आए थे और वहां रहते हुए उन्होंने साहित्य के लिए बेहद अहम कार्य किया. उनकी रचनाएं काल की सीमाओं को तोड़ते हुए आज भी अपने बूते पर जिंदा हैं. जरूरत उसको विशाल हिंदी पाठक वर्ग तक पहुंचाने की है.

हिंदी में लंबे समय तक परंपरा को तोड़ने-फोड़ने का काम किया गया और इस तोड़ फोड़ का नुकसान ये हुआ कि हम अपनी विरासत से दूर होते चले गए. अपरंपरा का शोर मचाने वाले तो समय के साथ साहित्य में हाशिए पर चले गए, लेकिन जब तक शोर मचाते रहे तब तक साहित्य का बहुत नुकसान कर दिया. कुछ कवियों को आगे बढ़ा दिया, तो कुछ के विचारों में कमजोरी पकड़कर उसके बरअक्श किसी और कवि को खड़ा करने की कोशिश की गई. मिसाल के तौर पर, जिस तरह से आलोचकों में गोस्वामी तुलसीदास और कबीर को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ दिखाई देती है, उसको देखा जा सकता है.

टी एस इलियट ने कहा था- ऐतिहासिक बोध उन कवियों के लिए, जो अपनी उम्र के पच्चीस वर्ष बाद भी कवि बने रहना चाहते हैं, लगभग अनिवार्य है. इस ऐतिहासिक बोध का मतलब है एक परप्रेक्ष्य, जो अतीत की अतीतता से नहीं, उसकी वर्तमानता से भी संबद्ध हो. ऐतिहासिक बोध व्यक्ति को इसके लिए बाध्य करता है कि वो अपनी अस्थियों में सिर्फ अपनी पीढ़ी को लेकर ही ना लिखें, बल्कि इस अनुभूति के साथ लिखें कि होमर से लेकर आज तक के यूरोप का संपूर्ण साहित्य उसमें अंतर्निहित है. इसमें उसके अपने देश के साहित्य का समांतर अस्तित्व होगा और वो समांतर क्रम में ही रचना करेगा. कवि जगन्नाथदास रत्नाकर में ये गुण हैं.

हिंदी में लंबे समय तक परंपरा को तोड़ने-फोड़ने का काम किया गया और इस तोड़ फोड़ का नुकसान ये हुआ कि हम अपनी विरासत से दूर होते चले गए. अपरंपरा का शोर मचाने वाले तो समय के साथ साहित्य में हाशिए पर चले गए, लेकिन जब तक शोर मचाते रहे तब तक साहित्य का बहुत नुकसान कर दिया. कुछ कवियों को आगे बढ़ा दिया, तो कुछ के विचारों में कमजोरी पकड़कर उसके बरअक्श किसी और कवि को खड़ा करने की कोशिश की गई. मिसाल के तौर पर, जिस तरह से आलोचकों में गोस्वामी तुलसीदास और कबीर को श्रेष्ठ साबित करने की होड़ दिखाई देती है, उसको देखा जा सकता है. कबीर को क्रांतिकारी और तुलसी को रूढ़िवादी करार देकर सालों तक तुलसी के कवि रूप पर विचार नहीं किया गया या कह सकते हैं कि तुलसी को सायास हाशिए पर डालने की कोशिश की गई. तुलसी को वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थक और कबीर को रूढ़ियों पर प्रहार करने वाला रचनाकार बताया जाता रहा. यह तो तुलसी के कवित्व की ताकत थी, जिसके बूते पर वो पाठकों के मानस पर पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहे. सवाल तो उसपर भी खड़े होने चाहिए कि कविता की कसौटी कवि का विचार होना चाहिए या उसकी विचारधारा? हमारा तो मानना है कि कविता को कविता की प्रचलित कसौटी पर ही कसा जाना चाहिए. कविता को विचार और विचारधारा की कसौटी पर कसना कवि के साथ अन्याय करने जैसा है. हिंदी में विचारधारा के आलोचकों ने जब कवियों का विचार और धारा के आधार पर मूल्यांकन शुरू किया, तो इस तरह की गड़बड़ियां होने लगीं. जगन्नाथदास रत्नाकर से लेकर अन्य रीतिकालीन और भक्तिकालीन कवि हाशिए पर धकेले जाने लगे. अब वक्त आ गया है कि एक बार फिर से हम अपने पूर्ववर्ती रचनाकारों पर गंभीरता से बगैर किसी वैचारिक पूर्वाग्रह के विचार करें और मूल्यांकन का आधार साहित्यिक हो. सरकारें भी हिंदी का बहुत शोर मचा रही हैं, लेकिन अगर वो सचमुच हिंदी को लेकर गंभीर हैं, तो उनको प्रतीकात्मकता छोड़कर ठोस कार्य प्रारंभ करना होगा. केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अलावा भी भारत सरकार के कई संस्थान हैं, जो इस तरह के काम को अपने हाथ में ले सकते हैं. कई संस्थाएं तो पुरानी कृतियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हैं. इन बिखरी हुई संस्थाओं को साथ आकर गंभीरता से लोगों को चिन्हित कर इस काम को करवाना होगा.■

anant.ibn@gmail.com

आरटीआई: सौ समस्याओं का एक समाधान

आप चाहे शहर में रहते हों या गांव में, सरकारी बाबुओं द्वारा फाइल दबाने और फाइल आगे बढ़ाने के लिए रिश्वत की मांग से आप सभी का सामना ज़रूर हुआ होगा. गांवों में वृद्धावस्था पेंशन के लिए बुजुर्गों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है. शहरों में भी लोगों को आयु, जन्म-मृत्यु एवं आवास प्रमाणपत्र बनवाने या इनकम टैक्स रिफंड लेने के लिए नाको चने चबाने पड़ते हैं, साथ ही रिश्वत भी देनी पड़ती है. अब सवाल यह है कि जो आदमी रिश्वत देने की स्थिति में नहीं है, तो क्या उसका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है, काम ज़रूर होगा, वह भी बिना रिश्वत दिए.

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

ज़रूरत है, सिर्फ अपने अधिकार का इस्तेमाल करने की और वह अधिकार है, सूचना का अधिकार. यह अधिकार एक क़ानून है. महज़ एक आवेदन देकर आप रिश्वतख़ोर अधिकारियों की नींद हराम कर सकते हैं. जैसे ही आप अपने रुके हुए काम से संबंधित एक आरटीआई आवेदन डालते हैं, भ्रष्ट एवं रिश्वतख़ोर अधिकारियों और बाबुओं की समझ में आ जाता है कि वे जिसे परेशान कर रहे हैं, वह आम आदमी तो है, लेकिन अपने अधिकारों और नियमों के प्रति जागरूक है. कोई समस्या हो, कोई सुझाव चाहिए या आप अपने अनुभव हमसे बांटना चाहें, तो हमें पत्र लिखें या ई-मेल करें. हम आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हैं.■

किसी सरकारी विभाग में रुके हुए कार्य के विषय में सूचना के लिए आवेदन

(राशनकार्ड, पासपोर्ट, वृद्धावस्था पेंशन, आयु-जन्म-मृत्यु-आवास आदि प्रमाण पत्र बनवाने या इनकम टैक्स रिफण्ड मिलने में देरी होने, रिश्वत मांगने या बिना वजह परेशान करने की स्थिति में निम्न प्रश्नों के आधार पर सूचना के अधिकार का आवेदन तैयार करें)

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

मैंने आपके विभाग में ..... तारीख को ..... के लिए आवेदन किया था. (आवेदन की प्रति संलग्न है) लेकिन अब तक मेरे आवेदन पर सन्तोषजनक कदम नहीं उठाया गया है.

कृपया इसके सन्दर्भ में निम्नलिखित सूचना उपलब्ध कराएं.

1. मेरे आवेदन पर की गई प्रतिदिन की कार्रवाई अर्थात दैनिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. मेरा आवेदन किन-किन अधिकारियों के पास गया तथा किस अधिकारी के पास कितने दिनों तक रहा और इस दौरान उन अधिकारियों ने उसपर क्या कार्रवाई की? पूरा विवरण उपलब्ध कराएं.

2. विभाग के नियम के अनुसार मेरे आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी हो जानी चाहिए थी? क्या मेरे मामले में उपरोक्त समय-सीमा का पालन किया गया है?

3. कृपया उन अधिकारियों के नाम तथा पद बताएं जिन्हें मेरे आवेदन पर कार्रवाई करनी थी? लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की.

4. अपना काम ठीक से न करने और जनता को परेशान करने वाले इन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? यह कार्रवाई कब तक की जाएगी?

5. अब मेरा काम कब तक पूरा होगा?

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपए अलग से जमा कर रहा /रही हूं.
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं.....है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो, तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं.

भवदीय
नाम:
पता:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

अगर आपके पास आरटीआई से सम्बंधित कोई ख़बर या सवाल है तो हमें इमेल करें:
rti@chauthiduniya.com

जन्मांक के हिसाब से इस सप्ताह आपका भविष्यफल

क्या कहता है आपका टैरो कार्ड

अलंकृता मानवी

लेखिका मशहूर टैरो कार्ड रीडर हैं. आप भी अगर टैरो कार्ड के ज़रिए अपना भविष्य जानना चाहते हैं, तो उनसे संपर्क करें- 9999182127

जन्मांक 1: (जिनका जन्म 1, 19, 28 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह सूर्य है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, धकनी वज्र. इस हफ्ते आप अपने जीवन में कई सारे नए अनुभव हासिल करेंगे. यह सप्ताह आपके लिए मजेदार रहेगा. हॉलीडे ट्रीप, संगीत आदि का मजा ले सकेंगे. इस सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रंग है लाल.

जन्मांक 2: (जिनका जन्म 2, 11, 20, 29 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह चन्द्रमा है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, डेथ कार्ड. इस सप्ताह आप महत्वपूर्ण बदलाव देखेंगे. आपके आवास या कार्य स्थल में बदलाव आ सकता है. ये बदलाव बेहतरी के लिए होगा. आपके लिए शुभ रंग है सफेद.

जन्मांक 3: (जिनका जन्म 3, 12, 21, 30 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वृहस्पति है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, थ्री ऑफ डबल वज्र. इस हफ्ते आप कोई भी निर्णय अपने किसी वरिष्ठ या गुरु की सलाह से ही लें. कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सलाह जरूर ले. आपके लिए शुभ रंग है नीला.

जन्मांक 4: (जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह है यूरेनस यानी अरुण ग्रह)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, फर्स्ट सेरमन. ये कार्ड बताता है कि इस सप्ताह आप कुछ नया सीखेंगे या किसी को नया पढ़ाएंगे. यानि, आपको किसी नए अनुभव का एहसास होगा, आपके लिए शुभ रंग है हरा.

जन्मांक 5: (जिनका जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह बुध है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, सिक्स ऑफ ज्वेल्स. इस सप्ताह आपको उदारता दिखाने की जरूरत है. कुछ दान-पुण्य करें. इस सप्ताह आपका लक फैक्टर आपके साथ होगा. आपके लिए शुभ रंग है पर्पल.

जन्मांक 6: (जिनका जन्म 6, 15, 24 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शुक्र है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, द फूल कार्ड. इस सप्ताह आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें, अगर लें भी तो काफी सावधानी से, अन्यथा नतीजा उल्टा हो सकता है. आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी.

जन्मांक 7: (जिनका जन्म 7, 16, 25 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह वरुण है).

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, फाइव ऑफ वज्रा. ये कार्ड बताता है कि इस समाह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना है. सावधानी बरतें. स्वास्थ्य जांच करवा लें. आपके लिए शुभ रंग है, इंडिगो.

जन्मांक 8: (जिनका जन्म 8, 17, 26 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह शनि है).

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, एस ऑफ लोटसेज. ये एक विश कार्ड है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी. नई सफलताएं मिलेंगी. आपके लिए शुभ रंग है काला.

जन्मांक 9: (जिनका जन्म 9, 18, 27 तारीख को हुआ है. इस जन्मांक का स्वामी ग्रह मंगल है)

इस सप्ताह के लिए आपका कार्ड है, एट ऑफ लोटसेज. इस सप्ताह थोड़ी नकारात्मकता रहेगी. नकारात्मक विचार और व्यक्ति से दूर रहें. कुछ दान-पुण्य करें. आपके लिए शुभ रंग है नारंगी.

सेलेब्रिटी टैरो कार्ड

अर्जुन कपूर

इनका कार्ड है फोर ऑफ ज्वेल्स. इसके मुताबिक, इनकी प्रतिभा का प्रदर्शन अब तक ठीक से नहीं हुआ है.

श्रद्धा कपूर

इनका कार्ड है, टू ऑफ ज्वेल्स. इस फिल्म मे इनकी प्रतिभा निखर कर सामने आएगी.

हाफ गर्ल फ्रेंड

इस फिल्म का कार्ड है मदर कार्ड. कुल मिला कर ये फिल्म ठीक-ठाक प्रदर्शन करेगी, लेकिन ब्लॉकबस्टर साबित नहीं होगी.

सुखदेव
स्वतंत्रता संग्राम में क्रांति के अग्रदूत

साथियों के नाम सुखदेव का अंतिम पत्र

7 अक्टूबर-1930 को जब सुखदेव को उनके साथियों के साथ फांसी की सजा सुनाई गई, उसी दिन उन्होंने एच.एस.आर.ए. के अपने साथियों को ये पत्र लिखा था- लाला जी (लाला लाजपत राय) पर किए गए लाठियों के प्रहार ने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी थी. हमारे लिए यह जनता को अपनी विचारधारा से अवगत करने का अच्छा अवसर था. अत: हमने सौन्डर्स की हत्या की योजना बनाई. हम लोगों को यह बताना चाहते थे कि यह एक राजनीतिक हत्या है, जिसे करने वाले क्रांतिकारी हैं. हमने हमेशा जनता की तकलीफों के विरोध में ही प्रतिक्रिया की है. हम जनता में क्रांतिकारी आदर्शों को बढ़ावा देना चाहते थे और इस तरह के आदर्शों की अभिव्यक्ति उस व्यक्ति के मुख से और भी अधिक गौरवान्वित प्रतीत होती है, जो स्वयं इन आदर्शों के लिए ही मृत्यु के द्धार पर खड़ा हो.■

जन्मदिन पर विशेष

जन्मदिन- 15 मई 1907
पुण्यतिथि- 23 मार्च 1931

चौथी दुनिया ब्यूरो

लाहौर षडयंत्र केस के ऐतिहासिक निर्णय में जज ने लिखा था, 'सुखदेव को इस षडयंत्र का मस्तिष्क कहा जा सकता है, जबकि भगत सिंह उसके दाहीने हाथ हैं.' इस केस की जांच कर रहे तत्कालीन एस.एस.पी. हेमिल्टन हार्डिंग ने एफ.आई.आर. में पच्चीस दोषियों में से सुखदेव को प्रथम ओरापी बनाया था, जबकि भगत सिंह बारहवें और राजगुरु बीसवे आरोपी थे. इससे समझा जा सकता है कि सुखदेव कितने बड़े क्रांतिकारी थे. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों का नेतृत्व एक संगठनात्मक आंदोलन का रूप ले सका, इसका श्रेय सुखदेव को भी जाता है. सुखदेव के साथी और लाहौर षडयंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले शिव वर्मा ने एक बार कहा था, 'वास्तव में भगत सिंह पंजाब पार्टी के राजनीतिक परामर्शदाता थे, जबकि सुखदेव उसके संगठक थे. सुखदेव वे व्यक्ति थे, जिन्होंने संगठन की नींव का एक-एक पत्थर रखा.' सुखदेव के बारे में कहा जाता है कि अपनी सहनशक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से उन्होंने एक बार अपने बांयें हाथ पर बने ओम के निशान को हटाने के लिए पहले उस पर नाइट्रिक एसिड डाला और फिर उसे मोमबत्ती से जला लिया.

15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना में मां श्रीमती रल्ली देवी और पिता श्री राम लाल थापर जी के घर सुखदेव का जन्म हुआ. बचपन में ही सुखदेव के सर से पिता का साया उठ गया. इसके बाद ताऊ लाला अचिन्त राम ने इनका लालन-पालन किया. सुखदेव के भीतर बचपन में ही सेवा, त्याग और राष्ट्रप्रेम की भावना जागृत हो गई थी. वे दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और अछूत कहे जाने वाले बच्चों को पढ़ाते भी थे. सुखदेव के भीतर एक क्रांतिकारी का भाव तब उत्पन्न हुआ, जब 12 साल की उम्र में उन्होंने जलियांवाला बाग़ नरसंहार के बारे में सुना. उनके इस क्रांति के भाव को दिशा देने का काम किया उनके अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार ने. सुखदेव जब लायलपुर के सनातन धर्म हाईस्कूल से मैट्रिक पास कर लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया, तो यहीं पर उन्हें इतिहास के अध्यापक जयचंद्र विद्यालंकार का सान्निध्य मिला. इस कॉलेज में ही सुखदेव की मुलाकात भगत सिंह से हुई. इस विधालय के प्रबंधक भाई परमानंद भी जाने-माने क्रांतिकारी थे. यहीं पर सुखदेव और भगत सिंह के मन में व्यवस्थित क्रांति का बीज पड़ा. लाहौर में ही 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन किया गया, जिसके मुख्य संयोजक सुखदेव ही थे. इस संगठन में उनके साथ भगत सिंह, यशपाल, भगवती चरण, भगवती चन्द्र वोहरा, कॉमरेड राम चन्द्र और जयचंद्र विद्यालंकार जैसे क्रांतिकारी भी थे.

सुखदेव हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन (एच.आर.ए.) नामक क्रांतिकारी सभा के प्रमुख सदस्य थे. सितंबर 1928 में इस दल के कुछ सदस्यों ने उत्तर भारत के अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा की और आजादी की लड़ाई और भी धार देने के लिए एक नया संगठन गठित हुआ, जिसका नाम दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (एच.एस.आर.ए.). भगत सिंह इस संगठन के राजनीतिक नेता थे और सुखदेव संगठनकर्ता. सुखदेव को पंजाब के संगठन का उत्तरदायित्व दिया गया. इस संगठन के माध्यम से युवा क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ सरकार के खिलाफ अलख जगाना शुरू किया. इसी बीच साइमन कमीशन का विरोध करने पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय का देहांत हो गया. सुखदेव और भगत सिंह ने इसका बदला लेने की ठानी.

19 दिसंबर 1928 को सुखदेव भगत सिंह और राजगुरु ने ब्रिटिश पुलिस ऑफीसर जेपी सौंडर्स की हत्या कर दी. इसके बाद इन्होंने केंद्रीय एसेंबली में बम फेंकने का फैसला लिया. इस सारी योजना के सूत्रधार सुखदेव ही थे. सुखदेव के कारण ही भगत सिंह को केन्द्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए चुना गया था, क्योंकि सुखदेव का मानना था कि भगत सिंह द्वारा ऐसा करने पर पूरे देश में क्रांति का संदेश जाएगा. लाहौर षडयंत्र केस में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले शिव वर्मा के अनुसार, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन (एच.एस.आर.ए.) की केन्द्रीय कमेटी ने फसला लिया था कि केन्द्रीय विधानसभा में बम फेंकने के लिए भगत को नहीं भेजा जाएगा. उस बैठक में सुखदेव उपस्थित नहीं थे. इस फैसले के तीन दिन बाद जब वे वापस आए, तो उन्होंने इस निर्णय का अत्यधिक विरोध किया. उनका मानना था कि एच.एस.आर.ए. की सोच और उद्देश्य को भगत सिंह से बेहतर कोई नहीं समझा सकता. सुखदेव ने तो इसके लिए भगत सिंह को भी धिक्कारा था कि आखिर उन्होंने ये फैसला मान कैसे लिया. अंतत: कमेटी ने अपना निर्णय बदलकर भगत सिंह को बम फेंकने के लिए चुना. लेकिन अपने प्रिय मित्र को इस तरह बलिदान के रास्ते पर आगे करने के फैसले से सुखदेव मन ही मन बहुत दुखी थे. दुर्गा भाभी जी के अनुसार, अगले दिन जब वे लाहौर पहुंचे तब उनकी आंखें सूजी हुई थीं, क्योंकि वे अपने निर्णय पर पूरी रात रोते रहे थे.

8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की घटना के बाद चारो तरफ क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियों का दौर शुरू हुआ. इसी दौरान लाहौर में बम बनाने की एक फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसमें अन्य क्रांतिकारियों के साथ सुखदेव भी गिरफ्तार हुए. केंद्रीय विधानसभा में भले ही भगत सिंह और राजगुरु ने बम फेंका हो, लेकिन इसके सुत्रधार सुखदेव ही थे. ये बात लाहौर षडयंत्र केस के इस शीर्षक से साबित होती है- 'खप ींहश लॅींीं ष ढहश डरहीश उेपीळीरलू उरीश ढीळर्लीपरश्र, डरहीश, लेपींींळींींशिव ींपवशी जीवळपरपलश पे खखख ष 1930: ढहश उीप ह्र उेश्रिरळपरपीं ींशीींी डींज़हवर्शी रपव ींहशीी. ' अंतत: 7 अक्टूबर 1930 को इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई और 23 मार्च 1931 को मात्र 24 साल की उम्र ये महान क्रांतिकारी अपने साथियों भगत सिंह और राज-गुरु के साथ हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गया. सुखदेव का जीवन हमारे लिए सदा ही प्रेरणा का स्त्रोत रहेगा. लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत की आजादी के लिए खुद को कुर्बान करने वाले इस क्रांतिकारी का एक राष्ट्रीय स्मारक भी देश में नहीं है.

नाइंसाफी के सवाल पर गांधी जी को सुखदेव का पत्र

क्रांतिकारी बंदियों के साथ नाइंसाफी के सवाल पर सुखदेव ने जेल में रहते हुए महात्मा गांधी को एक पत्र लिखा था. गांधी जी ने इस पत्र को उनके बलिदान के एक माह बाद 23 अप्रैल, 1931 को यंग इंडिया में छापा. सुखदेव ने लिखा था, 'आपने अपने समझौते के बाद अपना आंदोलन (सविनय अवज्ञा आंदोलन) वापस ले लिया है और फलस्वरूप आपके सभी बंदियों को रिहा कर दिया गया है, पर क्रांतिकारी बंदियों का क्या हुआ? 1915 से जेलों में बंद गदर पार्टी के दर्जनों क्रांतिकारी अब तक वहीं सड़ रहे हैं. बावजूद इस बात के कि वे अपनी सजा पूरी कर चुके हैं. मार्शल लॉ के तहत बन्दी बनाए गए अनेक लोग अब तक जीवित दफनाए गए से पड़े हैं. बब्बर अकालियों का भी यही हाल है. देवगढ़, काकोरी, महुआ बाज़ार और लाहौर षड्यंत्र केस के बंदी भी अन्य बंदियों के साथ जेलों में बंद हैं. एक दर्जन से अधिक बंदी सचमुच फांसी के फंदों के इंतजार में हैं. इन सबके बारे में क्या हुआ?' ■

feedback@chauthiduniya.com

जल संग्राम

जल है तो कल है. कल की बात बाद में. देखना ये है कि आज जल की स्थिति क्या है. पीने का पानी, कृषि में लगने वाला पानी, पानी की औद्योगिक खपत, जल प्रदूषण, जल संरक्षण. ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज विचार नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर जल की कमी हमारे कल का सबसे बड़ा काल बन जाएगी. फिर, तीसरे विश्व युद्ध की कौन कहे, हम गृह युद्ध तक से नहीं बच पाएंगे. गर्मी के मौसम में जल का संकट और बढ़ जाता है. ऐसे में चौथी दुनिया ने अपने पाठकों तक जल की दुनिया से रूबरू कराने का फैसला किया है. जल संग्राम नाम से हम प्रत्येक सप्ताह जल से जुड़े विभिन्न मुद्दों को आपके सामने लाएंगे. अगर आप भी अपने विचार या अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है.

नई तकनीक

कार्बन फुटप्रिंट की तरह वाटर फुटप्रिंट भी महत्वपूर्ण है

सबसे पहला सवाल ये है कि ये वाटर फुटप्रिंट है क्या? हमारे प्रतिदिन के बहुत से उत्पादों में आभासी या छुपा जल शामिल होता है. उदाहरण के लिए, एक कप कॉफी के उत्पादन के लिए आभासी पानी की मात्रा 140 लीटर तक होती है. आपका वाटर फुटप्रिंट केवल आपके द्वारा प्रयोग किए गए प्रत्यक्ष पानी (उदाहरण के लिए, धुलाई में) को ही नहीं दिखाता, बल्कि आपके द्वारा उपभोग किए गए आभासी पानी की मात्रा को भी दर्शाता है. पीने, खाना पकाने और कपड़े धोने के लिए लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इससे अधिक पानी का इस्तेमाल अनाज उपजाने, कपड़ा बनाने, कार बनाने और कम्प्यूटर बनाने में होता है. वाटर फुटप्रिंट ऐसे ही हर एक उत्पाद और सेवा, जिसका हम उपभोग करते हैं, उसमें इस्तेमाल किए गए पानी की गणना करता है. वाटर फुटप्रिंट हमारे

सामने कई सारे सवाल उठाता है. जैसे, किसी कंपनी में इस्तेमल किए जाने वाले पानी का स्त्रोत क्या है? इन जल स्त्रोतों की रक्षा के लिए क्या उपाय है? वाटर फुटप्रिंट के तीन घटक हैं. ग्रीन, ब्लू और ग्रे. एक साथ मिल कर ये घटक पानी के इस्तेमाल की असल तस्वीर दिखाते हैं. मसलन, इस्तेमाल किया गया पानी बारिश का पानी है, सतह का पानी है या भू-जल है. वाटर फुटप्रिंट किसी प्रक्रिया, कंपनी या क्षेत्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पानी की खपत और जल प्रदूषण को बताता है. ग्रीन वाटर फुटप्रिंट मिट्टी की परत में छुपा पानी है, जिसका इस्तेमाल कृषि, हॉर्टीकल्चर या जंगल द्वारा होता है. ब्लू वाटर फुटप्रिंट ग्राउंड वाटर है, जिसका इस्तेमाल कृषि, उद्योग और घरेलू काम में होता है. ग्रे वाटर फुटप्रिंट ताजा जल (फ्रेश वाटर) की वह मात्रा है, जिसमें प्रदूषक हटा कर जल की गुणवत्ता को सुनिश्चित किया जाता है. वाटर फुटप्रिंट का संबंध फ्रेश वाटर (ताजा जल) पर मानवीय प्रभाव और मानवीय इस्तेमाल से है. फुटप्रिंट के जरिए पानी की कमी और जल प्रदूषण जैसे मुद्दे को भी समझा जा सकता है.■

जल संरक्षण

विदर्भ और बुन्देलखंड का समाधान देवास है

स्वर्गीय अनुपम मिश्रा ने अपनी किताब आज भी खरे हैं तालाब में लिखा है, इंदौर के पड़ोस में बसे देवास शहर का किस्सा तो और भी विचित्र है. पिछले 30 वर्ष में यहां के सभी छोटे-बड़े तालाब भर दिए गए और उन पर मकान और कारखाने खुल गए. लेकिन फिर पता चला कि इन्हें पानी देने का कोई स्रोत नहीं बचा है! शहर के खाली होने तक की खबरें छपने लगी थीं. शहर के लिए पानी जुटाना था, पर पानी कहां से लाएं? देवास के तालाबों, कुओं के बदले रेलवे स्टेशन पर दस दिन तक दिन-रात काम चलता रहा. 25 अप्रैल, 1990 को इंदौर से 50 टैंकर पानी लेकर रेलगाड़ी देवास आई. स्थानीय शासन मंत्री की उपस्थिति में ढोल नगाड़े बजाकर पानी की रेल का स्वागत हुआ. मंत्री जी ने रेलवे स्टेशन आई नर्मदा का पानी पीकर इस योजना का उद्घाटन किया. संकट के समय इससे पहले भी गुजरात और तमिलनाडु के कुछ शहरों में रेल से पानी पहुंचाया गया है. लेकिन देवास में तो अब हर सुबह पानी की रेल आती है, टैंकरों का पानी पंपों के सहारे टंकियों में चढ़ता है और तब शहर में बंटता है.

दूसरी तरफ, पानी की कमी की वजह से 90 के दशक में किसानों ने खेती कम की, जमीन बेचने का काम ज्यादा किया. नलकूपों को आधुनिक खेती के सबसे बेहतर विकल्प के रूप में प्रचारित किया गया, जो जल संकट का कारण बना. तब देवास के टोंकखुर्द तहसील के हरनावदा गांव के रघुनाथ सिंह तोमर ने अकेले ही दस फुट गहरा एक हेक्टेयर का तालाब, अपने खेत की सिंचाई के लिए बनाया. तालाब बनकर तैयार हो गया. 15 बीघा के खेत की सिंचाई होने लगी. रघुनाथ सिंह ने पूरे गांव के सामने एक नई मिसाल रख दी थी. साल 2005 में इस किसान के तालाब को देखकर जिले के दूसरे गांवों में भी लोगों ने तालाब बनाने शुरू किए.

इसी बीच, आईआईटी रूड़की से पासआउट उमाकांत उमराव 2006 में देवास का कलेक्टर बनकर आए. जिले में पानी की गंभीर स्थिति को देखते हुए, उन्होंने किसानों को अपने खेत के एक छोटे हिस्से में तालाब बनाने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने बैंक और सोसाइटी को राजी किया कि वे तालाब बनाने के लिए किसानों को लोन दें. उनके प्रयासों से गोरवा गांव के 150 से ज्यादा किसानों ने अपने खेत में तालाब बनाए. खेत में तालाब बनाने के काम को पानी की खेती का नाम दिया गया. आज, जिले में 10 हजार तालाब हैं. गोरवा, धतूरिया और चिड़ावद टोंकखुर्द के आसपास ऐसे कई गांव हैं, जो इस अभियान के प्रेरक बने. तीनों गांवों को जलसंवर्धन के लिए अलग-अलग वर्षों में राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है. इस सब का नतीजा ये निकला कि जिस देवास शहर का जलस्तर 300 फुट से भी नीचे चला गया था, वह अब 170 फुट पर आ गया है. आज देश दुनिया की कई संस्थाएं इन गांवों में घूमने आती हैं.■

जल संकट

58 फीसदी जलस्तर घटा: इस गर्मी में प्यास कैसे बुझेगी

अभी प्रचंड गर्मी ने दस्तक भी नहीं दी है, लेकिन देश के 91 प्रमुख जलाशयों का जल संग्रह उनकी क्षमता से बहुत कम हो गया है. दूसरी तरफ, मौसम विभाग ने भी सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है. अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा, तो इस बार मई-जून की गर्मी में उन क्षेत्र के लोगों की हालत क्या होगी, जहां जलस्तर पहले से ही काफी कम है. केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने देश के प्रमुख 91 जलाशयों में जल स्तर की ताजा रिपोर्ट जारी की है. इनमें फिलहाल 48.42 अरब घन मीटर जल का संग्रहण आंका गया है, जो छह माह

पहले यानि अक्टूबर के अंत में 115.457 अरब घन मीटर था.

मंत्रालय के अनुसार, गर्मी के दौरान हर साल जल संकट से जूझते देश के विभिन्न राज्यों व इलाकों के लोगो को राहत देने के लिए सरकार ने पहले से ऐसी चुनौतियों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए तैयार किए गए रोडमैप के तहत 1,600 करोड़ की योजना को शुरू कराने का दावा किया जा रहा है. लेकिन मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड से जिस तरह की खबरें आ रही हैं, वे चिंताजनक हैं. केंद्र सरकार के लिए बुंदेलखंड और मराठावाड़ा प्राथमिकता पर हैं, जहां पिछले साल भारी जल संकट का सामना करना पड़ा था. केंद्रीय जल आयोग के अनुसार, देश में हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में जल स्तर में तेज गिरावट देखी जा रही है.■

जब इरफ़ान ने सोनू निगम से पूछा एक सवाल

सिंगर सोनू निगम ने कुछ समय पहले ट्विट के जरिए धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का विरोध किया था,जिसे लेकर काफी विवाद की स्थिति पैदा हो गई थी. अब इस मामले को लेकर एक्टर इरफ़ान ने भी कई अहम सवाल उठाए हैं.

फिल्म *हिंदी मीडियम* के प्रमोशन के दौरान बातचीत करते हुए इरफ़ान ने सोनू निगम द्वारा किए गए ट्विट को लेकर उन पर ही कई सवाल दागे हैं. इरफ़ान ने पूछा कि, विदेशों में गाड़ी के हॉर्न पर पाबंदी है क्योंकि वह इस बात को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं, लेकिन क्या भारत में यह संभव है? आगे इरफ़ान कहते हैं, जब एक अस्पताल के बगल में डिस्कोथेक चलता है, तब लोग उसपर सवाल क्यों नहीं उठाते? हमें सभी तरह के ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए. हमें यह भी सोचना चाहिए कि क्या सिर्फ एक ही आदमी को साउंड से समस्या है? आपको बता दें कि, सोनू ने ट्विट करके धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकरों का विरोध किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ फ़तवा जारी किया गया था कि उनके सिर का मुंडन करवाने वाले को दस लाख रुपए ईनाम दिया जाएगा. इसके बाद सोनू ने खुद अपना मुंडन भी करा लिया था.

> मुझे फिल्म का टाइटल हाफ गर्लफ्रेंड बड़ा पसंद है, दोस्त से ज्यादा लेकिन प्यार से कम. मेरे किरदार का अर्जुन के किरदार से कुछ ऐसा ही रिश्ता है. आशा करती हूं आप-सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी.

क्यों नर्वस हैं श्रद्धा कपूर!

श्रद्धा ने अपने करियर में आशिकी-2, एक विलेन, बागी, हैदर, एबीसीडी-2 जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसकी बदौलत वह आज टॉप की अभिनेत्रियों में शामिल हैं. अपने करियर में इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद श्रद्धा कपूर की रातों की नींद उड़ी हुई है. वे बेहद नर्वस हैं और प्रेशर भी महसूस कर रही हैं.

प्रतीश कुमार

आशिकी-2 से बॉलीवुड में ख़ास जगह बनाने वाली श्रद्धा कपूर का करियर इन दिनों बुलंदियों पर है. हालांकि श्रद्धा की शुरुआती पारी कोई ख़ास नहीं रही थी लेकिन साल 2013 में आई उनकी फिल्म आशिकी-2 ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज की तारीख में श्रद्धा कपूर के करोड़ों फैंस हैं.

श्रद्धा ने अपने करियर में आशिकी-2, एक विलेन, बागी, हैदर, एबीसीडी-2 जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसकी बदौलत वे आज टॉप की अभिनेत्रियों में शामिल हैं. अपने करियर में इतनी हिट फिल्में देने के बावजूद श्रद्धा कपूर की रातों की नींद उड़ी हुई है. इन दिनों वे बेहद नर्वस हैं और प्रेशर भी महसूस कर रही हैं.

अब आप सोच रहे होंगे यह तो प्यार-मोहब्बत के लक्षण हैं और प्यार में ऐसा होना लाजिमी है. वैसे भी इन दिनों श्रद्धा की मोहब्बत में बॉलीवुड के दो दीवाने फरहान अख्तर और आदित्य रॉय कपूर कैद हैं. ख़ैर श्रद्धा की आंखों से गायब नींद की वजह प्यार, इश्क मोहब्बत नहीं है, बल्कि इसकी वजह उनकी अर्जुन कपूर के साथ रिलीज के लिए तैयार निर्देशक मोहित सूरी की फिल्म *हाफ गर्लफ्रेंड* का टाइटल रोल है.

जी हां, चौंक गए ना आप! श्रद्धा कहती हैं, पहली बार किसी फिल्म का टाइटल रोल निभा रही हूं. पहली बार किसी किताब के अडॉप्टेशन पर बनी फिल्म में काम कर रही हूं, इसलिए बहुत ज्यादा नर्वस हूं. मैं पिछले कई हफ्तों से ठीक से सो नहीं पा रही हूं. अपनी फिल्म *हाफ गर्लफ्रेंड* को लेकर बहुत प्रेशर महसूस कर रही हूं. यह डर, प्रेशर और नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि निर्देशक मोहित सूरी और किताब के लेखक चेतन भगत ने मुझ पर विश्वास कर यह टाइटल रोल मुझे दिया है. मैं आज तक कभी भी इतना प्रेशर और नर्वसनेस नहीं महसूस किया है, जितना इस फिल्म को लेकर हूं.

श्रद्धा ने आगे बताया कि, मुझे फिल्म का टाइटल हाफ गर्लफ्रेंड बड़ा पसंद है, दोस्त से ज्यादा लेकिन प्यार से कम. मेरे किरदार का अर्जुन के किरदार से भी कुछ ऐसा ही रिश्ता है. आशा करती हूं आप-सबकी उम्मीदों पर खरी उतरूंगी. हाफ गर्लफ्रेंड एक इंटेंस लव स्टोरी है. फिल्म के निर्देशक मोहित ऐसी ही फिल्मों के मास्टर हैं. श्रद्धा कपूर की आने वाली फिल्मों में *हाफ गर्लफ्रेंड* के अलावा *हसीना: द क्वीन ऑफ मुंबई* भी चर्चा में है. इस फिल्म में वे भारत के मोस्ट वांटेड दाउद इब्राहिम की बहन की भूमिका अदा करेंगी. बता दें कि श्रद्धा कपूर-अर्जुन कपूर अभिनीत यह फिल्म 19 मई को रिलीज होने वाली है.■

अर्जुन कपूर

बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जिनका कोई नाम नहीं होता. कभी-कभी अधूरेपन में ही कुछ चीजें पूरी हो जाती हैं. यह शब्द उन रिश्तों के लिए है जिनका कोई नाम नहीं. हाफ यानी आधा कभी बहुत अच्छा होता है तो आप कहते हैं, चलो इतना सा रिश्ता ही सही, यही काफी है. कभी कभी हाफ बुरा होता है. इस फिल्म में आपको हाफ के दोनों पहलू मिलेंगे.

मोहित सूरी

मुझे याद है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था. मैंने जब उस लड़की को बताया तो उसने कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. तब मैं सोचता था कि काश कोई मुझे समझे और 'हाफ गर्लफ्रेंड' बना दे. फिल्म का यह टाइटल उन लोगों की सोच को दर्शाता है जो लोग एक दूसरे को जानते हैं, पसंद करते हैं, पर रिश्ते को कमिट नहीं कर पाते हैं.'

feedback@chauthiduniya.com

ऋषि कपूर की नसीहत के बाद प्रेयर मीट में पहुंचे स्टार्स

नए स्टार्स को शर्म आनी चाहिए. उनमें से कुछ ही विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जबकि इनमें से कई ने उनके साथ काम किया था. इन्हें सम्मान करना सीखना चाहिए. उन्होंने यह भी लिखा था कि कई चमचे प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन विनोद खन्ना को अंतिम विदाई देने कुछ ही पहुंचे. मैं इनसे नाराज़ हूं. मैं जब भी मरूंगा तो मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो

विनोद खन्ना के अंतिम संस्कार से यंग स्टार्स के नदारद रहने पर ऋषि कपूर के ट्विट के बाद कई सितारे प्रेयर मीट में पहुंचे. प्रेयर मीट में शाहरुख, आमिर, ऋतिक शामिल हुए, लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान तीनों खान समेत कई युवा सितारे नदारद थे. तब नए स्टार्स पर ऋषि कपूर ख़ासे नाराज़ हुए थे. उन्होंने ट्विट किया था, नए स्टार्स को शर्म आनी चाहिए. उनमें से कुछ ही विनोद खन्ना को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जबकि इनमें से कई ने उनके साथ काम किया था. इन्हें सम्मान करना सीखना चाहिए. उन्होंने यह भी लिखा कि कई चमचे प्रियंका चोपड़ा की पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन विनोद खन्ना को अंतिम विदाई देने कुछ ही पहुंचे. मैं इनसे नाराज़ हूं. मैं जब भी मरूंगा तो मुझे मान लेना चाहिए कि मुझे कंधा देने वाला कोई नहीं होगा. ऋषि कपूर की इस नसीहत के बाद प्रेयर मीट में कई युवा सितारे पहुंचे. शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन अपनी बेटी श्वेता नंदा के साथ पहुंचे. बॉलीवुड स्टार्स में पत्नी किरण राव के साथ आमिर खान, ऋतिक रोशन, राकेश रोशन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, बोनी कपूर, श्रीदेवी, तब्बू, माधुरी दीक्षित, फरहान अख्तर, अरबाज खान, मलाइका अरोड़ा, कपिल देव, संजय खान, सुरेश ओबेरॉय समेत कई सितारे मौजूद रहे. ब्लैडर कैंसर से जूझ रहे विनोद खन्ना का 27 अप्रैल को निधन हो गया था. वे 144 फिल्मों में काम कर चुके थे. फिलहाल वे पंजाब के गुरदासपुर से भाजपा सांसद थे. अंतिम संस्कार के वक्त उनकी दोनों पत्नियां गीतांजलि और कविता भी मौजूद थीं.

हालांकि अंतिम संस्कार में सितारों के नहीं पहुंचने के बारे में जानकारी मिली कि उस समय ज्यादातर सितारे फिल्म की शूटिंग में बिजी थे. हालांकि प्रेयर मीट में सलमान कहीं नज़र नहीं आए. पता चला कि वे अबूधाबी के लिए रवाना हो गए थे. अक्षय कुमार भी उस दिन नेशनल अवॉर्ड लेने के लिए दिल्ली गए हुए थे. इसके बाद किए गए ट्विट में ऋषि कपूर ने प्रेयर मीट में युवा सितारों के पहुंचने की सराहना की.■

feedback@chauthiduniya.com

क्यों कहा आशा ने कि अच्छा ही हुआ कि मैंने दोबारा किसी बच्चे को गोद लेने की बात नहीं सोची.

हिट गर्ल: आशा पारेख

> दिलीप साहब के साथ काम न कर पाने का अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए आशा कहती हैं, मुझे दिलीप साहब बहुत अच्छे लगते थे. मेरा बड़ा मन था किसी फिल्म में उनके साथ काम करने का. वैसे हमारी एक फिल्म शुरू भी हुई थी लेकिन न जाने क्या हुआ कि वह फिल्म बीच में ही बंद हो गई और इसके बाद चाह कर भी मुझे दिलीप साहब के साथ दोबारा काम करने का कोई मौका नहीं मिला. मैं आज भी जाती रहती हूं दिलीप जी और सायरा जी से मिलने.

अपने जमाने की सुपरस्टार रहीं आशा पारेख इन दिनों ऑटोबायोग्राफी *द हिट गर्ल: आशा पारेख* को लेकर सुर्खियों में हैं. इसी दौरान आशा पारेख ने निजी जिंदगी से जुड़े कई सवालों के दिलचस्प जवाब दिए. आशा पारेख ने शादी नहीं की. वह शादी न कर पाने की वजह बताते हुए कहती हैं, *देखिए कौन ऐसे मां-बाप हैं जो अपने बच्चे की शादी नहीं करना चाहते हैं? मां ने मेरी शादी भी करनी चाही थी. कई रिश्ते देखे गए, बातचीत की लेकिन कोई बात नहीं बनी. शायद शादी-विवाह किस्मत की बात होती है और मेरी किस्मत में शादी नहीं लिखी थी इसलिए नहीं हुई. किस्मत के आगे कुछ भी नहीं हो सकता.*

आशा जी ने आगे एक बात और कही कि वे एक बच्चे को गोद लेने की कोशिश भी कर रही थीं, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी. वे आगे कहती हैं, वैसे मुझे बच्चे को गोद न ले पाने का कोई मलाल नहीं है. जब आज के बच्चों को देखती हूं कि वे अपने माता-पिता का ध्यान नहीं रखते हैं, तो सोचती हूं कि अच्छा ही हुआ कि मैंने दोबारा किसी बच्चे को गोद लेने की बात नहीं सोची.

वहीदा रहमान, हेलन, नंदा, साधना और सलीम खान परिवार के साथ अपनी दोस्ती पर आशा कहती हैं, जी हां हम सब एक लंबे अरसे से बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैं कई बार हेलन के घर खाना खाने जाती हूं, तो वे हमारे लिए अक्सर खाओसे (एक बर्मी डिश) बनाती हैं. हेलन के हाथों का बना खाना हम लोग बड़े चाव से खाते हैं. मैं, हेलन और वहीदा एक-दूसरे के घर में खाने पर जाते हैं. हम सब दोस्त मिलकर बाहर घूमने भी जाते हैं. जब मेरे यहां सब लोग आते हैं तो सभी चाट और पानी पूरी खाने की डिमांड करते हैं. हम सभी को पढ़ने का बहुत शौक है. हमलोग कहानियां और समाचार सब कुछ पढ़ते हैं. अब नंदा हमारे बीच नहीं हैं, हम लोग नंदा को बहुत मिस करते हैं. दिलीप साहब के साथ काम न कर पाने का अफ़सोस ज़ाहिर करते हुए आशा कहती हैं, मुझे दिलीप साहब बहुत अच्छे लगते थे. मेरा बड़ा मन था किसी फिल्म में उनके साथ काम करने का. वैसे हमारी एक फिल्म शुरू भी हुई थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि वह फिल्म बीच में ही बंद हो गई और इसके बाद चाह कर भी मुझे दिलीप साहब के साथ दोबारा काम करने का कोई मौका नहीं मिला. मैं आज भी जाती रहती हूं दिलीप जी और सायरा जी से मिलने.

ऑटोबायोग्राफी *द हिट गर्ल: आशा पारेख* की लॉन्चिंग के दौरान बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार्स ने भी शिरकत की जिनमें धर्मेंद्र, सलमान खान, जितेंद्र, हेलन, वहीदा रहमान, जैकी ऑफ और अरुणा ईरानी आदि शामिल थे.■